हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 जनवरी, 1975 (द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय–सूची

मंगलवार, 7 जनवरी, 1975 (द्वितीय बैठक)

पृश्ठ संख्या

राज्यपाल के अभिभाशण का चर्चा (पुनरारम्भ) तथा धन्यवाद

(6)1–73

प्रस्ताव पर मतदान

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 7 जनवरी 1975 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान–भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14–00 बजे हुई। अध्यक्ष (**चौधरी सरूप सिंह**) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

चौधरी ि ाव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): स्पीकर साहब, मैं कल इस बात की चर्चा कर रहा था कि बिजली की कमी के कारण प्रांत की पैदावार को बहुत धक्का लग रहा है। यह केवल खेती की पैदावार में ही नहीं हो रहा है बल्कि उद्योग भी बन्द पड़ते जा रहे हैं और वे पूरी पैदावार नहीं कर पा रहे हैं और उद्योगों में पैदा होने वाली चीजों में कम पैदावार होने की वजह से वे चीज़े महंगी होती जा रही है क्योंकि जब पैदावार कम होगी और उनकी मांग ज्यादा होगी तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही। इसलिए इसकी तरफ वि ोश ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कई सालों से लारे दिए जाते रहे है। उस तरह लारे देने से और केवल कागज़ों पर ही बातें रख कर काम नहीं चलेगा बल्कि हमें इसके लिए कोई

ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए आव यकता इस बात की है कि बिजली की पैदावार बढ़ाने की तरफ सबसे ज्यादा पहल दी जाए, चाहे कुछ भी ढंग अपनाने पड़ें। जब तक हमारे यहां बिजली की आगे पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक कोई भी हमारा काम चाहे खेती का है, चाहे उद्योग का है, आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैंने कल प ाुओं के बारे में भी कुछ चर्चा की थी कि जींद में प ा चारा संयंत्र लगा है। उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वैसे बाजार से वह चीजें लेकर अगर चारा बनाया जाए तो इससे वह वहां का बना चारा महंगा पड़ता है तो इसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस संयंत्र का चारा अगर बाजब कीमत पर मिलेगा तब ही लोग उसे खरीदेंगे, और लोगों को लाभ पहुंचेगा। इससे आगें मैं यह कहना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या बहुत गम्भीर है और 27 साल की आजादी के बाद भी हम इस समस्या को हल नहीं कर पाए हैं और हम इस काबिल नहीं हो सके कि लोगों को पीने का पानी दे सकें। केवल हर बार अपने भाशणों में लारे देने से और इस तरह की बातें करके लोगों को बहलाया जाता हैं इस तरह करने से कब तक काम चलेगा और कब ते लोगों को बहकाने रहेंगे। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि सबसे ज्यादा प्रायिरिटी पीने के पानी को दी जानी चाहिए और जिन गांवों में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है वहां इसका सबसे पहले प्रबन्ध किया जाए। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक तौर पर जो कमजोर लोग हैं और जो माली तौर पर पिछड़े हुए हैं उनके लिए

सरकार को वि ोश पग उठाने चाहिएं, केवल कुछ आंकड़े देकर किसी साल कुछ दे दिए और किसी साल कुछ दे दिए इससे हालत सुधरने वाली नहीं है। इस बारे में कम से कम तीन चीजों की तरफ वि ोश ध्यान दिया जाना चाहिए और ये तीन चीजें हैं ि ाक्षा, चिकित्सा और न्याय। ये तीनों चीजें हर व्यक्ति को सस्ती और समान रूप से उसके अधिकार के अनुसार मिलनी चाहिएं लेकिन इस वक्त ये तीनौं इतनी महंगी हैं कि गरीब आदमी के बस में नहीं है। केवल पैसे वाले और तगड़े लोग इन बातों में आगे बढ़ते हैं और कमजोर वर्ग के लोग पीछे रह जाते हैं।

स्पीकर साहब, ि ाक्षा के बारे में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सबको मिलने की बात तो पीछे रह गई यह यकसां भी नहीं की गई है। अमीरों के बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीबों के लिए वही पुराने ढर्रे के प्राइमरी स्कूल गांव में हैं, जिनका कोई भी स्डैण्डर्ड नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह सरकार का काम है कि वह ि ाक्षा को सब के लिए यकसां और एक स्तर की बनाए या तो सारे ही स्कूल पब्लिक स्कूलों के स्टैण्डर्ड के हों या फिर सारे स्कूल ऐसे हों, जैसे गांव में हैं तब ही कहा जा सकता है कि ि ाक्षा के मामला में समाजवाद आ गया है। इस वक्त तो यह होता है कि अमीरों और अफसरों के बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ कर अफसर बन कर निकलते हैं और गरीबों के बच्चे तो क्लर्क भी नहीं बन पाते हैं वे तो ि ाक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ी मु ि कल से चपड़ासी ही बन

पाते हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ि ाक्षा यकसां की जाए और यह बात केवल कागज़ों में ही न रहे, बल्कि यह अमली तौर पर की जाए और इसके करने के लिए कोई टाईम की हद रखी जाए। यह जो हमारी ि ाक्षा प्रणाली है इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो नौजवान पढ़ कर निकलें, ि ाक्षित हो कर निकलें, उनके अन्दर अनु ाासन होना चाहिए, आत्म वि वास होना चाहिए और वे इस योग्य हों कि ि ाक्षित होने के बाद अपने पांव पर खड़े हो सकें। और नौकरियों के पीछे भागने की बजाए प्रांत के अन्दर उद्योग लगा कर अपना निर्वा कर सकें और इस तरह से दे ा की सेवा भी कर सकें, क्योंकि उनके ऐसा करने से दे ा भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसा करने के लिए इस ि ाक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की आव यकता है। हमारे ि ाक्षा मन्त्री चाहे वह हमारे प्रदे ा के हैं या केन्द्र के हैं, वह भी कहते हैं कि ि ाक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए लेकिन यह पता नहीं लगता कि वह यह बात किससे कहते हैं क्योंकि यह हाम तो उनके करने का है। हमारे राश्ट्रपति भी यही बात कहते हैं कि लेकिन अगर वह सरकार को यह हिदायत करें कि वह इस में परिवर्तन लाए तो यह उसका फिर कर्त्तव्य बन जाता है कि वह इस पद्धति में सुधार लाए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बातें करने से यह काम नहीं होगा इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए जाएं। हमारे हरियाणा में जो ि ाक्षा का बड़ा केन्द है वह कुरुक्षेत्र वि वविद्यालय है, लेकिन आप देखें उस में आजकल किस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही

है। वह वि वविद्यालय इस वक्त पुलिस का कैम्प बना हुआ है और उस के अन्दर पुलिस राज के ढंग का काम चल रहा है। विद्यार्थियों को बहुत आतंकित किया जा रहा है, वहाँ से पांच विद्यार्थी निकाल दिए गए और 112 विद्यार्थी ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं और इस से भी ज्यादा को बुरी तरह से परे ाान किया जा रहा है। यह आतंक समाप्त होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी ही हमारे भावी नेता होंगे दे ा के मालिक होंगे और कर्णधार होंगे। इसलिए उनके साथ दु मनी वाला रवैया अगर रखेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। उनके अन्दर दे ा प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए और उनको प्यार में अनु ाासन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि यह केवल विद्यार्थियों का ही कसूर नहीं है, यह हमारी इस ि ाक्षा पद्धति का कसूर है, जिसमें अनु ाासन के बारे में दे ा प्रेम के बारे में और उनको रचनात्मक काम करने के योग्य बनाकर अपना जीवन निर्वाह करने के योग्य बनाने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है केवल किताबी पढ़ाई पर जोर दिया जाा रहा है।

अब मैं कुछ आवास के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस मामला में गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब भी पूछते हैं, तो यही कहा जाता है कि भाहरों के लिए बस्तियां बनाई जा रही हैं क्योंकि वहां ही जरूरत है और गांव के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जाती है। गांव में भी बहुत अधिक संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग, हरिजन, गरीब लोग

जो आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं, बसते हैं, जिनको रहने के लिए मकानों की बहुत दिक्कत है, लेकिन गांव के लिए कोई भी आवास योजना नहीं बनाई जाती है, केवल बातें ही की जाती हैं। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां भी बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनके लिए इस योजना के बनाने की जरूरत है। रोजगार देने के बारे में इसमें लिखा गया है कि जो लोग एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज में रजिस्टर्ड हैं उनमें से केवल 11 प्रति ात बेरोज़गारों को रोजबार मिल सका है लेकिन बहुत बेरोज़गार ऐसे हैं जिनके नाम वहां दर्ज़ भी नहीं है, इसलिए अगर 11 फीसदी के हिसाब से ही रोज़गार मिला, तो फिर यह मसला कैसे हल हो सकता है, क्योंकि बेरोज़गारों की तादाद तो बढ़ती जा रही है और इस हिसाब से यह बेरोजगारी कब खत्म होगी। मैंने इस बारे में पहले भी सुझााव दिया था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इसका हल यह है कि ग्रामोद्योग, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कह लो, जब तक इन उद्योंगों का जाल नहीं बिछाएंगे तब तक यह बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं होगी। यही इसका एक मात्र हल है, वरना यह आगे से आगे गम्भीर से गम्भीर होती चली जाएगी। पैसे तो हर साल बजट में रखे जाते हैं, और खर्च भी किए जाते होंगे, लेकिन मसला ज्यों का त्यों है, क्योंकि सही ढंग से इस मसला को नहीं पकड़ा जा रहा है और यही वजह है कि यह समस्या बढ़ती जा रही है, कम तो इसने क्या होना हैं इसका हल करने के लिए सरकार को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। इस सम्बंध मैं

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो बड़े–बड़े उद्योग हैं, उनमें जो छोटी छोटी चीजें बनती हैं उन पर पाबन्दी लगनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि कुटीर उद्योगों में ही छोटी चीजें बनें। अगर कुटीर उद्योग ही ऐसी चीजें बनाएं, फिर तो हम कामयाब हो सकते हैं लेकिन अगर बड़े उद्योग भी बनाएं और छोटे भी बनाएं तो छोटे उद्योग बड़े उद्योग बड़े उद्योंगों का मुकाबला नहीं कर सकते और अन्त में फेल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इन कुटीर उद्योगौं में बैड ाीट, चमड़े का काम, साबुन, तौलिए, जूते, तेल इत्यादि बनें और इनके बनाने पर बड़े उद्योगों पर पाबन्दी लगाएं ताकि छोटे उद्योग तरक्की करें और लोग अपने पैरों पर खड़े हों। ऐसा करने से लोगौं के मन में आत्म वि वास जागेगा, नवयुवक कालेज से आने के बाद, ि ाक्षा पूर्ण करने के बाद कोई न कोई काम–धन्धा करने के लिए तैयार हो जाएगा और अपने अन्दर आत्म–वि वास पैदा करेगा।

यहां पर हरिजनों के बारे में बात आई, मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं तेजी से चलने की कोि ा ा कर रहा हूं, क्योंकि बातें बहुत सी हैं। और बातें तो हरिजनों के लिए हैं ही, सरकार केवल छुआछूत भी अभी तक समाप्त नहीं कर सकी। वैसे रेडियों पर चाहू छुआछूत के बारे में कुछ कह दें, यहां हाउस में भी कह देते हैं, लेकिन आप अपने–अपने गांव में जाकर देखें, तो पता लगेगा कि छुआछूत उसी तरह कायम है। वोट मांगने के लिए कुछ कह दें, यह बात अलग है लेकिन आप रोज़

के व्यवहार में देखें कि कितने लोग हरिजनों के साथ विवाह भाादियों में भाामिल होते हैं, कितने लोग कुएं पर पानी इकट्ठा भरते हैं ? इतने अर्से में भी हरिजनों में आपस में अभी तक छुआछूत समाप्त नहीं हुई, और इस बात पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसमें हरिजनों या दूसरे लोगों का दोश नहीं है, यह सरकार की नीति का दोश है क्योंकि सरकार चाहती है कि छुआछूत चलता रहे ताकि दो वर्ग बने रहें और हम कायम रहें। सिर्फ कागज़ में आर्डर करने से काम नहीं चलेगा। अगर दे ा का, प्रान्त का भला करना है तो सही कार्यवाही करनी होगी, तभी हमें लाभ पहुंच सकता है। यहां पर हरिजन कल्याण निगम के द्वारा हरिजन कल्याण की बात कही गई। लेकिन मैं समझता हूं कि हरिजनों का तो इतना कल्याण नहीं हुआ है, कल्याण तो किसी और का ही हुआ है। मैं आपको हिसार जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से कई साल पहले, हिसार जिले के 40–42 हरिजनों को ट्रैक्टरों लिए कर्जा मिला और वह ट्रैक्टरों के नाम पर खर्च गया। उन हरिजनों के पास न तो जमीन है और न ट्रैक्टर्ज़ हैं। इसी मामलें में इन्वाल्वड एक फर्म है जिसका नाम है "सरदार सिंह जगत सिंह"। यह हिसार में थी लेकिन अब भाायद मुझे पता लगा है वह फर्म नहीं रही, आज से कुछ दिन पहले थी। उसने ये ट्रैक्टर सप्लाई किए थे। मुझे पता लगा कि इस सदन के एक सदस्य का इसमें हाथ है। मैं समझता हूं कि यह रुपया एक तरह से चोरी हो गया खुर्दबुर्छ किया गया और इस रुपए का गलत इस्तेमाल किया गया। अध्यक्ष महोदय इसलिए मैं आपके द्वारा

निवेदन करूंगा कि विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बना दी जाए जो इस चीज की जांच करे, छानबीन करे और इसकी रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जाए। अगले सै ान में यह रिपोर्ट आ जाए क्योंकि तब तक ये सारे तथ्य समिति के सामने आ जाएंगे यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। हरिजनों के नाम पर कर्जा आता है लेकिन हरिजन कहते हैं कि हमने तो लिया नही नहीं। फिर जिन लोगों ने यह रुपया हेरा फेरी से लिया उन्होंने ही कर्जा की किस्त मांगने पर दाखल करवा दिया ताकि उनकी पोल न खुले। जिस काम के लिए यह पैसा खर्च होना चाहिए था हरिजनों की बहबूदी के लिए, उस पर तो खर्च नहीं हुआ बल्कि किसी औरों की बहबूदी हुई हरिजनों की नहीं हुई, इसलिए इसकी जांच बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ में कहना चाहूंगा कि और उद्योग तो बन्द पडे हैं परन्तु सरकार ने एक और ही उद्योग की तरफ ध्यान दिया है। मैं इस पर थोड़ी देर ही बोलूंगा इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि जिस चीज का प्रान्त को कोई लाभ नहीं है, जिससे लोगों का चरित्र खत्म होता है उसका उद्योग सरकार ने भाुरू कर दिया और राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में कहा गया कि भाराब उत्पादन भाुरू हो गया है। भाराब उत्पादन की इतनी आव यकता कही थी ? भाराब उत्पादन की इतनी आव यकता कही थी ? हमें तो दूसरी चीजों की आव यकता है, यह सरकार भाराब की तरफ क्यों

जा रही है ? इससे न दे ा का भला है, इससे समाज में खोखलापन आ रहा है। इससे बहुत हानि होने वाली है इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे उद्योग न खोल कर दूसरे उद्योग खोले जिससे दे ा की उन्नति होती है।

अब मैं प ाुधन की चर्चा करना चाहूंगा। प ाुओं को नाकारा बनाकर, बीमार घोशित करके बाहर भेजा जाता है। उनको इस तरह बाहर न भेजें, बल्कि यहां पर ही उनकी नसल सुधारी जाए। अगर हम नसल सुधारेंगे तब ही हम प ाुधन का सुधार कर सकते हैं। करनाल भ्ागर मिल मेरे ख्याल में 7–8 साल से रजिस्टर्ड सोसायटी है लेकिन अब आकर इसमें थोड़ा सा सुस्त रफ्तार से काम भ्ारू हो गया है। सोनीपत में भी एक और मिल लगाई जाने की योजना है, ये दोनों मिलें जल्दी मुकम्मल होनी चाहिए। अगर ये भी सात आठ सात तक लटकी रहें जिस तरह से ये लटकी रही तो इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे इस प्रान्त की तरक्की रूक रही है, सारे निर्माण के कार्य बन्द हैं। पंडित जी रोज कहते हैं कि स्लो डाउन कर दिया, आहिस्ता कर दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह काम जितनी जल्दी पूरा होगा उतनी ही ज्यादा हम अपने प्रान्त को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं।

जहां तक बस सुविधा का ताल्लुक है, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बस स्टौप्स पर सवारियां खड़ी रहती है, बस ड्राईवर बस स्टौप पर रोकता ही नहीं, सवारियां खड़ी

रहती हैं और बस एक फर्लांग पर जाकर खड़ी होती है और लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है। इस पर तो कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बिना पैसे से ही इसमें सुधार हो सकता है। लोगों को इस बात की सुविधा होनी चाहिए कि बस–स्टौप पर बस खड़ी हो, वहीं से सवारियां उतरें और वहीं से चढ़ें। इसके इलावा जो बस–स्टौप बने हुए हैं वहां पर बस की इंतजार में दा–दस, बीस–बीस सवारियां खड़ी रहती हैं। लेकिन धूप और बारि ा से बचने के लिए वहां पर कोई भौड नहीं है। इसलिए सरकार से गुजारि ा है कि बस–स्टौप पर भौड बनाए जाएं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर ऐड्रैस पर एक और बात आई कि वर्श 1974 के दौरान सामान्य कानून की व्यवस्था की स्थिति सन्तोशजनक रही है।

श्री अध्यक्ष: अगर आप इस तरह से पढ़ने लगे तो सारा टाईम लग जाएगा। आप बाइंड अप करें, आपने काफी टाईम ले लिया है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं अभी खत्म करने जा रहा हूं। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों, पिछले साल कई जगहों पर पुलिस ने ज्यादती की है। अगर इन ज्यादतियों की गिनती करने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। पेहोवा, पानीपत, करनाल, बरवाला, रिवास वगैरा कई जगहों पर

पुलिस ने ज्यादती की है। यह ज्यादती रोकी जानी चाहिए। लठ से राज कुछ दिन तो चल सकता है लेकिन यह जनतन्त्र है, अगर सरकार जनता की सहमति से चले तो अच्छी बात है। इसलिये पुलिस राज की भावना समाप्त होनी चाहिए। पुलिस व्यवस्था की एक मिसाल आप को देना चाहता हूं कि पिछले दिनों अम्बाला छावनी में एक तारा चंद वर्मा ....

श्री अध्यक्ष: आप वाइंड अप करें, आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: मैं खत्म करने जा रहा हूं जी।

श्री अध्यक्ष: टाईम मुकर्रर किया हुआ है, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, आप तो बिजनैस ऐडवाइज़री कमेटी के भी मैंबर हैं, आपको तो पता है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अभी खत्म करने जा रहा हूं। अम्बाला में एक अखकार ' ाोला' के एडीटर थे श्री तारा चन्द वर्मा, उनका मरडर 20—12—1974 को किया गया। इनका अभी तक कोई कलू नहीं निकला कि किसने मरडर किया है। इसका कारण एक ही समझा जाता है। वह यह कि लोगों के मन में भाक है कि वह चूंकि सरकार के खिलाफ और लोकल पुलिस के खिलाफ अपने अखबार में लिखता था, इस लिए भाायद उसकी मृत्यु हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। यदि जांच होगी तो ही सारी बातें सही निकलेंगी।

अध्यक्ष महोदय, एक और बात इस अभिभाशण के अन्दर आई है कि इन्होंने स्मगलरौं, जमाखोरों और दूसरे सारे के सारे समाज विरोधी कार्य करने वाले लोगों को पकड़ा है, लेकिन हमारे इसी सदन के उस माननीय सदस्य के बारे में जिसकी कई फर्में हैं, जिसके बारे में अखबारों में भी आया कि बहुत सा सामान, पता नहीं 25 लाख का या कितने का पकड़ा गया, हमें कुछ पता नहीं लगा –– (विघ्न) ––

Mr. Speaker: Order please. No. aspersions on any member of this House.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि उसके बारे में भी हमें पता लगना चाहिए कि उसका क्या हुआ ?

Mr. Speaker: Please resume your seat. You are not winding up.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: मैं अब समाप्त ही कर रहा हूं।

Mr. Speaker: Please resume your seat. You have taken all the time.

चौधरी ि ाव राम वर्मा: बस जनाब दो मिनट और लूंगा। तो मै। कहने जा रहा था कि पुलिस तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन अमनो–इन्तज़ाम ठीक ढंग से नहीं चल रहा। इसके अन्दर काफी सुधार की आव यकता है। तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अभिभाशण के अन्दर अगर यह भी जोड़ दिया जाए कि––

"आव यक तथा जीवनोपयोगी वस्तुऔं का अभाव, महंगाई, चोर–बाजारी, भ्रश्टाचार तथा काले धन का प्रभाव रोकने में सरकार पूर्णता असमर्थ रही और बिजली, पानी का प्रबन्ध करने में भी वह पूरी तरह असमर्थ रही है जिसके कारण खेती और उद्योग को घाटा हो रहा है।"

तभी इस सरकार के पूरे काम सामने आएंगे। इन भाब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, मैं उस रैज़ोल्यू ान की, जो गुलाब सिंह जैन जी ने मूव किया और जो ी साहब ने जिसकी ताईद की है, ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो ी साहब की सारी दलीलों की भी मैं ताईद करता हूं लेकिन मूवर आफ दी रैज़ोल्यू ान की एक आध बात के बारे में, जो कि रैलेवैन्ट नहीं थी, जिनका इस रैज़ोल्यू ान से या इस ऐड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर टाईम मिला तो इस बारे में कुछ अर्ज़ करूंगा। स्पीकार साहब, यह जो गवर्नर ऐड्रस होता है यह वेरियस डिपार्टमैंट्स के बारे में एक पालिस ऐड्रेस होता है और किसी बर्निंग टौपिक़ के बारे में, जिसकी तरफ स्टेट की तवज्जुह गहरी तरह से लगी हो। इसके द्वारा गवर्नमैंट अपनी

पालिसी डिक्लेयर करती है। कुछ टौपिक्स के बारे में तो वह लिख कर करती है और कुछ के बारे में चुप रह कर करती है। मुझे खु ाी है कि एक बड़े अहम मसले पर यह सरकार चुप है। यह वह अहम मसला है, जो चण्डीगढ़ और अबोहर फाज़िल्का़ा के फ्यूचर से ताल्लुक रखता है। इसका गवर्नर साहब ने और गवर्नमैंट ने अपने ऐड्रैस में ज़िक्र नहीं किया। इसके लिए मैं गवर्नमैंट को तहदिल से मुबारिक़बाद देता हूं। Sometimes silence is more eloquent than speech. इस गवर्नमैंट की यह पालिसी यह जाहिर करती है कि हरियाणा का इंट्रैस्ट तो हमें प्यारा है ही, लेकिन हिन्दुस्तान का इंट्रैस्ट उससे भी ज्यादा प्यारा है। ऐसे वक्त में जब कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुज़र रहा है, किसी कन्ट्रावि र्यल इ ू को छेड़ कर हम सैन्टर को एम्बैरैस नहीं करना चाहते और अपने पड़ौसियों से हम लड़ना नहीं चाहते। इस वास्ते हमारी गवर्नमैंट का यह वाईज़ स्टैप है कि न तो चण्डीगढ़ के बारे में कुछ बोला जाए और न ही अबोहर फाज़िल्का के बारे में बोला जाए। स्पीकर साहब, मैं अलबत्ता यह अर्ज़ किया चाहता हूं कि चण्डीगढ़ अब न पंजाब का, न हरियाणा का, न हिमाचल का प्रदे ा का जिनके रिसोर्सिज़ से यह बना और न ही यह दिल्ली का जिनके रिसोर्सिज से यह डिवैल्प हो रहा है, मसला है। चण्डीगढ़ अब सारी दुनियां का मसला है। ताजमहल यू0पी0 में जरूर है, भुवने वर में टैम्पल्ज़ जरूर है, लेकिन वे उस सूबे की जायदाद नहीं हैं। चण्डीगढ़ का एक बहुत बड़े आदमी, नेहरू ने स्वप्न लिया, एक बहुत बड़े टेलन्टिड आदमी कारबुज़े ने बेहतरनी

इंजीनियरों के साथ मिलकर उस स्वप्न की तामीर की और स्पीकर साहब यह खूबसूरत भाहर बीसवों सदी के फर्स्ट हाफ में भाुरू होकर इस सदी के आखिर तक एक ऐसी चीज़ बन जाएगी, जो दुनियां में अपनी किस्म की एक युनिक चीज़ होगी। जब पंजाब के मेरे भाई यह कहते हैं कि चण्डीगढ़ हमें दे दो, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि उनका क्या एटीच्यूड है। यह तो हरियाणा को मिलना था, लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने इसे ठीक ही हरियाणा को नहीं दिया। हरियाणा इसकी वह सही मैंटीनैंस नहीं कर सकता जिसका स्वप्न नेहरू ने लिया था, जिसके लिए टेलैन्ट कारबुज़े की थी, पीलू मोदी और दस दूसरे आर्किटैक्ट्स की थी। इसको तो सैन्ट्रल गवर्नमैंट ही अपने पैसे से मेनटेन कर सकती है। अगर पंजाब के जत्थेदारों को इसके दे दिया तो भी वह खूबसूरती, जो दुनियां में पदैा हुई थी, टवन्टियथ सैन्चरी में हिन्दुस्तान की सरेज़मीन पर वह खत्म हो जाएगी। इसकी बड़ी बड़ी लेंज़, यह लैण्ड स्केप, नेहरू का वह स्वप्न, आर्किटैक्ट्स को तमाम आर्ट, इन सबके साथ वही हेागा, जो एक खूबसूरत तस्वीर के साथ, जिसे किसी नादान बच्चे को दे दिया जाए और वह उस पर स्याही फैंक दे होता है। स्पीकर साहब, दुनियां की हिस्टरी में जब आर्ट की हिस्टरी लिखी जाएगी तो उसमें चण्डीगढ़ टाइन का एक युनिक स्थान होगा। तो चण्डीगढ़ का टाउन, जो एक स्पै ाल टाउन है, जो एक पीस आफ आर्ट है, जत्थेदारों के हवाले नहीं किया जा सकता। मैं चण्डीगढ़ के बारे में, स्पीकर साहब, यह कहना चाहता हूं। मैं अबोहर फाज़िल्का पंजाब में रहे तो हिन्दुस्तान में है,

हरियाणा में रहे तो हिन्दुस्तान में है। लेकिन हरियाणा का एटीच्यूड सैंट्रल गवर्नमैंट के लिए बड़ा कन्स्ट्रक्टिव है। बिल्कुल सीधी बात है। –– (विघ्न) –– दोनों तहसीलें हरियाणा को मिली थीं। मैं तो पे ा होता रहा भााह कमी ान के सामने। खरड़ तहसील भी हरियाणा की थी, क्योंकि वह हिन्दी स्पीकिंग है और फाज़िल्का भी हरियाणा की थी, क्योंकि वह भी हिन्दी स्पीकिंग डिक्लेयर हुई थी। लेकिन एक औड टर्म आफ रैफ्रैन्स से कि कन्टिग्विटी नहीं है, तीन गांव, हरियाणा के एक स्टेटसमैन ने प्रताप सिंह कैरों के वक्त में, हरियाणा से निकाल कर अपनी कलम से पंजाब में दे दिए। उन स्टेंटसमैन को आने वाली नसलें क्या याद करेंगीं, यह तो समय ही बातएगा लेकिन वह तीनों गांव की कंटिग्विटी जो टूटी उसकी वजह से अबोहर फाज़िल्का पंजाब में रह गया। अबोहर–फाज़िल्का के पंजाब में रहने की और कोई बात नहीं थी। इन हालात में हरियाणा की बड़ी कंस्ट्रक्टिव एप्रोच है। हम नहीं बीमारी छेड़ते, पंजाब वाले छेड़ना चाहें तो छेड़ कर देख लें। उसमें वे घाटे में रहेंगे और मुल्क़ तो घाटे में रहेगा ही। इन अल्फाज़ के साथ मैं गवर्नमैंट का फिर भाुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने चुप रहकर के, कुछ न कह करके, मुल्क की बड़ी भारी सेवा की है।

स्पीकर साहब, दूसरा प्वांयट जिसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह है डिवैल्पमैंट का। जींद के आनरेबल मैंबर ने हाउस में यह कहा था कि यह जो अभिभाशण है, पिछले साल भी

वही था, उससे पिछले साल भी वही था और उससे पिछले साल भी वही था। मुझे बड़े अफसोस सै कहना पड़ता है कि चौधरी दल सिंह जी की नुक्ताचीनी पिछले साल भी वही थी, उससे पिछले साल भी वहीं थी, उससे पिछले साल भी वही थी और ऐसा मालूम होता है कि पिछले साल उन्होंने जो नोट्स तैयार किए थे वे ही उन्होंने दोबारा यहां पढ़ दिए। कितने ट्यूबवैल्ज इधर गए, कितने उधर गए, कितने ट्यूबवैल्ज़ थे, कितने नहीं थी, यह सब पुरानी बातें हैं। स्पीकर साहब, यह ब्रौड फैक्ट है कि हरियाणा में डिवैल्पमैंट हुई है और इतनी मार्काखेज़ डिवैल्पमैंट हुई है कि इस हकीकत से जो इनकार करता है वह अपने आप को खुद फरेबी बनने में मुबतला करता है। डिवैल्पमैंट के बारे में कोई दो राय नहीं हैं। इसके लिए अगर क्रेडिट परमानैन्ट एग्ज़ैक्टिव लेना चाहती है, तो वह भी ले ले। भला वह क्यों न ले ? क्या वह हरियाणा के नहीं हैं ? क्या उनका पार्ट नहीं है उन प्लान्ज़ की ऐग्ज़ीक्यू ान में, जो तैयार की गई है ? अगर क्रेडिट गवर्नमैंट लेती है, तो वह लेने की हकदार है। लेकिन इस डिवैल्पमैंट में और फैक्टर्ज़ भी हैं। मैं सबसे बड़ा फैक्टर इस चीज़ को मानता हूं कि the very creation of Haryana is responsible for this progress. पहले यह पंजाब का हिस्सा था और इसके ही पैसे यहां खर्च नहीं होते थे, लेकिन अब हरियाणा का पैसा हरियाणा में खर्च होता है। इसका क्रेडिट वह आदमी तो जरूर लेगा, जिसने पार्लियामैंट में सबसे पहले कहा था कि हरियाणा बनना चाहिए और आखिर तक इस बात पर डटा रहा यानि प्रताप सिंह दौलता ही।

दूसरा प्वांयट डिवैल्पमैंट के बारे में क्रिए ान के अलावा जो है वह है ..... स्पीकर साहब, एक भी तो बी0एल0डी0 का मैंबर यहां नहीं है, मेरी बदकिस्मती तो यह है। यह कोई पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी है ?

—— (विघ्न) ——

कुछ आवाजें: हम बता देंगे।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, हरियाणा की जो डिवैल्पमैंट हुई है, वह डिवैल्पमैंट वही है, जिसे चौधरी चरणसिंह चाहते हैं और यह डिवैल्पमैंट हमारे हरियाणा में इतनी हो सकी है, कि अगर चौधरी चरण सिंह यू0पी0 में पावर में भी आ जाएं, तो भी नहीं कर सकेंगे। —— (विघ्न) —— स्पीकर साहब, आनैस्ट गांधीयन लाईक चौशरी चरणसिंह, लीडर आफ दी बी0एल0डी0 का इख्तलाफ कांग्रेस से यह है कि अब की कांग्रेस ने गांधीयन तरीका जो डिवैल्पमैंट का था, वह छोड़ दिया और रि ायन तरीका यानी सो ालिस्ट प्लांड इकोनोमी का वह अख्तियार कर लिया। स्पीकर साहब, मेरे विचारानुसार इस वक्त हिन्दुस्तानप में अपोज़ी ान के बड़े नेताओं के छोटे—मोटे लीडर तो और भी होंगे, दो ईमानदार आदमी हैं। एक तो हैं कांग्रेस (ओ0) के मोरार जी देसाई और दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह जिनको सीरियसली लिया जाना चाहिए, जिनके हर लपज़ को हर जिम्मेवार गवर्नमैंट को ध्यान में सुनना चाहिए।

मुझे खु ाी है कि बहन इंदिरा जी जब रोहतक आई, तो वे चौधरी चरण सिंह की पोलिटिकल थ्योरी पर काफी देर तक बोलती रहीं। उनकी डिफ्रैंन्स यह है कि जो डिवैल्पमैंट हो रही है, वह गांधीयन वे पर नहीं हो रही है। गांधीयन–वे क्या है ?

Mr. Speaker: Please speak about Haryana.

Chaudhri Partap Singh Daulata: I am coming to Haryana.

गांधीयन–वे तो यह है कि डिवैल्पमैंट के सिलसिले में ऐग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायिरिटी और उद्याग को सैकेण्ड प्रायरिटी दी जाए। स्पीकर साहब, गवर्नर एड्रैस के लास्ट पेज़ पर लिखा हुआ है हि हरियाणा के बजट का 60 प्रति ात के ऊपर हिस्सा इरीगे ान और इलैक्ट्रिसिटी पर खर्च होता है। उद्योगा को सैकेण्ड प्रायरिटी है। उसी पर गवर्नर महोदय सैटिसफाई नहीं हुए। उन्होंने वन लाईन लास्ट पेज़ पर, एक इनसटान्स दिया है कि रबी की फसल बोने के वक्त क्राइसिज़ आए। उस टाईपर पर यह सवाल पैदा हुआ कि इंडस्ट्रीज़ को बिजली दी जाए या ऐग्रीकल्चरिस्टस को बिजली दी जाए। इंडस्ट्रीज को बिजली बन्द करके ऐग्रीकल्चर को बिजली दी गई। यह है गान्धीयन–वे कि एग्रीकल्चर को बिजली में प्रायरिटी दी, इंडस्ट्रीज़ को नहीं दी। तो बी0एल0डी0 की जो पालिसी है, उसको सिर्फ हरियाणा ही एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। अगर दल के आदमी पढ़े–लिखे होने का दावा करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें गवर्नर महोदय का भाुक्रिया

अदा करना चाहिए था। कोई इस दे ा में ऐसी जगह तो है, प्रान्त तो है जहां ओल्ड गांधीयन–वे अडोप्ट किया हुआ है, एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। हरियाणा गवर्नमैंट की डिवल्पमैंट की पालिसी गांधीयन–वे की है। अब रही बात इस सारी डिवल्पमैंट का क्रेडिट लेने की, गवर्नर महोदय की पर्सनैलिटी भी जिम्मेवार है, सी0 एम0 भी जिम्मेवार है लेकिन एक बात बिल्कुल ही गलत है, जो बाबू गुलाब सिंह जी ने कही कि सी0एम0 साहब को जो दमे की बीमारी है, वह डिवैल्पमैंट की जिम्मेदार है। उन्होंने यहां हाउस में कहा कि उनका दमा है, वे रात को जाग उठते हैं और जब जाग उठते हैं, तो सोचते रहते हैं इसलिए हरियाणा की डिवैल्पमैंट हो गई। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि उनको चार पांच बीमारी और लग जाएं तो उससे ऐसा होगा कि वे सो ही नहीं सकेंगे और हरियाणा की डिवल्पमैंट होती ही चली जाएगी। He is not so simple as that. The thing is that political structure of Haryana because of the sound wisdom of the Haryanavi voter is touched that a stable Government under a dynamic head, under congress policy, is being run with the help of those responsible persons who were not returned on congress ticket but are patriot enough to support constructive policy of the Government. कोई स्टेट ऐसी है जहां पर अपोज़ी ान के मैंमरों से पहले डिस्कस किया जाता हो। हमारे सी0एम0 साहब आकर उनसे बातचीत करते हैं। यह दूसरी बात है कि कभी चौधरी राम लाल जी या चौधरी दल सिंह जी से झड़प हो जाए। कया यह कोई अपोज़ी ान वाली बात है ? जब उनकी कोई और एक्सरसाइज न हुई हो तो तब वे

आया करते हैं, वरना हमारा तो पूरा को ऑप्रे ान है, चाहे वे हरिद्वारी लाल का ले लें, चाहे रिज़कराम का ले लें। और आजकल तो थोड़ा सा चौधरी दल सिंह का भी स्वभाव नर्म सा हो गया है। हम तो सार ही उनको वाहिद कोऑप्रे ान देते रहे हैं। इस स्टेबिलिटी में हमारा क्रेडिट पता नहीं श्री गुलाब सिंह जी को क्यों नज़र आता। वे तो गिनते ही नहीं। –– (विघ्न) ––

स्पीकर साहब, तीसरा प्वांयट सर्विसिज़ के बारे में है। गवर्नमैंट की पालिसी है in respect of service recruitment. What constitutes the bureaucracy ? उसमें काफी कमियां हैं, लेकिन मैंने कभी हिपोक्रेसी से काम नहीं लिया। स्पीकर साहब, मैं ईमानदार से कहता हूं। मुझे गवर्नर साहब के वे लफज़ याद हैं जब मैं मिनिस्टर था; उन्होंने कहा था– Haryana is the only State which is run by non-Haryanavi bureaucracy. सर्विसिज़ की कोई किताब उठा लें उसमें बड़ा गजट उठा लें, छोटा उठा लें। बाहर गांवों में जाओं तो आपको मिलेगा कि 'अरे तू कड़े जा सै'। ''किततै आया सै', 'के गयान से भाई' और उसी ब्लाक के दफ्तर में आपको मिलेा 'किथे गया सी, किवें आया सी, किथे जांदा प्या है।' तमाम ब्योराक्रेसी नीचे से ऊपर तक उन लोगों की है, जो इमो ानल हैं और जिसका हरियाणा से, कोई सरोकार नहीं। चौधरी राम लाल जी को यह बात बहुत पसन्द आएगी, लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि हरियाणा के बनाने वाले हरियाणा के

लोग, जब हरियाणा बना, तो यह दावा करते थे कि जो परमानैंट हुकमरान हैं, सरकारी मुलाज़िम हैं इनमें हरियाणा के लोगों का हिस्सा होगा। अगर ये सब सारे के सारे पंजाबी स्पीकिंग जो कि हरियाणा की मुलाज़मत को डोमिनेट करते हैं, हरियाणा के हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हरियाणा में कोई भी पंजाबी नहीं बसता। हरियाणा में चाहे कोई खतरी है, चाहे अरोड़ा है, चाहे जाट है, चाहे सैनी है, चाहे ब्राह्मण है, वे सब हरियाणवी हैं, लेकिन जो आदमी हरियाणा में तीस वर्श बसने के बाद यह कहे "साडे पंजाबियों पर जुल्म होन्दा प्या है।" "सानूं कोई बरदा त नहीं करदा", अपनी सैप्रेट इन्टेटी करेंगे, वे मेरे भाई घाटे में रहेंगे। मै। उनसे अर्ज़ करूंगा कि वे अपने आपको हरियाणवी ही कहें। अगर यह तमाम सर्विसिज़ पंजाबी स्पीकिंग जो हरियाणा में हैं, हमारी अपनी सैटलर्ज़ हैं, अगर वे अपने आपको बाहर का कहते हैं, तो All the more undersirable. उनको आज आबादी से ज्यादा सर्विसिज़ मिली हुई हैं। वक्त आना चाहिए कि हरियाणा के लोगों को हरियाणा में सर्विस परमानैन्ट मिलनी चाहिए। गवर्नर साहब के एड्रेस में लिखा है कि हरिजनों को मिली। परमात्मा का भाुक्रिया कि हरिजनों की रिज़र्वे ान है। चार–पांच आई0ए0एस0 हैं। जब मैं इधर को मुंह करता हूं और जब आफिसर गैलरी में उनको देखता हूं, तो दौलत जैसे जजबाती आदमी का दिल राजी हो जाता है कि हरिजन तो हैं। अगर हरिजनों की रिज़र्वे ान न होती, तो वे बेचारे भी न होते, लेकिन इन हरिजनों के बाद बैकवर्ड और साठ प्रति ात अजगर हैं। I am not apologetic about

it. किसान का बेटा चाहे मिश्र में मरे, चाहे कहीं मरे, वह कहता है मुझे मेरे गांवों में फूंको, चाहे वह रेलवे स्टे ान पर ऐक्सीडैंट से मरता हो, वह कहेगा कि मुझे ले जाओ, बलवा बाजार में, वहां पर फूंको। जो पीजैन्ट प्रोपराइटरी के बच्चे हैं जिनकी तादाद 61 परसैन्ट है, उनको मुलाज़मत पिछले 25 साल से नहीं मिल रही है, और न ही उनके लिए रिज़र्वे ान है। वे धीरे–धीरे तमाम मुलाज़मत से चले जा रहे हैं। आज सर्विसिज़ तमाम की तमाम उनके हाथ से निकली जा रही हैं। गवर्नमैंट को यह सोचना पड़ेगा कि सन्ज़ आफ दी सायल, जो किसान पांच–छः एकड़ का मालिक है, चाहे वह गौड़ ब्राह्माण हो, चाहे अज़गर हो या सैनी हो, उनको मुलाज़मत में कैसे लाया जाए। यह गवर्नमैंट का हैड–एक है। गवर्नमैंट को सीरियसली सोचना चाहिए वरना वह सिचुए ान हिन्दुस्तान में क्रिएट होगी जो महाराश्ट्र में हुई थी, और यहां अभी नहीं, कभी कोई हरियाणवी सैना बनेगी, जो मुलाज़मत में अपना हिस्सा मांगेगी, सारे हमारे जैसे ठन्डे खून की जनरे ान नहीं होगी।

स्पीकार साहब, सर्विसिज़ के बाद मैं नैक्सट प्वांयट पर आता हूं। मेरा अगला प्वांयट गवर्नमैंट की लैण्ड री–क्यूजी ान की पालिसी के बारे में है। आप कोई भी गजट उठाइए। पहली चीज़ आपको मिलेगी यह कि डिवैल्पमैंट के लिए इतनी जमीन ले रहे हैं, रेल निकाल रहे हैं, इतनी ज़मीन नहर के लिए निकाल रहे हैं, इतनी फलां चीज़ के लिए चाहिए। अगर डिवल्पमैंट होगी, तो

आसमान से तो होनी नहीं, ज़मीन पर ही की जाएगी, लेकिन मैं गवर्नमैंट की तवज्जोह खास तौर से रेवैन्यु मिनिस्टर साहब की वे बहुत लरनड लाइयर हैं, मुल्ला की री–क्यूजी ान के बारे में इनक्वायरी थी, की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट को निकाल कर जो कि रौनक सिंह के मामले से सम्बन्धित है, गवर्नमैंट पढ़े। किसान की ज़मीन एक्वायर करके इंडस्ट्री वालों के लिए देने के माने क्या हैं ? किसान बेचारे को भाव नहीं लेने देते। उसे उसकी मर्ज़ी के भावन पर अनाज नहीं बेचने देते। इंडस्ट्री वाले आते हैं, और वह अपनी इंडस्ट्री एस्टेबलि ा करना चाहते हैं, तो उन्हें ज़मीदार को मुंह मांगे पैसे देने चाहिएं, जिन की ज़मीन में कारखाने लगे हैं, धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वहां मेरी मां, बहन, बेटियां लामनी नहीं कर सकती। क्या हक हक इंडस्ट्रीज के एिल गवर्नमैंट ज़मीन एक्वायर के बारे में मुल्ला ने जो लिख दिया उस रिपोर्ट को गवर्नमैंट को हबीब के तौर पर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मेरा सुझाव यह है कि किसान की ज़मीन एक्वायर की जाए लेकिन जहां एक एकड़ की जरूरत होती है तो पांच एकड़ एक्वायर करते हैं, परवाह नहीं करते। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि एक्वायर करने वालों को गवर्नमैंट की इन्स्ट्रक ान्ज़ हैं कि तुम गवर्नमैंट के अफसर हो, do not act as judicial officer. Give the least compensation that you can give. मैं ज़िम्मेवारी से कहता हूं कि इंस्ट्रक ान्ज़ मौजूद हैं। इस किस्म की बात ज़मींदार के साथ होती है वह फिल्म मुझे रह–रह कर याद आती है जो रूस में फिलमाई गई, जो छः महीने तक चलती

रही, दो बीघे ज़मीन दो। एक बैग पकड़े हुए एक मारवाड़ी, बंगाल के खेतों में गया कि मैंने कारखाना लगाना है। उसने कहा कि मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। जाकर रक ाा चलाई, 15 साल के बाद जब वापिस आया तो पता चला कि तपेदिक में तेरी मां भी, बाप भी, सब मर चुके हैं और ज़मीन पर कारखाने का धुआं है। वह यह सुनकर वहीं गिर कर मर गया। आज ज़मीन एक्वायर करना एक मजाक बना रखा है। ज़मीन ओन करना एक जुर्म बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए, जो चालीस साल पहले अनारकली और लाहौर के बाजारों में बाद ााह की तरह घूमते थे आज वह मुजरिम से बने फिरते हैं। कोई कहता है कि मुझे मकान की ज़मीन दो। अरे भाई मकान बनाने के लिए ज़मीन लो। कानून बना हुआ है कि पंचायत से एक पैसे गज के हिसाब से ज़मीन ले लो। Let Government know it that the land which vests in the Gram Panchayat does not belong to Haryana Government. It belongs to the proprietors of those villages. Supreme Court has given a clear ruling. It vests in them. The ownership still remains with the proprietors. It can be used for the well being of the entire community but not this 'kharayat'. चौधरी चांद राम जी को राजी करने के लिए हरिजनों को प्लाट दे दिए। भाई, जिसके पास ज़मीन नहीं वह भी इतना ही दुःखी है जितना हरिजन है। ग्राम पंचायत के कामन लैण्ड एक्ट में प्रोविजन है कि वे मोल ले लें, वे अपना मकान बना लें। वैसे तो मेरी इक्वीज़ि ान और री–ऐक्वीज़ि ान के बारे निवेदन है कि वे यह न भूलें जिनकी ज़मीन है, वे आज इस वक्त घबराए हुए हैं। पोलिटिकल तौर पर

कन्फयूज़ड हैं। वे पहली जनरे ान को भूल चुके हैं कि जब वह हुकमरान की तरह से चलता था। लोगों को यह बुरा महसूस हुआ है कि कौड़ियों के भाव उनकी ज़मीन एक्वायर करके इस बेदर्दी के साथ दी जा रही है। फालतू ज़मीन लेकर कभी कारखाने के नाम पर, कभी दूसरे के नाम पर बरबाद की जा रही है और पार्टिकुलर्ली सैनी बिरादरी की ज़मीन जो हमारे ज़मीदारों की सबसे गरीब ज़मीदारों की बिरादरी थी, जो भाहर में रहते थे उन सब की ज़मीन एक बहाने या दूसरे बहाने ले ली गई है। यह सैनी बिरादरी भाहर का सबसे गरीब तबका था, वे सब बे–ज़मीन हो चुके हैं। गवर्नमैंट की एक्वीज़ी ान की पालिसी निहायत बे–रहमाना पालिसी है, ऐंटी पीजेन्ट पालिसी है। मैं इसके बारे कोई जज़बात को उभारना नहीं चाहता।

अगला प्वांयट जिस पर मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं वह है प्राइस आफ ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रोडयूसर को पूरी कीमत क्यों ने मिले। स्पीकर साहब, मैं ज्ञानी जैल सिंह का, विनायक का और चौधरी बंसी लाल जी का म ाकूर हूं। इन्होंने बेचारौं ने पूरी कोि ा ा की कि प्रोडयूसर के लिए कन्ज़यूमर के मुकाबले में कुछ प्वांयट रेज़ करें। मुि कल यह है कि कुछ लोग तो पैदा करने वाले हैं और सारा हिन्दुस्तान कन्ज़यूमर है। उनके सी0एम0 आते हैं। वे ऐसी बढ़िया अंग्रेजी–वंग्रेजी बोलते हैं कि अपनी बात इम्प्रस कर लेते हैं।

लेकिन यह हमारी खु ाकिस्मती है कि चौधरी बंसी लाल ने अपना वहां स्कोप बना लिया है।

डिवैल्पमैंट के क्रैडिट के बारे में ज्यादा कुछ कहूं तो वह खु ाामद सा मालूम होगा। मैं प्राईस आफ एग्रीकल्चर के बारे में यह कहना चाहता हूं कि ज़मींदार के साथ इन्साफ नहीं होता। जो पैंसिल मेरे पास है, मुझे हक है कि जब कोई पूछ तो मैं यह बताऊं कि मैं इसे किस भाव पर बेचूंगा। चमार जूती बनाकर लटकाता है। जब चौधरी मेले में आएं, और पूछे तो उसको यह कह है कि वह कहे कि मै। 12 लूंगा या 14 लूंगा। सारी दुनियां को अपनी प्राडयूस की पूरी कीमत लेने का पूरा हक है। लेकिन इस ज़मीदार को जिसकी बूढ़ी औरत ने, जिसकी फूल सी बच्ची ने स्कूल जाने की बजाए खेत में काम किया, जो कभी ओले से डरती थी, कभी धूप से डरती थी, कभी सर्दी मरती थी, उसने, जिसने यह गेहूं का दाना पैदा किया, क्या वह मार्कीट में ले जाकर यह नहीं कह सकता कि यह दाना मेरे खून से पैदा हुआ है। बहक्कान वह अपने खून की पूरी कीमत लेगा। क्या गुनाह है, अगर वह अपनी प्रोडयूस की पूरी मार्किट वैल्यू मांगता है। स्पीकर साहब, सिवीलाइजे ान के नाम से तहज़ीब के नाम से, प्लानिंग के नाम से संसार में बहुत जुल्म होते हैं। लेकिन जो जुल्म इस प्रोडयूसर के साथ, इस दाना पैदा करने वाले के साथ होता है, वह बहुत ज्यादा है। आज हरिजन बड़े घमण्ड से कहता है कि मुझे अनाज सस्ता दो। जब वह टीके लगाने वाले, उनकी नसबन्दी करने वाले

जाते हैं तो कहता है कि हमारी तो वोटें कम हो जाएंगी। हम अगले इलैक्शन में डौमीनेट नहीं कर सकेंगे, इसलिए नसबन्दी नहीं करेंगे। बच्चे दबा कर पैदा करता है और फिर ज़मींदार से कहता है कि हमको सस्ता अनाज खिलाना। यह ज़मीदार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने परमिट कटवाकर बच्चे पैदा किए हैं। ज़मींदार के साथ यह एक मज़ाक बना हुआ है। मैं मानता हूं कि हरिजनों का भला किया जाना चाहिए। अछूतोद्धार किया जाना चाहिए। इसके लिए एक महकमा है। बड़ा जरूरी महकमा है।

चौधरी पीर चन्दः आन ए प्वांयट आफ आर्डर। मैं यह कहना चाहता हूं कि दौलता साहब चमारों या हरिजनों पर ही बोल रहे हैं या इस गवर्नर एड्रैस पर बोल रहे हैं। इन्होंने तो अपनी स्पीच में हरिजनों को ही नि ाना बना रखा है।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः स्पीकर साहब, हरिजनों का हिमायती मुझसे ज्यादा कोई नहीं है। मैं उनकी मुलाज़मत के लिए यहां तक कहता हूं कि हमारे वाली नौकरियां भी उन्हीं को दे दो। उनकी रिज़र्वे ान उनको ही रहे। लेकिन भई हरिजनों, इस बात को भूल जाओ, कि यह जमींदार तुम्हारे लिए अनाज पैदा करता है, वह अपने बच्चों के लिए अनाज पैदा करता है। वह तो महंगी ज़रूर बेचेगा। जो उनका नुमायन्दा उनसे वोटें लेकर आएगा, वह तो उनके अिलए पूरे दाम मांगेगा, चाहे छूट है चाहे न छूट है।

चौधरी पीर चन्दः दौलता साहब, आप तो पर्ची मांग कर आते हैं फिर ऐसी बातें करते हो।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः पर्ची मैंने कभी गिड़गिड़ाकर नहीं मांगी। पर्ची डंके की चोट पर अपनी पालिसी बताकर मांगी है। हर आदमी जानता है कि दौलता छोटू राम के बाद पक्का जमींदार है, जो अभी जिन्दा है। मैंने कभी गिड़गिड़ाकर वोट नहीं मांगे। ये रिवाड़ी वाले बैठे हैं, इनसे पूछ लो। डंके की चोट पर अपनी पालिसी बताई है कि मेरी यह पालिसी होगी। नम्बर वन ज़मीदार। ज़मीदार से कुछ बच गया तो हरिजन और भाहरी। –– (व्यवधान) –– मैंने कभी नहीं छुपाया। मैंने अपने ख्यालात को नहीं छुपाया। मैंने कभी हिप्पोक्रेसी नहीं की, अपनी जिन्दगी में भी कभी नहीं की। –– (व्यवधान) –– लाइन से तो मैं उतरा ही नहीं, कोई चढ़ने ही नहीं देता। जिनकी मैं नुमांयदगी करता हूं, चौधरी राम लाल जी, अगर वे मुझे समझ सकते या चौधरी छोटू राम को समझ सकते तो आज न पंजाब के टुकड़े होत, न इस हरियाणा पंजाब की मिट्टी खराब होती। हम कहीं के कहीं होते। –– (व्यवधान) ––

मेरा अगला प्वांयट है रूरल डैट। चौधरी दल सिंह जी यहां नहीं हैं, वे कहते थे कि हरियाणा पर 300 करोड़ का डैट चढ़ गया। मैं कहता हूं कि जिन्दाबाद बंसीलाल, तूने हरियाणा पर 300 करोड़ डैट चढ़ा दिया। उस डैट का क्या किया ? सड़कें

बिछा दीं। क्या कल कोई डिग्री लावेगा और हमारे सड़कें कुर्क करवाएगा ? उस डैट से क्या किया है ? बिजली के खम्भे गाड़ दिए। कल को कौन सा कोर्ट डिग्री देगा कि गांवों में से खम्भे उठा लाओ। जितना पैसा बंसी लाल जी ने हरियाणा के अन्दर बहाया है उतना कोई भी नहीं बहा सकता। अरे, सर्वोदय लीडरो, चरण सिंह और चरण सिंह के चार नादान साथियों, हिन्दुस्तान की ज़मीन पर इस रूरल इंडिया के लिए जितना पैसा बंसी लाल जी ने बहाया है उतना पैसा कोई नहीं बहा सकता। कर्ज़ा लाए हैं और मांग कर लाए हैं। चोरी से नहीं लिया है। हरियाणा की डिवैल्पमैंट के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। हरियाणा की डिवैल्पमैंट यूं हुई है। इस किसान के बेटे को किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, प्लेट पर नहीं रखा, किसानों ने भी उसकी टांग खेंचने की कोि ा ा की। दूसरों ने भी कोि ा ा की। उसने पहले अपने आपको ऐस्टेबलिश किया। फिर सैन्टर में अपने आपको ऐस्टेबलि ा किया। अगर आज चार पैस जैल सिंह को मिलेंगे तो पट्ठा हमारे लिए 12 पैसे लाएगा। अगर नायक 16 रुपए लेगा, तो हमारे लिए 36 रुपए मिलेंगे। लोन भी मिलेगा, ग्रांट भी मिलेगी। लोन से क्यों घबराते हो ? मैं चौधरी बंसी लाल जी से और पंडित चिरंजी लाल जी की सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक और डैट है जो हरियाणा को खा लेगा, और वह है रूरल डैट जो पीजेंट पर है। मेरे भाई हरिजनों ने भी बैंकों से कर्ज़ा लिया है, गवर्नमैंट ने बहुत पब्लिसिटी दी है कि कर्ज़ा लो, कर्ज़ा लो, लेकिन मुझे खु ाी है कि मेरे हरिजन भाइयों का ये क्या बिगाड़ लेंगे

क्योंकि उनके पास गरीबी के सिवाय कुर्क करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह खा पीकर यूं हाथ फेर कर चल देता है और उगराही करने वाले चक्कर काटते रहेंगे। लेकिन ज़मींदार के पास जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है दो एकड़ ज़मीन है, तीन एकड़ ज़मीन है, उनकी ज़मीन तो कर्ज़े के नीचे दबी पड़ी है। गवर्नमैंट इस बारे में सोचे कि यह कर्जे राईट आफ करने हैं या इनका क्या करना है। ज़मींदार को तो यह रूरल डैट दबा लेगा। यह तीन सौ करोड़ का कर्जा जिस पर चौधरी दल सिंह को दुःख आता है, वह तो हमारा अपना राईट है। खा पीकर बैठे रहो। किसने किसको देना है ? यह तो रूरल डैट की बात है।

इसके अलावा एक बात और मैं अर्ज़ किए देता हूं फिर मैं बैठ जाऊंगा, मैं ज्यादा टाईम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा साथी गुलाटी साहब, बोलने के लिए बहुत उतावला है। गुलाब सिंह जी कई बार हमको गवर्नर एड्रैस की डिस्क ान पर याद कर लेते हैं, हालांकि हमारा उसके साथ कोई ताल्लुम नहीं क्योंकि हमारी भी एक गवर्नमैंट बनी थी। वह आठ महीने की थी। बालक को भी पूरे 9 महीने पेट में रहने देते हैं लेकिन हमको तो 8 महीने में ही निकाल दिया था। वे यह कहते हैं कि डारकैस्ट पीरियड था। उससे पहले भगवत दयाल की गवर्नमैंट थी। वह तो बिल्कुल ही मौज़ की गवर्नमैंट थी। उसमें तो कोई डारकैस्ट का सवाल ही नहीं सोचते ? मैंबरों को उन दिनों में होस्टलों में ले जाना, दाएं, बाएं घुमाना, इतना रंगीन पीरियड हिस्टरी में आना

भाायद मुि कल है। वह बहुत चमकदार पीरियड था। यह ठीक है कि वे पोलिटीकली जो कुछ भी कहें, लेकिन जो हमारे वाला पीरियड था, उसके बारे में कभी अपोलोजटिक न हुआ हूं, न दिल्ली जाकर किसी लीडर के सामने अपोलोजैटिक बना हूं न ही आज हूं। उन पीरियड में हमने अपने लीडर को जिसको हम समझते थे कि यह आदमी कास्टीइज़्म का जहर फैलाता है, जिसने का ी तक के अंगोछे इकट्ठे कर दिए थे और जो इस तरीके से बोलता था और जो नान–कांग्रेस पालिसी पर अमल करता था, कांग्रेस पालिसी पर अमल नहीं करता था, उसके खिलाफ हमने रिवोल्ट करके, अपने कैरियर को आज़ादी ली। हालांकि हम कहते थे कि हमें पार्टी में बिठा लो, बिठा लो, – लेकिन वे नहीं माने। हमने रिवोल्ट किया और एक अन–डिज़ायरेबल आदमी को यहां से निकाल दिया जिसने एम0एल0एज़0 को होटलों में ले जाकार बदचलनी वगैरा की वजह से हरियाणा की सियासत में गन्द मचा दिया था। हमने अपनी गवर्नमैंट बनाकर उस चेयर के भाग्य से यह डिक्लेयर किया कि हमारी गवर्नमैंट बागी कांग्रेसियों की गवर्नमैंट है। एक बार जब पार्टी बनी तो उन्होंने जब मुझे यह कहा कि इस पर दस्तखत करो, तो मैंने कहा कि मैं तो कांग्रेसी हूं। भगवत दयाल को निकालने के लिए था जो कुछ भी था। मैंने कोई गलत बात नहीं की। गुलाब सिंह जी, अगर मेरे हलके बेरी में जाकर आप पूछें, तो पता लगेगा कि मैंने कहा था कि कोई मुझे वोट दे या न दे, मैंने मुनतखिब होते ही कहा था कि भगवत दयाल की चोटी में कील गाड़ दूंगा। हमने वोट ही इस काम के लिए ली

थी। जो हम कह कर आए थे, वह आकर पूरा किया। आकर कील गाड़ा। जो कहकर आए थे, वह पूरा किया। इस दफा यह कह कर आया था कि भई, कोई वोट दे या न दे, मैं तो इंदिरा बहन का नौकर हूं। मैं इस बात पर बड़ा फर्क समझता हूं और मुझे इसमें कोई भार्मिन्दगी नहीं है। कांग्रेस गवर्नमैंट का साथ दूंगा। किसी ने वोट देनी हो तो दे, न देनी हो, तो न दे।

श्री गणपत रायः स्पीकर साहब, जो व्यक्ति इस हाउस में मौजूद न हो और उसके बारे में इस प्रकार की भाशा बोली जाए, क्या यह उचित है ? अगर उचित नहीं है तो क्यों ने उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए ?

श्री अध्यक्षः वह लफ्ज़ क्या है जिस पर आपको एतराज़ है ?

श्री गणपत रायः पण्डित भगवत दयाल की चोटी में कील गाड़ दूंगा। वह ऐसा था वह वैसा था।

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज़।

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः जहां तक चोटी में कील गाड़ने का ताल्लुक है, यह बिल्कुल पार्लियामैंटेरियन लफ्ज़ है और यह पालिटीकल वर्ड है और मैं इस बात को फिनि ा कर चुका हूं। जहां तक होटलों में ले जाने का ताल्लुक है, वे एम0एल0ए0 बेचारे कल भी यहां गैलरी में बैठै थे ..... (व्यवधान) .....

सच्ची है या झूठी है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। अनपार्लियामैंट्री नहीं है। यह तो क्रिटीसिज़म है, चाहे सख्त हो या हार ा हो, लेकिन गुलाब सिंह जी, हमने तो वह काम किया था कि अगर कोई कद्र दान होता तो हमें पूजता। असली कांग्रेसी तो हम हैं, जो तुमको इस पोज़ी ान में ले आए और चौधरी बंसी लाल जैसा डायनेमिक लीडर नसीब नहीं हो सकता था। मैं आपको बताऊं कि अभी लोगों के मन में सारे आदमियों के मन में यह जंचा नहीं है, क्योंकि वह बहुत बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोलता। उसकी पर्सनैलिटी को सारे लोग जान नहीं पाए जो समझदार आदमी जान पाए हैं और जब हरियाणा की हिस्टरी लिखी जाएगी, तो लोगौं को पता लगेगा कि अगर भगवत दयाल की मिनिस्टरी न जाती तो हरियाणा ऐसे आदमी से महरूम रह जाता। अगर हम भगवत दयाल को नहीं निकालते तो हरियाणा को बंसी लाल नसीब नहीं होता। आज कहा जाता है कि हमारी सरकार जब बनी तो उसने कोई काम नहीं किया मैं कहता हूं जिस वक्त हमारी गवर्नमैं अ बनी अगर यह अपोज़ी ान वाले देवी लाल जैसे आदमी गवर्नमैंट की लैग पुलिंग न करते और हमारी गवर्नमैंट तीन–चार साल चलने देते, तो हम बताते कि हमने हरियाणा में कितना काम किया है। आज जो लोख चीखते हैं कि दौलता कहीं कांग्रेस में न आ जाए उनको पंजाबी ब्यूरोक्रेसी ने दबा रखा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हरियाणा की डिवैल्पमैंट में हम लोगों का जो कंट्रीब्यू ान रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है, हमने हमे ाा फुल को–ऑप्रे ान दिया है। दौलता ने भगवत दयाल को निकाला और

बंसी लाल के लिए रास्ता साफ किया। स्पीकर साहब इन लफ्ज़ों के साथ मैं वांईड–अप करता हूं।

श्री के0 एन0 गुलाटी (फरीदाबाद): माननीय स्पीकर साहब, आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे सामने है उस सिलसिले में मैं आपकी मारफत कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूं कि पिछले छह साल से हरियाणा के अन्दर चौधरी बंसी लाल की चीफ मिनिस्टरि ाप में जो स्टेबल गवर्नमैंट आई है उसने हद से ज्यादा काम किया है। हर सैक्टर में चाहे वह रोहतक का मैडीकल कालेज हो, अस्पताल हो, हिसार की ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुरुक्षेत्र की एजुके ान यूनिवर्सिटी हो और चाहे बड़ी–बड़ी नहरे हों, यह हरियाणा की मुंह बोलती तस्वीर है। हम तो इस गवर्नमैंट के बहुत म कूर हैं और दिल से यह महसूस करते हैं कि इस सरकार ने हरियाणा की तरक्की के लिए बहुत काम किए हैं और भविश्य में भी इस तरह से और तरक्की के काम होंगे। स्पीकर साहब, हर विधायक का यह फर्ज़ होता है कि वह अपने इलाके की तरक्की के लिए कुछ सुझाव दे, अपने इलाके की बात कहे। हमको जनता ने इसीलिए चुनकर भेजा है कि उस इलाके की तकलीफों को यहां रखें। एक विधायक का यह काम नहीं है कि आपस में ऊंची नीची बात कहें, या गाली दें, या जातिवाद की बात लेकर आपस में कुछ कहें। एक विधायक का सिर्फ काम है कि अपने

इलाके की दु:ख और तकलीफों को हाउस के सामन रखे। स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत कुछ सुझाव जनरल और कुछ अपने हलके के बारे में रखूंगा। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है कि फरीदाबाद में थर्मल प्लांट लगा है, मैं हरियाणा सरकार का बहुत ही म ाकूर हूं, लेकिन मैं सुझाव के रूप में इतना कहना चाहता हूं चूंकि वह थर्मल प्लांट फरीदाबाद में लगा है तो उसका ज्यादा फायदा फरीदाबाद के ज़मींदारों को दिन के टाईम में या रात के टाईम में दी जाए और फैक्ट्री के लिए भी ज्यादा बिजली दी जाए, ताकि आजकल जो वहां ले–आफ चल रहा है, वह दूर हो और मज़दूरौं को पूरे वेजिज मिल सकें। बिजली की कमी के कारण प्रोडक ान कम होती है और इस कारण से सरकार को टैक्सिज़ थोड़े मिलते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस थर्मल प्लांट की ज्यादा से ज्यादा बिजली फरीदाबाद को ही दी जाए। इस पावर को सैक्टर सात और बाईस की स्ट्रीट लाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। मैं महसूस करता हूं कि एक ही सैक्टर में कुछ बिल्डिंगज़ को बिजली मिल जाती और कुछ को नहीं मिलती है। इसके पीछे असलियत यह है कि वहां से ट्यूबवैल्ज़ और अस्पतालों की लाईनें जाती हैं जिनको बिजली ज़रूर देनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वहां पर अस्पतालों और टयूबवैल्ज की जो लाईनें हैं, उनको बिल्कुल अलग कर दें। जैसा कि मैंने भाुरू में कहा कि थोड़े से इलाके में बिजली चल रही होती है और दूसरे में बन्द होती है। जब हम बिजली बोर्ड से इस बारे में बात करते हैं, तो कहा जाता

है कि तार नहीं मिलते। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हरियाणा का बिजली बोर्ड जल्दी से जल्दी तारों का बन्दोबस्त करे और जिन लोगों के कनैक ानर पैंडिंग पड़ें हैं, उनको भीघ्र ही कनैक ान दिए जाएं। चाहे वे रेज़िडैंि ायल हों, चाहे कमि ायल हों। स्पीकर साहब, मैं एक जनरल बात आपकी मारफत सरकार से और कहना चाहता हूं कि आफिसिज़ में चाहे वह हरियाणा स्टेट के हैं, म्यूनिसिपल्टी के हैं, काम्पलैक्स के हैं और चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, सरकार को यह इंस्ट्रक ान्ज़ इ ू करनी चाहिए कि कोई भी एम्प्लाई दफ्तर के आईम में चाय नहीं पीएगा। आज चारों तरफ दफ्तरों में करप ान की बात की जाती है। मैं कहता हूं कि खाली कहने से करप ान खत्म नहीं होगा। इसके लिए कुछ करना होगा। यह कोई हंसी की बात नहीं है। पहली बात तो मैंने यह कही कि चाय पीने की मनाही कर देनी चाहिए कि कोई भी बहन दफ्तर के टाईम में स्वाटर नहीं बुनेगी। दफ्तरों में पूरी तरह से साइलेंस आब्जर्ब होगा। हर आदमी अपने काम से काम रखेगा। जो एप्लीके ान दफ्तर में आए, उसको डिस्पोज आफ करने का टाईम मुकरर्र होना चाहिए कि इतने टाईम के अन्दर उसका जवाब देना है, हां में या ना में। मुझे उम्मीद है कि करप ान का नामो–नि ाान नहीं रहेगा और आफिसिज़ में तेजी से काम चलेगा और इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि समय–समय पर आनरेबल मिनिस्टर साहिबान या हैड–आफ–दि डिपार्टमैंट बिना इत्तलाह दिए विज़िट करें सरपराइज़ चैक करें, कि कौन एम्पलाई अपनी सीट पर नहीं है, कैसा काम हो रहा है। स्पीकर साहब,

आपको जानकर खु ाी होगी कि फरीदाबाद में जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट के ऐम्पलाईज़ हैं, मुझे अपनी बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं उन ऐम्पलाईज़ के सी0सी0ए0 के सिलसिले में सैन्ट्रल मिनिस्टर से मिला और अब उनको सी0सी0ए0 सैंक ान हो गया है। मैं आपकी मारफत अपनी सरकार से भी अर्ज़ करूंगा कि जो स्टेट ऐम्प्लाईज़ हैं, उनको भी सी0सी0ए0 सैंक ान किया जाए। अगर हमारी सरकार इस काम में भी पहल करे तो बहुत अच्छी बात होगी। आज सो ालिज़म की बात बड़े जोरों से की जाती है। मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूं कि वह एक अच्छा काम यह करे कि कम से कम दो सौ रुपया तनखाह कर दे और अधिक से अधिक दो हजार रुपया तनखाह कर दे। जिसको दो हजार से ज्यादा तनखाह मिलती है उसको वह खजाने में दाखिल कर ले और सिर्फ एम्पलाई को दो हजार दे और जिस को दो सौ रुपए से कम मिलता है, उसको अपने खजाने से और दे।

स्पीकर साहब, मैं एक प्वांयट और कहना चाहता हूं कि पहले फरीदाबाद में एक नेहरू कालेज था जो अब बन्द हो गया है, उसका केस कोर्ट में चल रहा है लेकिन जो कालेज का फर्नीचर है, लाइब्रेरी है, कैमिकल्ज़ है उनको ताला लगा हुआ है और गुड्ज वहां सड़ रही हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार कोि ा ा करके उन गुड्ज को निकाल कर दूसरे कालेजों, स्कूलों को सप्लाई कर दे तो बड़ी अच्छी बात होगी।

15.00 बजे

स्पीकर साहब, अब मैं टैक्सिज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि जहां हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वहां पर मुझे अपने भाई चौधरी दल सिंह जी की बात याद आ गई। चौधरी दल सिंह जी ने दूसरी स्टेट्स का हवाला देते हुए यहां पर बहुत कुछ कहा है कि हरियाणा ने कोई खास तरक्की नहीं की है। लेकिन यह बिल्कुल फैक्ट्स हैं कि हरियाणा ने पिछले 6 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं जिसने कि हरियाणा को चार चांद लगा दिए हैं। दूसरी स्टेट्स में भी हमारी खूब प्र ांसा की जाती है। हमारी जितनी भी कमेटियां हैं, जब हम बाहर की स्टेट्स में जाते हैं और वहां की कमेटियों के मैंबर साहिबान हमारे भी आते हैं, तो वे हमें कहते हैं कि आपके हरियाणा ने चौधरी बंसी लाल जी की लीडर ाप में बड़ी तरक्की की है। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, यह फैक्ट्स हैं। हमारी कमेटियों के अन्दर हरेक पार्टी के मैंबर साहिबान होते हैं तो वे सभी इस बात के लिए आई विटनैसिज़ हैं, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। स्पीकर साहब, इसके आगे चलकर मैं ए0 जी0 आफिस के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं हमे ाा जहां भी जाता हूं, फरीदाबाद और चण्डीगढ़ कहीं भी, तो मैं अपने साइकिल पर जाता हूं। लोगों के कामों के लिए लोगों के कागज़ वगैरह उनसे लेकर आता हूं और फिर उनके घरों में पहुंचाता हूं और मैं किसी को भी अपने साथ होस्टल वगैरह में नहीं लाता हूं और न ही किसी को यह कहता हूं कि मेरे साथ चलो। मुझे ए0 जी0 आफिस में 50–50 बार जाना पड़ता है, कई किस्म के

केसिज़ होते हैं, किसी का पैं ान का केस होता है, किसी का जी0पी0 फण्डज़ का केस होता है। अगर ऐसे कामों के लिए एक एम0एल0ए0 बार बार जाता रहे तो कोई अच्छी बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पर कोई किसी की बात तक नहीं सुनता है। यह बात तो ठीक है कि हमारी सरकार का एकाउंट्स के मैटर में दखल देने का मतलब नहीं है, मेरी आप के द्वारा सरकार से यह प्रार्थना है कि ए0 जी0 आफिस में काम के र ा को देखते हुए उसे केवल आडिट वगैरह का काम सौंपा दिया जाये और यह जो पैन् ान, जी0पी0 फण्डज़, और दूसरे एकाउंटस के काम हैं, जिन से पब्लिक का ज्यादा ताल्लुक रहता है, वह मामले किसी दूसरे विभाग को सौंप दिये जाएं जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इससे आगे मैं लेबर डिपार्टमैंट के बारे में भी दो भाब्द कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में सिर्फ एक ही लेबर कोर्ट है, एक लेबर ट्रीब्यूनल है, और जिसका एक ही जज है। मैं चाहूंगा कि लेबर कोर्ट, लेबर ट्रीब्यूनल की तादाद एक से बढ़ा दी जाए और कम से कम एक लेबर आफिसर और दो लेबर इंस्पैक्टर और दिए जाएं। इसके साथ–साथ किसान को, ज़मींदार के लिए जहां पर ड्राट एरिया है, बिजली नहीं है, कोई न कोई रिलीफ भी दिया जाए। जो इंडस्ट्रीयल एरियाज़ हैं, जैसे फरीदाबाद, यमुनानगर और बहादुरगढ़, वहां पर कम से कम लेबर क्लास के लिए कोई न कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए, जिससे कि उनको राहत मिल सके।

सरकार उनके लिए सस्ते भाव पर डिपोज़ खोले ताकि वे लोग सस्ते भाव पर सरकारी डिपोज़ से गेहूं, आटा वगैरह ले सकें। अगर सरकार यह दो चीजें कर दे, तो जो थोड़ी बहुत कमी लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसा करने से यह सरकार उनकी सभी दिक्कतों को दूर कर देगी।

स्पीकर साहब, इससे आगे पुलिस डिपार्टमैंट के मुताल्लिक भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। ला ऐंड आर्डर इस हरियाणा में वाकई अच्छा है। जो अच्छी बातें होंगी उनकी तो हम अव य ही तारीफ करेंगे और करनी भी चाहिए लेकिन जिन भाईयों की आदत ही बन गई है कि क्रिटीसिज़म ज़रूर करना है, उन्होंने तो क्रिटिसिज़म करना ही है। हमें तो सरकार की अच्छी बातों को कहने में कोई गरेज़ नहीं है, अगर यह कह दिया कि पिक–पाकिट गुलाटी साहब के 400 रुपए ले गया और जो ी जी के कहने पर एक ही रपट में वह पैसा वसूल हो गया तो इससे ज्यादा और ला ऐंड आर्डर की अच्छी स्थिति क्या हो सकती है कि एक ही कम्पलेंट पर पैसा रिकवर हो गया। इससे आप खुद ही अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में ला ऐंड आर्डर की स्थिति क्या है ? मैं सिर्फ अपनी सरकार से यह कहूंगा कि फरीदाबाद में इस वक्त एक ही पुलिस स्टे ान है। वहां पर केसिज़ की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर एक दूसरा पुलिस स्टे ान भी खोल दिया जाए और उस एरिया को रि–डिवाइड कर दिया जाए।

इसके साथ–साथ झुग्गी झोंपड़ी वालों के बारे में भी प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है उनकी एकम्मोडे ान के लिए भी सरकार को कुछ न कुछ प्रबन्ध करना चाहिए।

इससे आगे चलकर मै। एजुके ान के बारे में कहूंगा कि इस वक्त सारे हरियाणा में कोई 70–72 मदर टीचर्ज़ हैं, पांच साल से वे पार्ट टाईम काम कर रही हैं, जब स्ट्राइक हुई थी उस वक्त भी वे उसमें भाामिल नहीं हुई और न ही इस्तीफा ही दिया बल्कि उन्होंने गवर्नमैंट की फुल टाईम मदद की है। फुल टाईम काम करके पार्ट टाईम के पैसे लिए हैं। तो मेरी एजुके ान मिनिस्टर साहब से और अपनी सरकार से पुरजोर रिक्वैस्ट है कि जो पिछले पांच साल से ही तरह काम कर रही है, उनको फौरन रैगुलराइज कर दिया जाए और इसके साथ ही जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी व दूसरी यूनिवर्सिटीज वगैरह ने वहां पर कोरैस्पौंड कोर्सिज़ खोल रखे हैं, उसी प्रकार से हमें इधर फरीदाबाद के अन्दर ऐसे कोई कोर्सिज का इन्नजाम करना चाहिए। फरीदाबाद के अन्दर व 22 सैक्टर के अन्दर नाइट ि ाफ्ट खोल कर एम0ए0 या दूसरी क्लासिज़ के लिए सैंटर खोल देने चाहिएं ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें। अगर सरकार ऐसा कोई इन्तज़ाम कर देगी तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि सभी जगह पर मिडल स्कूल की जो परीक्षाएं होती है, उन सब का एक ही तरीका होना चाहिए।

स्पीकर साहब, इससे आगे हाई करैक्टर के सम्बन्ध में भी कहूंगा कि ने ान का हाई करैक्टर होना चाहिए। अगर एजुके ान डिपार्टमैंट में ऐसा कर दें कि जब कभी भी कोई फंक ान हो, कोई प्रोग्राम हो, तो उस वक्त नै ानल सौंग्ज़ के बजाए कोई दूसरा सौंग न हो, तो इससे भी ने ान के करैक्टर पर जरूर असर पड़ सकता है। इससे आगे मैं हरियाणा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जो प्रावीडैंट फण्ड का कार्यालय है, जिसको सैन्ट्रल गवर्नमैंट चलाती है अगर हरियाणा सरकार अपना आफिस अलग कर दे तो इससे काम और अच्छी तरह से निपट सकता है। यहां पर यह कह बगैर भी नहीं रहूंगा कि सो ालिज़म को तेजी से करने के लिए अगर प्रोपर्टी सीलिंग का बिल जल्द आ जाए, तो अच्छी बात है। इससे आगे स्पीकर साहब, मैं न ोबन्दी के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है, यह देख लिया जाए कि हाउस का कोरम भी पूरा है ?

श्री अध्यक्षः हां, पूरा है।

श्री के0एन0 गुलाटीः तो मैं न ाबन्दी के बारे में कह रहा था क्योंकि मैं गुरु नानक मि ान को मानता हूं और सियासी तौर पर मैं गांधी जी का पक्का चेला हूं क्योंकि वह भाराब को बन्द करना चाहते थे। यह बात तो ठीक है कि सरकार को इससे

काफी रेवैन्यू आती है। मेरा तो केवल हरियाणा सरकार को एक सुझाव है कि इस भाराब को हरियाणा स्टेट में बन्द कर दें, और इसकी जगह पर डिवैल्पमैंट टैक्स लागू कर दें तो भी सरकार को काफी इन्कम हो सकती है और यहां पर एक काम और यह भी कर दें कि सिनमाज़ को नै ानेलाइज कर दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाएगा, तो वहां पर कोई ऐसी–वैसी फिल्म, कोई ऐसा वैसा गाना बजाना नहीं होगा, जिससे ने ान के करैक्टर के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। मुझे आ ाा है कि सरकार मेरे इन सुझावों पर ज़रूर गौर करेगी।

स्पीकर साहब, एक और बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे फरीदाबाद में एक गोल्फ क्लब है, उसके पास 100 एकड़ के करीब जमीन है, जो कि लीज़ पर दी हुई है, मैं आपकी मारफत अपनी सरकार से और अपने योग्य चीफ–मिनिस्टर साहब से यह कहूंगबा कि उस लीज़ को खत्म किया जाए और उस जमीन के ऊपर कोई कालेज, स्कूल वगैरह की बिल्डिंग बनाई जाएं या वहां पर गरीब लोगों के रहने के लिए मकान बनाए जाएं तो सरकार की बड़ी कृपा होगी। आगे चलकर मैं फरीदाबाद की वाटर सप्लाई स्कीम का भी जिक्र करना चाहता हूं। अगर यहां पर मच्छर का जिक्र न करूं तो ठीक नहीं रहेगा, हंसने वाली बात नहीं है। वहां पर बहुत बड़ा–बड़ा मच्छर है, स्पीकर साहब, अगर हम मुंह ढांपते हैं, तो दम घुटता है, अगर बाहर मुंह निकालते हैं, तो मच्छर काटता है, मतलब यह है कि

वहां पर बहुत बुरी हालत है। लेकिन यह जो कमियां हैं, मेरा विधाययक के नाते फर्ज़ बनता है कि मैं उनको सरकार के नोटिस में लाऊ।। तो मैं कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद में मच्छर खत्म करने और वाटर सप्लाई का पूरा प्रबन्ध करने के लिए एक क्रै ा प्रोग्राम बनाया जाए और वहां की जो सैनीटे ान की हालत है, उसे सुधारा जाए। इसी लिंक में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सैनीटे ान के सिलसिले में एक बाधा जो आती है, वह यह है कि फरीदाबाद में पैकेज डील के मुताबिक एक साइड में कुछ ज़मीन तो सैन्टर के अण्डर आती है और दूसरी साइड में स्टेट की लैण्ड है, जिसकी वजह से वहां सैनीटे ान के काम ठीक ढंग से नहीं हो पाते, क्योंकि सीवरेज़ वगैरा ले करने, वाटर पाइप लाइन ले करने और दूसरी ऐसी बातें करने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करता हूं कि वह इस पैकेज डील को खत्म करके वह जो सैन्टर की लैण्ड है, उसे कब्जे में लेकर इस सैनीटे ान के काम को ठीक ढंग से करवाएं। स्पीकर साहब, हमारी हरियाणा की पार्लियामैंट की सीटें 9 कीजाय 10 हो गई हैं। और गुड़गांवा वाली सीट को फरीदाबाद के नाम किया जा रहा है। मैं इस बात से खु ा हूं और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इसके साथ–साथ यह निवेदन करूंगा कि पार्लियामैंट की सीट तो फरीदाबाद के नाम से हो गई है, तो इसके साथ ही वह यह भी कर दें, कि 26 जनवरी वाले दिन फरीदाबाद को जिला डिक्लेयर कर दें। अफवाह तो है कि उसे जिला बनाया जा रहा है और 26 जनवरी को इसका ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अगर वह इस

अफवाह को अमली रूप दे दें, तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी और मैं उनका म ाकूर हूंगा। उसे ज़िला बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, सारा स्टाफ तो है सिर्फ ऐस0पी0 लगाने की ज़रूरत है और डी0सी0 लेवल का अफसर तो पहले ही वहां मौजूद है, क्योंकि वहां के कम्पलैक्स के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वह डी0सी0 लैवल के हैं और डी0सी0 का काम उनको सौंपा जा सकता है। एक बात मैं फरीदाबाद के ओवर ब्रिज के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी रेलवे बोर्ड के मैंबरान से बात हुई है और वह इस काम के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि अगेर कम्पलैक्स वाले और अर्बन एस्टेट वाले पैसा दे दें तो एक साल के अन्दर अन्दर वह ओवर ब्रिज बना देंगे। तो मेरी इस बारे में अर्ज है कम्पलैक्स के पास काफी पैसा है जो उसने लोगों से टैक्सों की भाक्ल में लिया हुआ है और वह जनता का ही पैसा है। इसी तरह से अर्बन एस्टेट वालों ने भी जमीन लोगों की एक्वायर करके फिर उसे बेच कर काफी पैसा ले रखा है और ये दोनों बाडीज़ इस काम कये लिए पैसा दे सकते हैं, आखिर यह जनता का ही पैसा है और ओवर ब्रिज जनता के फायदा के लिए ही बनना है हसलिए सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब के आर्डर करने की जरूरत है, पैसा फौरन आ जाएगा। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह कम्पलैक्स को और अर्बन एस्टेट वालों को आधा आधा पैसा इस काम के लिए देने की इजाजत दे दें, ताकि वहां का ओवर ब्रिज बन जाए। फिर फरीदाबाद का जो बी0के0 हस्पताल है, उसकी बहुत पुरानी

बिल्डिंग है और वह सिर्फ 250 बैड का हस्पताल है। अव्वल तो गाल्फ क्लब की जो सौ एकड़ जमीन वहां पर पड़ी है, उसे लेकर वहां पर एक नया 500 बैड का हस्पताल बनाया जाए, क्योंकि वह जगह फजूल पड़ी है। वैसे बी0के0 हस्पताल के पास भी उसकी काफी जगह खाली पड़ी है, और इस हस्पताल को एक्सटैंड किया जा सकता है। इसलिए मेरी अर्ज़ है कि जैसे भी हो इस हस्पताल को 500 बैडज़ का बनाया जाए। इस हस्पताल के साथ एक टी0बी0 बार्ड को बी0के0 हस्पताल से अलैहिदा कर दिया जाए और उसके लिए अलैहिदा मैडीकल अफसर लगा दिया जाए, जो उसका इंचार्ज हो, ताकि टी0बी0 पे ांट्स को तकलीफ न हो। इसके अलावा फरीदाबाद कम्पलैक्स में हैल्थ अफसर नहीं है, अगर वहां हैल्थ अफसर भेज दिया जाए, तो बहुत मेहरबानी होगी। इसके अलावा मैं अर्ज़ करता हूं कि यहां हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने और दूसरे मिनिस्टर साहिबान ने मुझे पाली रोड़ के बारे में अ योरैंसिज़ दी हैं, जो कि एप्रूव्ड कालोनीज़, मदर टीजर्ज़ और विडो होम्ज़ की अलाटमैंट के बारे में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अ योरैंसिज को पूरा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि फरीदाबाद में लोकल बस सरविस दुगनी कर देंगे। यह बहुत अच्छी बात है और मैं उनसे निवेदन करात हूं कि इन अ योरैंसिज़ को भीघ्र ही पूरा कर दिया जाए और इसके लिए मैं उनका और हरियाणा सरका का बहुत म कूर हूंगा। अगर स्पीकर साहब हरियाणा सरकार फरीदाबाद के लिए जल्दी बसें नहीं दे सकती, तो वहां का काम्पलैक्स मिनी बसें चलाने के लिए तैयार

है, और उन्होंने इसके लिए एप्लाई भी कर दिया है। अगर सरकार इस बात की इजाज़त दे दे तो लोगों को बहुत आराम मिलेगा। –– (घंटी) –– एक बात मैं ट्रांसफर्ज़ के बारे में कहना चाहता हूं और इस बारे में यह सुझाव देना चाहता हूं कि ट्रांसफर्ज़ सिर्फ अप्रैल और मई के महीनों में ही जाएं, और बाकी दस महीने तक कोई ट्रांसफर्ज़ की बात न की जाए, इस बारे सख्त आर्डर कर दिए जाएं। इससे यह होगा कि न तो लोग हमारे पीछे–पीछे भागेंगें, और न हम ही मिनिस्टर साहिबान के पीछे भागते फिरेंगे, और उनका समय जाया नहीं होगा। लेकिन इसके साथ मे। एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाए, उनको वहां रैंजीडैं ियल अकोमोडे ान ज़रूर मिलनी चाहिए, और पूरा इन्तज़ाम किया जाना चाहिए, ताकि उनको वहां रहने की दिक्कत न हो –– (घंटी) –– बस जी, मैं एक बात कह कर खत्म करता हूं। एक सौ गांव की वाटर सप्लाई और सीवरेज़ की स्कीम के बारे में बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि उस गांव की पंचायत तो खत्म हो गई लेकिन उस गांव ने इस कम्पलैक्स को इस काम के लिए दस लाख रुपया दिया हुआ है और इस बारे में पता लगा है कि पब्लिक हैल्थ वालों के पास एस्टीमेट आया हुआ है। तो मैं पब्लिक हैल्थ वालों से कहूंगा कि वह यह कागज़ जल्दी निकाल दें, ताकि कम्पलैक्स यह काम कर सके। एक इसी गांव ने वहां भाम ाान घाट के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन उस गांव के एक आदमी की बात मान ली गई और सारे गांव की बात को नहीं माना गया। मेरा सुझाव है कि इस बारे

में जो उस गांव ने अपील की हुई है, उसे माना जाए, और जो बात सारा गांव कहता है, उसे माना जाए। –– (घंटी) ––जो टाउनज़ में रोड़ज़ बनती हैं और विलेज लिंक रोड्ज़ बनती हैं, वह बहुत जल्दी टूट जाती हैं, उनके रोड़ बर्मज़ टूट जाते हैं और उसके बीच में कट पड़ जाते हैं। इस बारें मे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे फरीदाबाद में जो आर्य समाज के सामने रोड़ बनी हैं, उनकी मिसाल को देखा जाए, और उसके मुताबिक रोड़ज बनाई जाएं, और उनकी प्लानिंग की जाए, ताकि रोड़ज़ की बीच कट न पड़ें और उनके बमर्ज़ न टूटें। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक भाई ने कहा था कि उनके चार मैंबर हैं और उनकी दूसरी पोज़ी ान है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर नम्बर के हिसाब से देखा जाए तो उस हाउस में हम इंडीपैंडेंट्स का दूसरा नम्बर पड़ता है, क्योंकि हम 15/16 हैं, इसलिए हमें हर बात में टाईम में व्हेटेज़ मिलना चाहिए, न कि इन तीन चार मैंबरान को। हम भी गांधीवादी हैं, और प्रो–गवर्नमैंट हैं, इसमें भाक़ नहीं है। इन अल्फाज़ के साथ मैं इस गवर्नर एड्रैस की ताईद करता हूं।

श्री राम धारी गौड़ (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण के बारे में जो धन्यवाद का प्रस्ताव गुलाब सिंह जी जैन ने सदन के सामने पे ा किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में हरियाणा के प्रत्येक निवासी की भावनाओं की सही

तौर पर तरजमानी की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हरियाणा के हर आदमी को रोटी मिले, कपड़ा मिले, रहने के लिए मकान मिले, चिकित्सा मिले और अच्छी ि ाक्षा मिले। राज्यपाल महोदय ने बताया है कि हमने ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करने के लिए क्या–क्या साधन जुटाए हैं। अन्न पैदा करने के लिए सबसे बड़ा साधन पानी है। आप जानते हैं कि हरियाणा के पास सिवाए यमुना नदी के पानी के या फिर कुछ भाखड़ा से पानी मिलता है और कोई साधन पानी का नहीं था जैसा कि राज्यपाल महोदय ने भी बताया है। इस मौजूदा सरकार ने आगमैंटे ान कैनाल बनाई और इसके जरिए पानी को आगे उन इलाकों में ले जाते हैं, जहां पहले पीने का पानी भी नहीं मिलता था, फसलों को पानी देने की तो बात ही क्या करनी है। वह पानी जो जमीन के अन्दर बेकार पड़ा था और किसी काम नहीं आता था, बल्कि सेम भी पैदा करता था, उसे नल कूप लगाकर बाहर निकाल कर एक पक्की नहर बनाकर उसमें डालकर आगे खु क इलाकों में ले जाया गया। आप देखें यह कितना बड़ा काम था। पहले कहावत यह थी कि पानी नीचे को बहता है लेकिन हरियाणा में पानी ऊपर को ले जाया गया, लेकिन फिर भी कुछ भाई कहते हैं कि हरियाणा में कोई काम नहीं हुआ। ये पुरानी आंकड़े हैं, अगर इनको आए साल दोहरा दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। यही नहीं किया, हमने पानी उपलब्ध किया है और इसके अलावा जो पानी मौजूद था, उसको बचाने के लिए साधन भी जुटाए क्योंकि कच्ची नहरों की वजह से काफी पानी जमीन में रिस जाता था और यह पानी जाया जाता

था, इसको बचाने के लिए हमारे इंजीनियर्ज़ ने उपाय किए। उन्होंने बताया कि मोघे से निकलने के बाद पानी जब खाल में जाता है तो खाल कच्ची होने के कारण पानी ज़ाया हो जाता है। दरियाओं से नहरों के ज़रिए जो पानी हम खेतों में ले जाते हैं, जमींदार के खेत में पहुंचते–पहुंचते एक चौथाई पानी खालें पक्की न होने की वजह से ज़ाया हो जाता है। मौजूदा सरकार ने यह कोि ा ा की कि यह पानी जाया न जाए, जिसका राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में इ ाारा भी किया है कि सरकार ने 1800 किलोमीटर लम्बे खाले पक्के किए, जिनकी कुल संख्या 600 है। स्पीकर साहब, जो पानी जाया होता था .....

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, कोरम पूरा ही नहीं है। 11 मैंबरों का कोरम है, लेकिन यहां पर 10 बैठे हैं।

श्री अध्यक्षः कोरम 10 का है including myself. मेरे समेत 11 बैठे हैं।

श्री राम धारी गौड़ः मेरे भाई चौधरी दल सिंह जी ने दिल खोल कर बिजली बोर्ड को कोसा और कहा कि घटिया खम्भे लगा दिए, पैसा जाया हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एफिि ाएंसी बिजली बोर्ड में है, जो अहसान बिजली बोर्ड ने हरियाणा के ऊपर किया है, उसको हरियाणा भुला नहीं सकता। मुझे याद है उटाकामंड में पावर मिनिस्टर्ज़ की कान्फ्रैंस हुई थी, और उसमें प्रस्ताव रखा गया थ। और मीटिंग में कहा गया था कि

प्रत्येक स्टेट 1980 तक कम से कम 50 प्रति ात गांवों में जरूर बिजली दे दे लेकिन हम 6 महीने के बाद ही हर एक गांव को बिजली देने वाले थे। जब उन्होंने सुना कि हरियाणा में हर एक गांव में 6 महीने के बाद बिजली पहुंच जाएगी, तो उनको ताज्जुब हुआ और वे यह समझते थे कि भाायद यह गप्प है। लेकिन ठीक छः महीने के बाद बिजली पहुंच गई। उस वक्त जो बिजली का सामान लिया गया था, अगर उसको आज लें तो एक चौथाई सामान आना था। आप देखें कि हमको कितना फायदा हुआ है ? अभी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में बताया कि हमारी पैदावार प्रति हैक्टेयर 893 के0जी0 से बढ़ कर 1539 के0जी0 हो गई है। यह वैसे ही नहीं पहुंची, इसके लिए प्लानिंग की गई है, साधन जुटाए गए हैं। 1 लाख 39 हजार टयूबवैल हो गए हैं। क्या इन टयूबवैल्ज़ का पानी नहाने के काम आता है ? उनका पानी कहां गया ? खेतों में इस्तेमाल हुआ, उससे पैदावार बढ़ी। आगमैंटे ान का पानी, पक्की नहरे बनाकर जो पानी बचाया गया, वह कहां गया, नहाने के काम नहीं आया, वह खेतों में गया, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ी। अच्छा बीज दिया गया, खाद दी गई, हर एक ढंग से किसान को फायद पहुंचाया और साधन जुटाए। मैं समझता हूं कि बिजली बोर्ड पर यह आक्षेप लगाना निराधार है। मेरे विचार में इनको इसका फोबिया हो गया है कि कोई बात हो, सरकार की बुराई की जाए, चाहे कोई काम सरकार करे, चाहे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड करे, बुराई करना इनका ध्येय है। मुमकिन हो सकता है, चेयरमैन से उन पर कोई ज्यादती हो गई

हो, लेकिन उस जाती बात को, पर्सनल बात को लेकर अच्छे कार्यों पर, किए कराए पर पानी नहीं फेरना चाहिए, यह गलत बात है। इतनी अच्छी प्लानिंग हुई है, इससे ज्यादा और क्या प्लानिंग हो सकती है ? जिस स्टेट के साधन थोड़े हों उसमें इससे ज्यादा प्लानिंग और क्या हो सकती है। 1967 के बाद जब पहली कैबिनेट का पहला इजलास हुआ तो यह बात सामने आई कि डिवैल्पमैंट कैसे की जाए ? कैबिनेट में यह बात आई कि हमारे साधन इतने कम हैं कि हम मु कल से मुलाज़िमों को सिर्फ तनखाह दे सकते हैं। इतना ही पैसा है, यह 1967 की बात है। जिस स्टेट के पास इतने कम साधन थे कि मुलाजिमों का तन्खाह न दे सके, आज वही स्टेट हर एक गांव में बिजली दे रही है। घर–घर में बिजली पहुंचा दी, कारखाने लगे और पैदावार बढ़ी। आप जानते हैं कि हम खाने के लिए एक लाख टन अनाज सैन्टर से मांगते थे, लेकिन आज हम अपना भी काम चलाते हैं और सैन्टर को भी देते हैं। पहले सात लाख टन दिया, उसके बाद 5 लाख टन दिया, बावजूद इसके कि हमारे ऊपर कई आफतें आई। आप जानते हैं कि ठंडी हवा चली, जिसकी वजह से उपज कम हो गई है, लेकिन बावजूद इसके, हमने काफी अनाज सैन्ट्रल पूल में दिया। लेकिन ये कहते हैं कि कुछ है ही नहीं, छोटी मोटी बात को लेकर कभी कहते हैं, यह हो गया, वह हो गया, अरे जितने ज्यादा काम होंगे, उतनी ही खामियां होंगी, जितनी मांग बढ़ेगी, तो काम बढ़ेगा, और अगर काम बढ़ेगा, तो खामियां बढ़ेगी। जो काम नहीं करेगा, उस पर क्या आक्षेप लगेगा ? कई भाईयों ने कहा कि 9 महीने की

गवर्नमैंट आई थी, जिसने लिफाफों में अनाज बिकवाया था। लिफाफों में अनाज वहां बिकता है, जहां अनाज की कमी होती है, लेकिन जहां अनाज की ज्यादती होगी, वहां अनाज बोरियों में डलता है, लिफाफों में नहीं। मुमकिन है, अगर उनका राज रहता, तो लिफाफों में अनाज बिकना था लेकिन यहां तो टनों में, क्विंटलों में चलता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक आदमी को काफी मात्रा में अनाज मिले, हर एक आदमी को रहने के लिए मकान मिले, हर एक आदमी को पहनने के लिए कपड़ा मिले, हर एक आदमी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। मुझे याद है, गोहाने में प्राइवेट डाक्टरों की दुकानें थी, वे खूब कमाते थे। जब वहां पर हस्पताल बनाया गया, तो वे कहते हैं कि आपने क्या कर दिया, हमारा काम ही बन्द हो गया क्योंकि जहां अच्छा इलाज होगा, जहां मुफ्त सुविधा मिलेगी, लोग वहां पहुंचेंगे। अगर लोगों को चिकित्सा की मुफ्त सुविधा मिल जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, लेकिन इन भाईयों को इन कामों में दुःख होता है। ये अपने ज़ाती फायदे की बात करते हैं, जनता के भले की बात नहीं करते। यहां हाउस में दिखाने के लिए बात करते हैं, ताकि लोगों को कह सकें, कि हमने वहां यह बातें कहीं। गलत कहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कई कमियां होती हैं, आदमी बड़ी कोि ा ा करता है, लेकिन फिर भी उसमें कमियां रह जाती हैं। अगर ऐसा है, तो उन कमियों को किसी बेसिज़ पर नोटिस में लाएं, लेकिन सब कामों को मिथ्या कहना कि कोई बात ही नहीं है, यह ठीक नहीं है। कभी यह कहते हैं कि हमारी प्रधान

मन्त्री रोहतक में आई और यह गप्प मारी कि इतने आदमी लाठियों से जख्मी हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां मौजूद था, ऐसी कोई बात वहां नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, जहां काम अच्छा होता है, वहां कुछेक लोगों को जलन हो जाया करती है। हरियाणा में काम बढ़िया हो रहा है। यहां ही नहीं हिन्दुस्तान भर में हमारी प्राईम मिनिस्टर बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। आज जन–साधारण के लिए, छोटे आदमियों को ऊंचा उठाने के लिए, समाजवाद लाने के लिए बड़े–बड़े मगरमच्छों को जाल में फंसाने के लिए बहुत काम हो रहा है ? यहां ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। समाजवाद वहीं आता है जहां ऊंच नीच का भेदभाव कम हो, जहां छोटे–बड़े का सवाल कम हो। यह छोटे–बड़े का सवाल क्या है ? इसका मतलब यह है कि यदि किसी की आमदनी ज्यादा है तो उस पर थोड़ी सी पाबन्दी लगाई जाए और जिसकी कम है, उसको थोड़ा ऊंचा उठाया जाए। यह है समाजवाद। हमारी प्राईम मिनिस्टर साहिबा चाहती है कि दे ा में उन्नति हो, दे ा में समाजवाद आए। हरियाणा सरकार भी उसी नक ो कदम पर चल रही है। जो पिछड़े इलाके थे वहां इसने पानी दिया। कई जगह जहां कोई पहुंचता नहीं था, जिनको पता नहीं था कि सरकार क्या होती है, उन गांवों में सड़कें गई, बसें चलती हैं, दूसरी सहूलियतें पहुंची हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है ? जिस प्रान्त में साधन थोड़े हों, उसमें इतना काम हो जाना, स्पीकर साहब कम प्र ांसा की बात नहीं है। यह सिर्फ यहीं की ही बात नहीं है। आप किसी प्रान्त में जाईये, हरियाणा की प्र ांसा होगी, हरियाणा का नाम आप सुनेंगे।

वे कहेंगे कि हरियाणा में बड़ी डिवैल्पमैंट हुई, बड़ा काम हुआ। जिस इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की ये यहां नुक्ताचीनी करते हैं उसके बारे में दूसरे प्रान्त वाले कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम इसने किया है। स्पीकर साहब, मुझे एक बहुत पुरानी बात याद है। कोई तीस चालीस साल पुरानी बात होगी। रोहतक में मेहर सिंह नाम का एक भजनी था। वह कहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब झोंपड़ी में बुढ़िया लट्टू लगा कर चर्खा कातेगी। आज आप कहीं चले जाइए। आप देखेंगे कि झोंपड़ियों में सचमुच लट्टू लगे हुए हैं। आज वहां बिजली की रो ानी है। उसको तो एक ख्याल था, एक स्वप्न था,लेकिन आज वह पूरा हो चुका है। जो बात वह 40—50 साल पहले कहता था, आज वह हकीकत है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद राज्यपाल महोदय ने जो बातें कहीं, मजदूरों को मकान देने की वह भी बहुत सराहनीय है। मजदूरों को कौन मकान देता था ? मजदूर तो झुग्गियौं में रहते थे, काम करते थे उनका कोई ठिकाना ही न थां कोई दरखत के नीचे सो गया, कोई कहीं सो गया और कोई कहीं पड़ गया, लेकिन अब यह सरकार फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत आदि जगहों पर कालोनियां बना रही है। आज मजदूरों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। उनमें फ्ल ा सिस्टम हैं, बढ़िया कमरे हैं, जिनके बारे में उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था।

इसी ढंग से ि ाक्षा के बारे में आप देखिए। मुझे याद है कि जिस वक्त मैं पढ़ता था कोई कालेज हरियाणा में नहीं था।

मैं पढ़ने के लिए दिल्ली गया। रोहतम में इंटरमीडिएट कालेज होता था जहां कि आज लड़कियों का भी कालेज बन गया है। जिन गांवों में प्राईमरी स्कूल नहीं होते थे, वहां भी आज कालेज हैं। कितना विस्तार हुआ है। ि ाक्षा का हर गांव में यह आत जानते हैं, आपको पता है। पहले यदि कोई लैटर गांव में पहुंच जाता था तो लोग लैटर पढ़वाने के लिए पटवारी के पास जाते थे लेकिन आज घर घर में तीन तीन, चार चार बच्चे पढ़े लिखें हैं।

फिर स्पीकर महोदय, इन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग जबरदस्ती करते हैं। अब बताओं कि इसमें भी कोई तुक है 75 लाख की आबादी से बढ़कर अब हमारी आबादी एक करोड़ 13 लाख की हो गई है। आबादी तो बढ़ रही है लेकिन जमीन बढ़नी नहीं है। जमीन इतनी ही रहेगी। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि साधन कम हो गए लेकिन दूसरी तरफ दूसरी तरह की बातें करते हैं। बताओ आमदनी आएगी कहां से ? फैमिली प्लानिंग कितना बढ़िया काम है लेकिन उसमें भी मुखालिफत करने का इनको फोबिया हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में जो बातें कहीं हैं, उनके द्वारा उन्होंने सही मायनों में, जन–साधारण की, आम हरियाणवी की जो आ ाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी तर्ज़मानी की है। ऐसा मालूम होता है कि वैद्य जिस तरह से नब्ज देखकर मरीज की बीमारी बता देता है और यह भी बता देता है कि उस बीमारी का इलाज क्या है, उसी

तरह से राज्यपाल महोदय ने प्रत्येक हरियाणवी की नब्ज पर हाथ रखकर उनकी जो बीमारियां हैं, आ ाए हैं आकांक्षाएं हैं, उनकी तर्जमानी की है। इस अभिभाशण के द्वारा अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने हमारी जो मौजूदा सरकार है, उसकी नीति बताई है। हमारी सरकार समाजवाद लाना चाहती है, यह वैलफेयर स्टेट बनाना चाहती है, लोगों का रहन–सहन ऊंचा करना चाहती है। उनकी तकलीफें दूर करना चाहती हैं। इसके बावजूद भी आपने देखा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा। मैं समझता हूं कि हमें राज्यपाल महोदय का भुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें सही रास्ता बताया है, हमारा उत्साह बढ़ाया है। इन भाब्दों के साथ, स्पीकर साहब, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाशण का समर्थन करके बैठ जाता हूं।

मलिक सतराम दास बतरा (कलानौर) : माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय का अभिभाशण अति विचार ील, अति प्रगति ील और बहुमुखी उन्नति का प्रतीक है। उन्होंने अपने अभिभाशण में हमारा मार्ग द र्ान किया है। यह ठीक है कि दे ा में आर्थिक संकट है, आर्थिक क्राइसिज है, लेकिन यह बात भी ठीक है कि आर्थिक संकट तो सारे संसार में ही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर नहरें नहीं हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, वहां पर ड्राट हैं लेकिन इस दुर्भिक्ष के काल में भी अपनी सरकार की तरफ से रा ान आदि का प्रबन्ध बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया।

डिपोज आदि सारे ठीक चल रहे हैं। इन चीजों का डिटेल में वर्णन तो मैं बाद में करूंगा क्योंकि सबसे पहले मैं उस मुख्य विशय को लेना चाहता हूं जिसकी वजह से कुछेक इंडस्ट्रीज का काम और ऐग्रीकल्चर का काम धीमा पड़ा हुआ है। वह है इलैक्ट्रिसिटी। इलैक्ट्रिसिटी कहीं सें इम्पोर्ट नहीं होती है, इलैक्ट्रिसिटी तो जैनरेट होगी जब दरियाओं में पानी होग। यदि हमें बिजली उपलब्ध अच्छी मात्रा में हो जाए, तो सारा काम ठीक चलेगा। लेकिन फिर भी मै। उस बोर्ड की सराहना करता हूं जिसने इस बिजली के काम को ठीक ढंग से, बड़े कन्ट्रोल के साथ चलाया हुआ है। अभी कल के भाशण में हमारे एक माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह जी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर बड़ा प्रहार कर रहे थे। मैं नहीं समझता क्या बात है ? सन् 1968 से, जबसे मैं इस हाउस का सरस्य बनकर आया हूं, मैं यह देख रहा हूं कि कभी तो वे खम्भों की बात करते हैं, कभी लाईन लौसिज़ की बात करते हैं, कभी बहुत बड़ा कर्ज़ा हो गया है, इसकी बात करते हैं और कभी करप ान की बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कल का जो उनका भाशण था, उसको अगर सक साल पहले इसी विशय पर दिए हुए भाशण से मिलाया जाए, तो उसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। उसका हरफ हरफ आज के इनके भाशण से मिलेगा। भले ही आप उसे निकाल कर देख लीजिए। सेम भाशा, सेम ही भाशण इनका हमे ाा चलता है। इतनी बहुमुखी प्रगति होने पर भी इनको कुछ नजर नहीं आता। ऐग्रीकल्चर साईड को ही ले

लीजिए। बहुत अच्छे–अच्छे बीज निकाले गए हैं। इरीगे ान साईड में अगर देखा जाए, तो इतनी उठान सिंचाई स्कीमें निर्मित हुई हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं, लेकिन उन पर वे बोले नहीं। केवल यही बात बोलते रहे कि नहरों वाले खा गए, बिजली बोर्ड वाले खा गए और लाईन लौसिज हो गए। स्पीकर साहब जब हरियाणा की आबादी एक करोड़ तेरह लाख की है, उसका मुकाबला यू0पी0 के साथ जिसकी आबादी करीब दस करोड़ की है, करने का क्या तुक है। कहते थे वहां पिछले साल तीन सौ चार गांव के अन्दर बिजली आई। यह बात कोई जंचने वाली नहीं थी।

हरियाणा में 6666 गांव हैं, जिनमें से कुछ ढ़ानी और माजरे भी हैं। यह भी करीब सा या दो सौ होंगे। उन्होंने जो बोर्ड को क्रिटिसाइज किया है, यह गलत किया है, उनकी जो फिगर्ज़ हैं, वे गलत हैं। उनको कौन बताए कि पावर सरकिल में मौजे भी आबाद हैं, छोटे गांव हैं, जहां पर बिजली का विस्तर हुआ है। चौधरी दल सिंह जी यहां पर नहीं बैठे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको केवल एक ही बिजली बोर्ड मिला है, जिसको आप क्रिटिसाइज करते हैं। उनकी बात में कोई तथ्य नहीं होता है।

वे यहां पर लाइन लौसिज की भी बात कर रहे थे। पिछले चार सालों की फिग्र्ज़ उठा कर देख लिजिए लाईन लौसिज घटते ही रहे हैं, बढ़े नहीं हैं। हरियाणा सरकार ने जो तरक्की की है, यहां पर जितनी योजनाएं बनी हैं, जो भी प्लानिंग हुई हैं। उनको चौधरी दल सिंह जली ने रौंग कहा है। उनको चाहिए तो

यह था कि उसके मुकाबले में एक बड़ी सन्दर, एक बड़ी उन्नत ाील प्लानिंग ला कर यहां हाउस को बताते। हाउस को बताते कि ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना चाहिए था, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं बता सके केवल यहां पर क्रिटिसाहज करते रहे।

मुझे याद है कि जब यह आगमैंटे ान कैनाल कमी ान हुई थी, तो अपोजी ान के भाईयों ने बड़ा भाोर मचाया था कि सब रौंग प्लानिंग हुई हैं। 16 करोड़ यों ही खर्च किया है। कल से मैं हाउस में देख रहा हूं कि वर्शा के अभाव में जो दूसरी नहरे हैं, उनमें पानी की कमी है। सारे हाउस में यह मांग हो रही है कि आगमैंटे ान कैनाल का पानी हमें मिलना चाहिए ड्राउट एरिया को मिलना चाहिए। अगर आगमैंटे ान कैनाल आज के दिन नहीं होती, तो जिन इलाकों में आज सिंचाई हो रही हैं, उनमें भी नहीं होती। हमें अपने मुख्यमंत्री जी का आभारी होना चाहिए, जिनके दिमाग की यह उपज थी। जिन्होंने इंजीनियर्ज़ से सालह म वरा करके इस नहर को बनवाया। आज इस आगमैंटें ान कैनाल का पानी टेल तक पहुंच रहा है। यह है उन्नति का प्रतीक। जैसे जैसे उठान सिंचाई नहरें चलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, उसी तरह से टेल पर पानी पहुंच जाएगा। जो रेगिस्तान के टिब्बे हैं, उनमें भी पानी पहुंच जाएगा। वैसे तो बड़े दु:ख की बात है कि कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां पर बाढ़ का पानी, जिन दिनों में फ्लड आता है, वे बाढ़ से बड़े पीड़ित होते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां सूखे से कुछ लोग तंग होते हैं। जब तक इस पानी का कुदरत की तरफ

से यह प्रकोप है, कोई हल नहीं सोचा जाएगा, तब तक बाढ़ की समस्या हल नहीं होगी। हरियाणा के अन्दर केवल एक ही दरिया है, जिसका एक किनारा हरियाणा में है और दूसरा किनारा यू0पी0 में है। जब हमारे यहां बाढ़ आती है, और हमारे यहां नदियों में इतना कम पानी है तो इस बाढ़ के पानी को कहीं न कहीं कन्ट्रोल किया जाए। अब यह ओटो लेक बन रही है। उसका पानी खेतों को जाएगा। उस पानी को उठान सिंचाई के जरिए खेतों में पहुंचाया जाएगा, इन छोटी छोटी स्कीमों पर सरकार गौर कर रही है। हमारी सरकार इस पानी को जो कन्ट्रोल करने की कोि ा ा कर रही है वह इसीलिए कर रही है कि पानी कहीं भी नहीं मिलता है। हमारी सरकार का इतना अनथक प्रयत्न है, कोि ा ा है कि यदि कहीं पानी मिल चाहे नाले से मिले, या किसी और जगह से मिले, उसको खेतों के लिए उपयोगी बनाया जाए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का यह स्वप्न है कि एक–एक कियारी को पानी लगाना है। तो स्पीकर साहब कितनी प्र ांसा की बात है, कितनी अच्छी प्लानिंग हो रही है और उसके साथ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में सारी बातों का संकेत दिया है।

जहां और क्षेत्रों में तरक्की हुई है, वहां खास कर कृशि के क्षेत्र में अधिक तरक्की हुई है। हमारे यहां ऐसे डाक्टर्ज़ हैं, जिन्होंने लेबोट्रीज़ में बैठ कर बहुत अच्छे बीज खोजे हैं, neuclus seed-foundation seed, sanker Bajra Jwar इत्यादि। जितने भी संकर बीजों की खोज की है, वह सभी इन लोगों के दिमाग की

उपज है। आप जानते हैं कि जमींदारों को इससे कितना फायदा हुआ है। जो भी जमींदार आज इस सदन के सदस्य हैं, वे इस बात का सुझाव देते हैं कि इस संकर बीज को इस प्रकार और ठीक किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात थी लेकिन उन्होंने इस प्रकार के कोई सुझाव नहीं दिए। जब पहले पहले इस बीज को बांटा गया, तो लोग नहीं लेते थे लेकिन अब जमींदार इस बीज के पीछे भागता है इस बीज के बोने से उसकी उपज अधिक होगी। आज चाहे छोटा जमींदार है या बड़ा है, सब यह चाहते हैं कि इस बीज को बोकर अपने खेतों की उपज को बढ़ाया जाए। वे चाहते हैं कि अच्छी खाद डालें। यह मैं मानता हूं कि खाद के भाव बढ़े हैं। खाद का हमारे प्रदे ा के अन्दर कोई कारखाना भी नहीं है। इसलिए हमें खाद की कोई फैक्ट्री अपने प्रदे ा में लगानी चाहिए। यह मेरा अपना सुझाव है।

जहां तक खेतों में और तरक्की हुई है, वहां पर सरकार की ओर से लैण्ड री–कलेमे ान का प्रोग्राम चालू किया गया है। हरियाणा में 14 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसको री–कलेम करना है। यह काम सरकार ने बड़ा ही सराहनीय भुरू किया है। आज हमारे कृशि मंत्री जी ने बताया कि सात सौ एकड़ जमीन ऐसी है, जिसको री–क्लेम कर दिया गया है। हमारे यहां ऐसी जमीनें भी हैं, जहां वाटर लौंगिग है। वह भी ट्यूबवैल्ज़ लगने के कारण से ठीक हो गई है। अगर इस तरह से जमीनों को पानी खड़ा कर री–कलेम किया जाए तो इससे बहुत उपज बढ़ाई

जा सकती है और अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जा सकता है।

अस्पतालों में मुत्तालिक भी राज्यपाल महोदय ने बड़ी प्र ांसा की है और कहा है कि जगह जगह पर अस्पताल खोल रहे हैं। जो लोगों की तकलीफ होती थी, वह भी अब रफा हो जाएगी अब सब–डिवीजनल लेवर पर भी अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है।

हाउस में हाउसिंग बोर्ड की चर्चा होती रही है। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की तरफ से यह भी स्कीम बनाई जा रही है कि जिन लोगों के पास झुग्गी झोंपड़ियां भी नहीं उनके लिए मकाने बनाने के लिए पैसा देने के लिए वायदा किया गया है। बहुत मकान बन चुके हैं और बाकी जो हैं, वे बनाए जा रहे हैं।

जहां और सारे क्षेत्र में प्रगति हुई है वहां प ा धन के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी का स्वप्न है कि जमीन जो है वह उतनी नहीं है, आबादी बढ़ती जा रही है। इसलिए जो जमींदार हैं या दूसरे गरीब लोग हैं, उनकी प ा धन के मामले में उन्नति की जाए। कुछ लोग का तकार दूध नहीं बेचना चाहते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जहां जहां आजकल जाते हैं, वहां हर गांव में लोगों को यही कहते हैं कि भैंस का दूध बेचना चाहिए। यह जो दूध न बेचने वाली प्रथा है, इसको समाप्त करना चाहिए। यह जो अड़चन है, इसको दूर करना चाहिए। हमारी सरकार ने जो फीड प्लांट

लगाएं हैं, यह बड़ा सराहनीय कदम है। हमारे यहां पहले फीड प्लांट नहीं था। बनौले और चना महंगा होने की वजह से जमीदारों को दूध काफी महंगा पड़ता था। उनका ख्याल था कि भैंस नहीं रखेंगे। अगर जमींदार इस अभियान के साथ चलेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे काफी धन कमा सकते हैं। हमारी सरकारी इस प्रकार के और भी कई प्लांट लगाने जा रही है। मैं समझता हूं कि हरियाणा में जो भवेत क्रांति लाने का स्वप्न है, जब सारे प्लांट लग जाएंगे तो जमींदार प ा धन कमाने में बहुत कामयाब हो जाएंगे।

ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारी सरकार ने काफी तरक्की की हैं यह वह डिपार्टमैंट है जिसकी इस टाईम साढ़े अट्ठारह सौ बसें सड़क पर हैं। यह भी ठीक है कि उसमें कुछ एक ऐसी बाते हैं, जिनका सुधार होना चाहिए। मैं सरकार को इस बात का सुझाव दूंगा कि जब तक वह वर्क ाापों को कंट्रोल नहीं करती, जब तक वह प्रापैर मेन्टनैंस की तरफ गौर नहीं करती और तब तक कन्डक्टर्ज़ के बारे में जो आम ि ाकायत है, उसकी तरफ नहीं देखती तब तक यह रोज का झगड़ा समाप्त नहीं हो सकता। जहां हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में इतनी तरक्की की है, वहां इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बसों में बहुत ज्यादा तेल क्यों खर्च होता है ? इन बातों की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। मिनिस्टर साहब यहां बैठे नहीं हैं। मैं उनका इन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, ताकि इनको ठीक किया जा सके।

को–आप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारें में यहां पर राज्यपाल के अभिभाशण में बताया गया कि ऐसी प्लानिंग की गई है और ये काम किए गए हैं, इसका जिक्र आ गया है। उसमें मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। यहां पर इतने अफसर साहबान बैठे हैं। यह जो आडिट रिपोर्ट की कल क्व चन आवर में बात चल रही थी और उससे पहले भी जिसका जिक्र आया है, इसके बारे में मेरा एक सुझाव है। कुछ एक ऐसी सोसायटियां हैं, जिनके रिकार्ड या तो कोर्ट में हैं या किसी थाना में पड़े हैं या कही गुम हैं। मैं स्पीकर साहब आपके जरिए सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि मैंने वहां जाकर को–आप्रेटिव के रिकार्ड से खुद यह देखा है कि पिछले साल में इनका सिर्फ 700 रुपए का टी0ए0डी0ए0 का बिल है। मैं यह समझता हूं कि टी0ए0डी0ए0 पर बहुत कम पैसा खर्च हुआ है। को–आप्रेटिव के इतने ज्यादा अफसर यहां बैठे हैं इनको फील्ड में जाना चाहिए और फील्ड में जाकर एक–एक सोसायटी को वहां पर चैक करना चाहिए। उनके जो रिकार्ड गुम हैं, उनको तला ा करवाना चाहिए। हमारे यहां जाहं को–आप्रेटिव सोसायटियों ने एक ओर काम किया है, वहां हमने चीनी मिलों के मामले में जो तरक्की की है, वह बहुत सराहनीय है। आज से 4–5 साल पहले यानी चौधरी बसी लाल की हकूमत आने से पहले इन मिलों की जो हालत थी, वह यह थी कि वे बिल्कुल घाटे में जा रहीं थी। इन मिलों का इतने अच्छे तरीके से कन्ट्रोल हुआ है, उनमें इतना प्रौफिट है कि उससे जमींदार भी अब सन्तुश्ट हैं। पहले इन मिलों का भोयर भी कोई खरीदने के लिए राजी नहीं

होता था। जमींदार भी कहते थे कि मैं तो भोयर इसलिए खरीदता हूं क्योंकि मैं गन्ने का सप्लायर हूं। आज उनमें इतना सुधार हुआ है कि तारीफ करने लायक है। मुझे याद है जब मैं रोहतक की मिल का डायरैक्टर बना था, तो वहां हजारों बोरियां ऐसी पड़ी थी, जो कि मार्कीट रेट से भी 6 रुपए कम में जाती थीं। जब मैंने पूछा कि इनका हरा रंग क्यों है, तो वह चीफ कैमिस्ट जवाब देने से पहले ही भाग गया। इस तरह से अब अगर देखा जाए, तो पता चलता है कि इनमें बहुत सुधार है। जहां हमारे यहां पहले ही तीन–चार भूगर मिलें हैं, वहां उसके साथ ही इन मिलों का विस्तार हो रहा है। इस तरह से मैं इसकी प्र ांसा करता हूं कि राज्यपाल महोदय का यह जो अभिभाशण है, यह बहुत ही सुन्दर और बहुत ही उन्नति ील है। इससे हमें बहुत ही मार्ग द र्ान मिला है। मैं इसका समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

राव बंसी सिंह (अटेली): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में गवर्नर के अभिभाशण पर चर्चा हो रही है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। (इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई) गवर्नर के अभिभाशण में जो हमारा मुख्य लक्ष्य बताया गया है, वह है इकोनोमिक जस्टिस विद सो ाल इक्वैलिटी। प्रांत के अन्दर इकोनोमिक जस्टिस ऐंड सो ाल इक्वैलिटी के आधार पर हम लोक कल्याण कार्य करें। जो सरकार हो, वह लोक कल्याणकारी

सरकार हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नर साहब ने अपने अभिभाशण में 9 सूत्री प्रोग्राम को अपनाया है, जिसके अन्दर सबसे प्रथम कार्य जो उन्होंने अपनाया है, वह है रूरल एरियाज़ के लिए इलैक्ट्रिसिटी। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि भारतवर्श के अन्दर हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रांत है। इस कृशि प्रधान प्रांत के अंदर जो मुख्य बात ऐग्रीकल्चर के लिए रह जाती है वह है इलैक्ट्रिसिटी को पहला स्थान दिया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि हरियाणा बनने के बाद चौधरी बंसी लाल की सरकार के समय में हरियाणा के गांव गांव में बिजली पहुंची। हर आदमी इसको मानता है और यह एक सराहनीय कार्य है। इससे बोर्ड का और सरकार का आपसी सहयोग का पता चलता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे यहां बिजली की प्रोडक ान का जो प्रोग्राम चल रहा है, वह स्टेट के लिए काफी नहीं है, क्योंकि बिजली की हमारे उत्पादन कम होता है और खर्चा ज्यादा है। इसके अलावा मैं यह समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने जो थर्मल प्लांट फरीदाबाद के अन्दर लगाया वह इसलिए लगाया ताकि लोगों को बिजली मुहैया की जाए। एक पानीपत के अन्दर थर्मल प्लांट बन रहा है। यह भी इसलिए बन रहा है क्योंकि हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रान्त है और यहां के किसान को हम अधिक से अधिक बिजली दे सकें। यह तो एक बड़ा ही उत्तम कार्य है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं अव य आपके थ्रू सरकार के नोटिस में लाउंगा कि आज किसान की हालत बेसिक रूप से कमजारे

होती जा रही है। इस कमजोरी का कारण भी मैं आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। वह यह है कि किसान को जितनी बिजली मिलनी चाहिए, उसको उतनी पूरी बिजली नहीं मिलती। बिजली न मिलने के कारण मैं समझता हूं कि बिजली का क्राइसिज है। स्टेट के पास इतनी बिजली नहीं है कि किसान को पूरी बिजली दी जा सके, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आपके द्वारा बिजली बोर्ड के चेयरमैन या सम्बंधित कर्मचारियों से कि उन लोगां का यह फर्ज़ बनता है कि हमारी स्टेट के अंदर जितनी बिजली अवेलेबल है उसी के मुताबिक आगे ट्यूबवैल्ज़ को कनैक्शन्ज़ दें। एक किसान को अगर ट्यूबवैल का कुनैक्शन मिलने के बाद भी जब वह बिजाई कर लेता है बिजली नहीं मिलती तो उसको बहुत दुःख होता है। वह सरकार के सारे करे कराए काम को भूल जाता है कि हमने बिजली की मिकदार को तो ख्याल में नहीं लिया लेकिन ट्यूबवैल कुनैक्शन देकर कन्ज़म्पशन उस मिकदार से ज्यादा कर दी, जिसकी वजह से आज बिजली क्राइसिज है। इसके साथ ही साथ आपके द्वारा बिजली बोर्ड के चेयरमैन के नोटिस में यह भी लाना चाहता हूं कि आपके कर्मचारी किसान के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा डेढ–डेढ दो–दो साल हो गए हैं, किसानों ने अपने कुओं पर पम्पिंग सैट लगवा रखे हैं, डिमांड नोटिस कटे पड़े हैं, टैस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उनको कुनैक्शन नहीं मिल पाया है। वे जमींदार जिन्होंने लैण्ड मार्गेज़ बैंक से कर्ज़ लेकर 8–8, 10–10 हजार रुपया डेढ़–डेढ़ साल हो गए लगाया हुआ है, उनको

कुनैक ान नहीं मिलता है लेकिन दूसरी तरफ यह सरकार कहती है कि हम किसान को ऊपर उठाना चाहते हैं और इसके लिए यह सरकार सबसे पहले उन पर 60 प्रति ात बजट खर्च करना चाहती है। यदि इसी तरह से हमारी रौंग प्लानिंग हुई, तो हमारी सब बड़ी–बड़ी स्कीमें फैल हो जाएंगी। मेरी अर्ज़ यह है कि उन कर्मचारियों की जिन्होंने टैस्ट रिपोर्ट ली, डिमांड नोटिस काटें जबकि उनके पास बिजली नहीं थी, ऐक्सप्लेने ान ली जानी चाहिए कि उन्होंनें ऐसा क्यों किया। हरियाणा को कमजोर करने के अन्दर उन मुलाजमों का बहुत बड़ा हाथ है।

16.00 बजे

जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि किसान के साथ यहीं तक खिलवाड़ नहीं किया गया, बल्कि उससे 2500 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाए। और उसको कहा गया कि विद इन एक या दो दिन या विद इन 15 डेज़ कुनैक ान दे देंगे, लेकिन उनको कुनैक ान नहीं दिया गया। जो अपनी किसान इतना कमजोर है, जिसके पास ब्याह भाादियों के लिए पैसा नहीं, जिसके पास बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, उस किसान ने कर्जा लेकर 2500 रुपए जमा करवाए, लेकिन उनको कोई कुनैक ान नहीं दिया गया। यह कोई खिलवाड़ नहीं तो क्या है ? इसका दोश चीफ मिनिस्टर पर या आई0पी0एम0 पर कैसे डाला जा सकता है। सारा दोश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का है, जिन्होंन डिस्ट्रिक्ट हैड–क्वार्टर पर बैठ

कर रांग पालिसी अपनाई, जिससे किसानों को इतनी परे ाानी का सामना करना पड़ा। जब तक इन कर्मचारियों को सख्त सजा नहीं दी जाएगी तब तक हरियाणा के किसानों की तकलीफ दूर नहीं हो सकती। मैं इस बात को मानता हूं कि हरियाणा की तरक्की के लिए इरीगे ान की स्कीम बनाई, जिसको लिफ्ट इरीगे ान स्कीम कहते हैं। मैं समझता हूं कि हरियाणा आगे तभी बढ़ सकता है जबकि उन नहरों का पानी उन खु ाक इलाकों में पहुंचाया जाएगा, जो कि आज तक नहीं पहुंचा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बात को मूल नहीं सकता कि इसी पानी को पहुंचाने के लिए जब ज्वांयट पंजाब था और राव बीरेन्द्र सिंह उस समय इरीगे ान मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस बैकवर्ड इलाके के लिए सोहना लिफ्ट स्कीम बनाई और सोहना लिफ्ट स्कीम मन्जूर कराने की कोि ा ा की। इस बार पर सरदार प्रताप सिंह कैरों जो उस समय पंजाब के मुख्य मंत्री थे, के साथ वाद विवाद हुआ। राव वीरेन्द्र सिंह को उस इलाके में पानी पहुंचाने के लिए डिसमिस होना पड़ा, जो कि दे ा के इतिहास में पहली मिसाल थी। आज मुझे यह कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि चौधरी बंसी लाल इस लिफ्ट स्कीम के द्वारा उस इलाके को जो पानी पहुंचाना चाहते हैं और जो बहुत से भाई यह कहते हैं कि वह पानी लाएंगे कहां से लेकिन मैं उनकी बहादुरी की ताईद करता हूं कि कम से कम उस व्यक्ति ने उस खु क इलाके को पानी पहुंचाने की कोि ा ा की तो सही और पंडित जवाहर लाल नेहरू स्कीम मंजूर करा कर उस इलाके को पानी पहुंचाने का विचार तो किया। उस इलाके के

लोग इस काम के लिए बहुत धन्यवादी हैं। वह इलाका उनका बड़ा धन्यवादी है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि दो–तीन साल के अन्दर वहां पानी पहुंच जाए। पानी पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि वहां छह महीने कहत पड़ता है और उस कहतजदा इलाके को बचाने के लिए, वहां के लोगों को ऊपर उठाने के लिए यदि हमारा अधिक से अधिक पैसा उस स्कीम पर खर्च होता है तो हम खर्च करें और उस इलाके को पानी दे दिया जाए तो वहां के लोग इतने मेहनती हैं कि वह काफी अनाज पैदा करके दे ा के अन्दर जो अनाज की कमी है उसकी कुछ हम तक पूर्ति कर सकते हैं। सरकार ने अभी तक जवाहर लाल नेहरू कैनाल स्कीम बनाई है और सैन्टर से इसको मंजूर कराया है लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक नहरों का सवाल है उस इलाके में और भी ऐसी स्कीमें हैं जो कि मैं अपनी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। कुछ लोकल स्कीम्ज हैं जिनके थ्रू उस इलाके की बैकवर्डनैस दूर हो सकती है। वहां पर तीन नदियां है टोहन, कृश्णावती और साहबी। यदि इन तीनों नदियों पर बांध बांधकर पानी रोका जाए तो मैं समझता हूं कि उस इलाके का एक तिहाई हिस्सा सिंचाई के रूप में लग सकता है और इसलिए अपनी सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर बांध बांध कर उस पानी को रोका जाए। उससे दो फायदे होंगे। कुओं के अन्दर जो पानी कम रहता है, पानी स्टोर करने की वजह से पानी का लैवल उन कुओं के अन्दर ऊंचा हो जाएगा और दूसरे सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि क्या बदकिस्मती है उस इलाके की कि आज तक उस इलाके को इन्साम नहीं मिला। जिस इलाके ने दे ा को आजाद कराने के अन्दर सबसे पहले 1857 के अन्दर लड़ाई लड़ी, जिस इलाके ने चीन और पाकिस्तान की लड़ाई के अन्दर सबसे ज्यादा कुर्बानी दी और आज वहां की बहन और बेटियों के सिर का सिंदूर मिट गया, वे विधवा हो गई उस इलाके को 27 साल दे ा को आजाद होने के बाद भी पीने का पानी नसीब नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है। मैं इस बात को कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं। मिसाल के तौर पर डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस कांस्टीच्युऐंसी से मैं ताल्लुक रखता हूं आज तक एक भी गांव के अन्दर वाटर सप्लाई की स्कीम बनाकर किसी गांव के अन्दर पानी नहीं पहुंचाया गया। जिस इलाके ने दे ा के लिए इतनी कुर्बानी की हो, जिसने दे ा की तरक्की में और हरियाणा की तरक्की में कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया हो, वहां के लोग खारा पानी पिएं, इससे ज्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है। मैं यह कहूंगा कि जिन इलाकों में वाटर सप्लाई की स्कीम चल रही है, उन इलाकों का चाहे कुछ बजट कम किया जाए, लेकिन उन इलाकों पर ज्यादा खच्र किया जाए, जो आज बैकवर्ड रहे हैं। अंग्रेजों से लेकर जिन इलाकों में आज तक कोई काम नहीं हुआ है कम से कम उन इलाकों को पीने का पानी अव य देना चाहिए। आपके द्वारा मैं अपनी भावना सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसी कोई कांस्टीच्युऐंसी न हों, जहां पीने के पानी की

सुविधा न हो। जितना हमारा हिस्सा आता है, चाहे दो गांव में चाहें पांच गांव में पीने के पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि जहां आलरेडी स्कीम्ज़ चल रही है, उनको बन्द करके हमारे इलाके में भ्रुरू की जाएं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उनका कुछ पैसा कम करके हमारे इलाके में भी पानी की स्कीम्ज़ आरम्भ की जाएं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज लोगों की उन्नति सिर्फ एक बात पर निर्भर नहीं करती कि केवल अनाज पैदा कर दें और दूसरा कोई साधन न हो। आज किसान तक तब ऊंचा नहीं उठेगा। तब तक कि उस इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं होंगी। हमारे राज्यपाल महोदय ने जो नौ सूत्री प्रोग्राम रखा है, उसके अन्दर किसान के हित की जो चीज है, उसको अव य करना चाहिए। हरियाणा के अन्दर हर जिले में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ताकि लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा जिला महेन्द्रगढ़ के लिए मिल्क प्लांट मन्जूर कराने की अपनी भावना सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि वहां पर एक चीलिंग सैन्टर बनाया जाए, लोगों को को–आप्रेटिव के थ्रू लोंन दिया जाए, जिससे लोग प ा खरीदकर और दूध बेचकर अपना गुजारा कर सकें। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि न ही वहां पर कोई इस किसम का इंटैन्सिव कैटल प्रोजैक्ट रखा गया है, जिससे वहां के किसानों की इकोनोमिक हालत अच्छी हो सके और न ही

वहां पर भवेत क्रांति के लिए कोई कदम उठाया गया है। ठीक है सरकार के पास पैसे की कमी है, मैं, इस चीज को मानता हूं कि इकनामिक क्राइसिज है। मैं मानता हूं कि जहां पहलें प्लांट लगाने का प्रोग्राम है वहां लगेंगे, लेकिन मैं उनको रूकवाता नहीं। मैं आपके द्वारा यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह इलाके जो बैकवर्ड हैं, जैसे भिवानी, महेन्द्रगढ़, नाहड़, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कुछ इलाके वहां के लोगों को दो भैंस का लोन दिया जाए ताकि वह किसार दो भैंस रखकर और उनका दूध बेचकर अपना गुजारा कर सकें और वह लोन को–औप्रेटिव बैंक के थ्रू दिया जाए और उन इलाकों में ज्यादा नहीं तो वह लोन तीन साल में वापिस लेना चाहिए, ताकि वहां के किसान की इकानामिक हालत अच्छी हो सके। अब तक जो लोन वहां देते हैं, वह सिर्फ छह महीने के लिए ही देते हैं। तो ऐसे हालात के अन्दर आप डिप्टी स्पीकर साहिबा समझ सकते हैं कि किसान अपने लोन की री–पेमैंट कैसे करेगा ? वहां के किसान को गुमराह किया गया है, वहां के किसान को पंपिंग सैट्स के लिए लोन नहीं दिया गया। वहां के किसान ने अपने जेवर वगैरह गिरवी रखकर लोन लेकर ट्यूबैवैल्ज वगैरह लगवाए और फिर भी उनको कुनैक न्ज़ नहीं दिए गए,, उनको हर तरह से निग्लैक्ट किया गया है, तो मैं यह समझता हूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा कि यह किसान के साथ बड़ा भारी अन्याय है, सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसान को हर तरह की सहूलियतें

न दी गई तो वह बर्बाद हो जाएगा, लिए हुए कर्जे को वह रि–पे कैसे करेगा ?

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक को –ऑप्रे ान का ताल्लुक है, उसके बारे में तो मैं यह कह सकता हूं कि अगर दे ा का सामाजिक ढांचा बदल सकता है तो केवल इसके द्वारा ही बदल सकता है। को–ऑप्रेटिव डिपार्टमैंट वह है जिस पर कि हमारी इकनामी उन्नति करने के लिए बेस करती है। आज इसी के कारण ही हमारी हरियाणा की भूगर मिल्ज़, इंडस्ट्रीज वगैरह सभी मुनाफा में जा रही हैं, जो हमारा किसान है, जो इस दे ा की रीढ़ की हड्डी है, वह भी इस पर निर्भर करता है। किसान को अगर बीज मिलता है, तो को–ऑप्रेटिव डिपार्टमैंट के द्वारा, खाद मिलती है तो इसके द्वारा बैल के लिए रुपया, भैंस खरीदने के लिए रुपया मिलता है तो वह भी को–औप्रेटिव के द्वारा ही मिलता है, मतलब यह कि किसान को यहां से हर तरह की सहूलियतें मिलती हैं। तो आज जो भी हमारा ढांचा है, इसके ऊपर सारे का सारा निर्भर करता है, निर्धारित है। तो इसलिए हमें इस को–ऑप्रेटिव डिपार्टमैंट की तरफ पूरी तरह से तवज्जो देनी चाहिए। यदि हमें कोई ढील आ गई यदि इसमें कोई त्रुटियां आ गईं तो किसान बिल्कुल नहीं उठ सकेगा और हमारा हरियाणा भी तरक्की नहीं कर सकेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, को–ऑप्रेटिव से सम्बन्धित मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढद्य में सन् 69 के अन्दर एक सैन्ट्रल को–ऑप्रेटिव बैंक था। वह हरियाणा स्टेट

का ए–ब्लास बैंक था। उसके बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया और अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। आप बड़े हैरान होंगे कि जब वह बैंक बोर्ड द्वारा चलाया जाता था उस वक्त वह बैंक सारी स्टेट के अंदर ए–क्लास था और उसमें कभी कोई घाटा नहीं पड़ा था, लेकिन जब काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया उस वक्त उसमें गड़बड़ होनी भुरू हो गई और बैंक ए–क्लास में आ गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप सोचें कि जिस बैंक को बोर्ड चलाए उस वक्त तो उसका मुनाफा लाखों तक पहुंच जाए और जब सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में यह प्रबन्ध आए तो उस वक्त लाखों से घटकर हजारों तक उसका प्रोफिट रह जाए, यह कितने दुःख की बता है, लेकिन जब तक इस तरफ कोई तवज्जों नहीं दी जाएगी, तब तक इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन सारी बातों का दारोमदार बड़े आफिसर्ज़ के ऊपर है। को–ऑप्रे ान का नाम केवल कुछ थोड़े लोगों के कारण से कुरप ान रखा गया, छोटे लोग गड़बड़ करते हैं, किसी को मालूम नहीं होता, लोन वगैरह ले जाते हैं, सोसायटीज के अन्छर भी अपनी मनमानी करते हैं। इसलिए को–ऑप्रेटिव का नाम बदनाम होता जा रहा हैं लेकिन गांवें के अन्दर चुनाव होते हैं और लोगों के वहां पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को यह भी पता नहीं होता कि इसका चेयरमैन कौन है, मैंबर कौन है, सैक्रेटरी कौन है। मैं आपकी तरफ से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जो आई0ए0एस0 आफिसर्ज़ हैं, बहुत समझदार हैं, उनको पूरी तरह से इस बात की आजादी

होनी चाहिए कि वे इसमें दखलअन्दाजी कर सकें। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारे जो बड़े आफिसर्ज़ आई0ए0एस0, आई0सी0एस0 हैं, वे बड़े ईमानदार आदमी है, यदि कोई गल्त काम होता है, तो नीचे के तबके से ही होता है, इसलिए यह सारा काम उन पर छोड़ देना चाहिए, तभी इसमें सुधार आ सकता है। अगर वह ईमानदारी लाना चाहते हैं, तो फिर हम पोलीटीि ायन्ज़ उन्हें किसी गल्त काम के लिए मजबूर कर देते हैं। जहां तक को–ऑप्रेटिव डिपार्टमैंट का ताल्लुक है, हमें रजिस्ट्रार, सैक्रेटरी साहब के ऊपर सभी काम छोड़ देने चाहिएं ताकि वे इन बुराइयों को दूर कर सकें और गांवों के अन्दर इक्वैलिटी ला सकें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक सिविल सप्लाई विभागा का ताल्लुक है, उनके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने गांव–गांव में डिपोज खोलकर बहुत अच्छा कदम उठाया है। हरिजनों को भी डिपोज दिए गए हैं, बल्कि उनसे तो सिक्योरिटी भी बहुत कम ली गई है। सरकार के इस काम की मैं ताईद करता हूं, यह एक बड़ा सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है, लेकिन इसके साथ–साथ मैं सरकार के नोटिस में एक दो बातें लाना चाहता हूं कि सरकार जिलेवार सी0आई0डी0 विभाग से रिपोर्ट मंगवा कर के देखे तो पता चलेगा कि एक–एक इंस्पैक्टर एक हजार रुपया महीना रि वत लेकर कमा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप सी0आई0डी0 की रिपोर्ट मंगवा कर देखें, दो–दो रुपए की बोरी पर लिया जाता है,

जब तक इम इन सारी चीजों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं करते, तब तक तो महकमें का नाम ही बदनाम होगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज तो ईमानदारी से कमा कर खाने वाले इंसान हैं, वह बहुत ही कम हैं। आप को कई ऐसे डिपो होल्डर्ज़ वगैरह भी मिलेंगे जो कि पैसे खिलाते हैं और लोगों को कम तोल कर देते हैं, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे इस कुरप् ान को खत्म किया जाए ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा एक प्वांयट रह गया है, वह है हरियाणा रोडवेज के बारे मैं, जिसमें हमारे हरियाणा प्रान्त ने सबसे पहले पहल की, बल्कि सारे भारत वर्श में इस ओर हमारा पहला स्थान है कि जो हरियाणा रोडवेज को अपने हाथ में ले लिया। मैं समझता हूं कि सरकार का यह बड़ा ही प्रं ाासनीय और सराहनीय कदम है। मैं आपके द्वारा इस सरकार के नोटिस में एक दो बातें लाना चाहता हूं कि अभी तक इस रोडवेज का सिस्टम सही ढांचें पर नहीं आया है, इसका कारण एक है कि जो वर्क ााप्स हैं, उनके अन्दर गड़बड़ होती है, उनमें पूरा टैक्नीकल काबिल स्टाफ नहीं है। दूसरी चीज जो बसों आदि के लिए पुर्जे खरीदे जाते हैं, वह पुर्जे बाजार में पहुंच जाते हैं, जो टायर हरियाणा रोडवेज के लिए खरीदे जाते हैं, वे बाजारों में पहुंच जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि चण्डीगढ़ जैसे स्थान पर जहां पर कि सभी बड़े–बड़े आफिसर्ज़ हैं, सारा सामान जहां पर इकट्ठा होता है, वहां पर आग लग जाए और कोई वहां डयूटी पर न हो, एक कहता है कि मैं नहीं था, दूसरा कहता है कि मैं भी नहीं था। कितनी बुरी बात है। डिप्टी स्पीकर साहिबा,

आज अगर इन कमियों को दूर न किया जाएगा, तो हरियाणा का नाम पीछे रह जाएगा। अगर हरियाणा रोडेवज वगैरह का नाम और ऊंचा लाना है, तो कम से कम इन त्रुटियों, इन कमियों की तरफ सरकार को ध्यान देना होगा और सही कदम उठाने होंगे। जब तक हम इन कमियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम ऊंचा नहीं उठ सकेंगे। दूसरी बात मैं यह कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि जहां पर भी बस अड्डे के लिए जमीन ली जाती है, वहां लोगों को चाहे म्यूनिसिपैलिटी की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे और किसी संस्था की हो, महकमें को उनको जमीन के पैसे देने चाहिएं। कनीना बस अ कनीना बस अड्डे के लिए फाउंडे ान स्टोन रखा गया है, जमीन एक्वायर की गई है और वह जमीन एक्वायर की गई है कि जहां पर कि लड़के–लड़कियों का एक स्कूल था। वहां लोग लड़के–लड़कियौं के लिए स्कूल बनाना चाहते थे, लेकिन हैरानी की बात है कि यह बात अफसरों के नोटिस में लाने के बावजूद भी उस जमीन को एक्वायर किया गया। वहां की जनता स्टैण्ड ले सकती थी लेकिन अगर स्टैण्ड लेते हैं, तो हमारी ही तरक्की रुकती है और कोई जिम्मेदार आदमी यह नहीं देख सकता कि हमारा विकास का काम रुके। कहने का मतलब यह है कि आखिर क्या जरूरथी कि उसी ही जगह को लेने की और अगर लेनी ही थी कि वहीं लेनी है जो जब दूसरी जगहों में दस–दस लाख रुपए देकर जगहें ली जा रही हैं तो इस साढ़े छः एकड जगह को भी पैसे देकर लिया जाता ताकि उस पैसे से वहां कोई पब्लिक बहबूदी का काम होता। वहां की कमेटी आज तक लोगों

को पानी मुहैया नहीं कर सकी। अगर यह रुपया उसे मिल जाता और उस जमीनर को खरीद कर लिया जाता तो यह पैसा इस काम में लग सकता था अगर वह जमीन लेनी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कहा जाता है कि वहां की कमेटी ने ही प्रस्ताव पास करके इस बारे में भेजा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस कमेटी में गवर्नमैंट का अपना एडमिनिस्ट्रटर बैठा हो, तो वहां कोई भी प्रस्ताव पास हो सकता है। उन एडमिनिस्ट्रेटर को क्या अधिकार है कि वह गांव की लैण्ड को लेकर मुफ्त में दे दे। तो मैं अर्ज करता हूं कि अगर वही जमीन लेनी है, तो ले लो, बस अड्डा बना लो ओर अड्डा के लिए वहां के इलाका की मांग भी है, लेकिन उस जमीन के पैसे कमेटी को मिलने चाहिएं और इतने पैसे देने से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को फर्क भी क्या पड़ेगा। और जगह भी पैसे देकर जमीन ली जा रही है, यहां भी पैसे दे देने में क्या दिक्कत है ? इसके साथ ही एक बात मैं स्पै ाली ट्रांसपार्ट मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे डिपो अब नुक्सान में जाने लग गए हैं। अगर इस बात की तरफ ध्यान न दिया गया और इस चीज को पड़ताल करके चैक न किया गया तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट नाम पैदा करता है, वह बदनाम भी हो सकता है। चैसीज खरीदी जाती हैं, लेकिन बाडीज़ वक्त पर न बनने की वजह से खड़ी रहती हैं। कोई 184 के करीब चैसीज़ पहले खरीदी गई, लेकिन वह पांच–पाच, छः–छः महीने तक खड़ी रहीं, क्योंकि बाड़ी बिल्डर्ज़ के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ कि किससे बाडीज़ बनवाने हैं। टैंडर इनवाईट करके क्यों

नहीं फौरन लोयेस्ट टैंडर देने वाले को काम सौंपा जाए ? आखिर यह जो इतना नुक्सान बसें खड़ी रहने की वजह से हुआ, यह हमारा ही हुआ टैक्स पेयर का ही हुआ। एक तरफ तो कमाई में नुक्सान हुआ, क्योंकि यह बसें चली नहीं, दूसरी तरफ जनता को दिक्कत हुई, जो सारा–सारा दिन अड्डों पर बस की इंतजार में खड़ी रहती हैं और उनको सीट नहीं मिलती। हम जब चण्डीगढ़ आते हैं, तो रास्ते में देखते कि लोग हाथ उठाते रहते हैं, लेकिन बिठाने के लिए जगह नहीं होती और वे बेचार बस अड्डों पर रातें काटते हैं। अगर आपने ट्रांसपोर्ट को नै ानेलाईज किया है, तो ठीक है लेकिन लोगां को तो एक जगह से दूसरी जगह जहां वे जाना चाहते हैं, पहुंचाओ।

अब मैं ि ाक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज यह हर कोई कहता है कि हमारी ि ाक्षा का जो मौजूदा सिस्टम है, वह ठीक नहीं है और ि ाक्षा भाास्त्री भी दे ा के यह महसूस करते हैं कि इस में परिवर्तन लाने की जरूरत है। ि ाक्षा सैन्टर का भी और स्टेट्स का भी विशय है। अगर आज की जो एजुके ान है, वह यही एजुके ान है, कि बच्चे सिर्फ यही सीखें और उस दे ा के बच्चे जो कृशि प्रधान दे ा है कि टैरीलीन की पैंट और बु ा– ार्ट किस ढंग की पहननी है, बाल किस नमूने के बनाने हैं, हरि सिनेमा– ाो देखना है लेकिन घर पर काम कोई नहीं करना है, तो ऐसी ि ाक्षा का क्या फायदा यह तो टाईम और पैसे दोनों की वेस्टेज हैं। आज पढ़े लिखे बच्चों की पढ़ाई का

स्टैण्डर्ड यह है कि उनको एप्लीके ान तक लिखनी नहीं आती और नालेज इतना है कि किसी बात का पता ही नहीं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार है ? ठीक है कि ि ाक्षा का ढांचा ठीक नहीं लेकिन इसके लिए हमारा अध्यापक वर्ग भी कम जिम्मेदार नहीं है। अगर अध्यापक वर्ग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे तो कोई वजह नहीं कि ि ाक्षा का स्टैण्डर्ड इतना लो चला जाए। जहां अध्यापक वर्ग की कठिनाई हो, उनकी जायज मांग हो, उसकी हम ताईद करते हैं, उनके लिए डियरनैंस अलाउंस की भी मैंन ताईद की और अब भी करता हूं, लेकिन उनको भी अपना रोल जो है, ईमानदारी से अदा करना चाहिए। आज हमारे हरियाणा के बच्चे कम्पीटि ान में नहीं आते हैं और दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। तो इसमें दूसरों का आगे निकलने वालों का तो कोई कसूर नहीं, अगर कसूर है, तो हमारे इस अध्यापक वर्ग का है, जो बच्चों को इस काबिल नहीं बनाते कि वह दूसरों का मुकाबला कर सकें। यह तो एक साईड है और दूसरी साईड इस मसला की यह है कि हमारी जो ि ाक्षा है वह किताबी ि ाक्षा है। बच्चों को न नैतिक ि ाक्षा दी जाती है और न ही चरित्र की ि ाक्षा दी जाती है सिर्फ अक्षरी ि ाक्षा ही दी जाती है और वह ि ाक्षा भी जब गुरु बे–मन से दे, ईमानदारी से न दे, मेहनत से न दे, तो फिर बच्चे कैसे लायक बन सकते हैं और यह ने ज्ञन कैसे आगे बढ़ सकती है। इसलिए इस ि ाक्षा के ढांचे में परिवर्तन लाने की जरूरत है और सबसे पहले प्राइमरी ि ाक्षा में परिवर्तन लाना होगा। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों के अन्दर काबिल से

काबिल अध्यापक लगाए जाने चाहिएं और ऐसे अध्यापके लगाए जाने चाहिएं, जो मनोवैज्ञानिक सब्जैक्टस पढ़े हुए हों, ताकि वे बच्चों को मनोवैज्ञानिक जांच करने के बाद उनके लिए सब्जैक्टस सिलैक्ट करें। और जो बच्चा जिस लाईन में जिस साईंस में चल सकता हो, उसी ग्रुप के सब्जैक्टस उसे दिए जाएं, और वही उसे पढ़ाए जाने चाहिएं। इसके साथ मैं अर्ज़ करता हूं कि इस अनएम्प्लायमैंट को दूर करने में सबसे बड़या रोल ि ाक्षा दी जाए और एक सी ि ाक्षा दी जाए, जिसके हासिल करने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाए कि वह अपने पांव पर खड़ा हो सके और नौकरी के पीछे भागने की बजाय खुद अपना काम चलाकर रोटी कमा सके। जो काबिल बच्चे हैं, वे आगे निकलें हायर सर्विसिज़ में जाएं और कम्पीटि ान में मुकाबला करें, बाकी दूसरे काम करें, जिनसे रोटी पैदा हो। आज हमें ि ाक्षा में क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी पैदा करने की जरूरत है। जो योग्य बच्चे हैं, उनको आगे कालेज में दाखिला दिया जाए, बाकी जो हैं, उनको व्यसायक ि ाक्षा दी जाए और ऐसी ि ाक्षा दी जाए जो उनको रोटी कमाने के काबिल बना सके। तभी यह बेरोजगारी दूर हो सकती है। दे ा की 80 फीसदी आबादी गांव में रहती है, और इस 80 फीसदी आबादी के बच्चे ज्यादातर बेकार रहते हैं और खाली दिमाग को भारारतें ही सूझती हैं, यही कारण है कि इतना इनडिसिपलिन नजर आता है। तो उनको काम देने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि को–ऑप्रेटिव सैक्टर सोसायटीज बनाई जाएं। सोसायटीज बनाने का मतलब यही न लिया जाए, कि पैसा दे दिया

फिर काम खत्म बल्कि जो इंडस्ट्रीज के स्पै ालिस्ट्स हैं, वह महकमा से लेकर इनमें एडवाइजर लगाएं जाएं जो बताएं कि कौनी सी इंडस्ट्री लगाई जा सकती हैं। हमें खु ाी है कि भिवानी और रिवाड़ी के बैकवर्ड इलाकों में वहां इंडस्ट्री को डिवैल्प करने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर्ज़ बनाने की कोि ा ा की है, और उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, लेकिन वह तक ही कामयाब हो सकते हैं, अगर वहां पर इंडस्ट्रियल ऐक्सपर्ट्स लगाए जाएं जो बताएं कि वहां पर कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है और साथ उनको चलाने में मदद भी दें, गाईडैंस भी दें। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब का जो अभिभाशण है, इसमें जो लक्ष्य दिए हैं, वह उत्तम हैं, और उनको पूरा करने के लिए हम हरियाणा की तरक्की के लिए इस सरकार के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार हैं।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना सी0सी0): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने है, यह इस सदन के माननीय सदस्य गुलाब सिंह जी जैन ने इस सदन के सामने रखा है और माननीय सदस्या जो ाी जी ने इसका अनुमोदन किया है। मैं भी इसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं उपाध्यक्ष महोदया आपका भी आभारी हूं, जो आप ने मुझे बोलने के लिए समय दिया। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाशण यहां सदन में दिया, वह काफी अच्छे ढंग का, व्यवस्थि और सुलझे हुए ढंग का था। मैं तो कहूंगा कि थोड़े भाब्दों में उन्होंनें हर बात को

उसमें ला दिया और लाने की चेश्टा भी की। कल्याणकारी राज्य के लिए जिन कार्यों का किया जाना बहुत जरूरी होता है, उन्हें इस अभिभाशण में भाामिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि उसके पहले ही पृश्ठ पर उन्होंने इन सारी बातों का वर्णन कर दिया कि इन कामों को करने मैं राज्य सरकार प्राथमिकता देगी। सदन में कई मैंबर साहबान ने उनके इस अभिभाशण की कटु आलोचना भी की है। मैं अर्ज़ करता हूं कि सदाचार तो यह हाता है कि वह सदाचार के नाते कुछ तारीफ की बातें भी कहते, लेकिन वे तो यहां तक कह गए कि इसमें धन्यवाद देने की कोई आव यकता ही नहीं है। मैं उन सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि सदाचार की जो बातें होती हैं, उनका पालन करना भी किसी संस्था के लिए सदन के लिए अत्याव यक होता है। उपाध्यक्ष महोदया, कल सदन के एक माननीय सदस्य ने सबसे पहले जो हमारे हरियाणा में हर गांव में बिजली देने की बात की गई है, उसकी कटु आलोचना की। मालूम नहीं उनको प्रान्त से प्यार नहीं या प्रान्त की कोई अच्छी बात सुनने में उनको कुछ बुराई महसूस होती हो। ख़ैर, यह भावना उनको मालूम होगी कि कैसी भावना है, क्योंकि यह उन्होंने कहे हैं, उनको वे पूर्णतया दे नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर सदस्य ने तो इन आंकड़ों की जांच नहीं करनी है, लेकिन सदन में जो विचार रख रहे हैं, वह अखबार में छपवाने के लिए रख रहे हैं, वे अखबार वालों पर अपना प्रभाव अव य डालेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रान्त की कोई अच्छी बात, भलाई की जो बात हो, चाहे वह बिजली की हो, चाहे कोई

और बात हो, उसको सुनकर, देखकर, हर्श ही नहीं, अपितु फख़ से हमारा सिर ऊंचा हो जाता है, लेकिन मालूम नहीं, उनको यह बात क्यों अखरी और कहने लगे कि हर वर्श बिजली का ही चर्चा सदन में होता है। अगर कोई अच्छी बात बार–बार कही जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कई प्रान्तों का उदाहरण दिया, लेकिन यह बात वे भूल गए कि आज तक सारे दे ा में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रान्त है, जिसमें भात–प्रति ात गांवों में बिजली पहुंची हो। लेकिन ये बात दिखाने के लिए कहना चाहते हैं कि हरियाणा के कम गांव हैं, जिनमें बिजली पहुंची है और दूसरे प्रान्तों के बहुत ज्यादा गांव हैं जिनमें बिजली गई है। लेकिन वे यह बात भूल गए हैं कि हरयाणा का जन्म थोड़े दिनों से हुआ है और इसके रिसोर्सिज बहुत कम हैं, लेकिन इस थोड़े से अर्से में हरियाणा ने जिस तेजी के साथ तरक्की की है, वह सराहनीय है और इसका श्रेय जाता है हमारे मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल को जिन्होंने समुचित प्रयास करके हर प्रकार के साधन जुटाए, इस प्रान्त की तरक्की को चार चांद लगाए। बिजली की बात वाकई सराहनीय है और आज हम फख़ से कह सकते हैं कि हमारे प्रान्त में भात–प्रति ात बिजली पहुंच गई है। एक और माननीय सदस्य ने कहा कि खर्चा बहुत किया गया। मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस लागत से हरियाणा में बिजली दी है, अगर उसके आंकड़े नापे जाएं, तो हो सकता है, आज उससे चार गुण कीमत पर भी बिजली देहातों में न पहुंचे कुछ सदस्यों ने कहा कि बिजली के कुनैक ान नहीं मिले। क्या कारण है क्यों नहीं मिले ? इसकी

वजह है दे ा के अन्दर आर्थिक संकट, उत्पादन की कमी, वस्तुओं का उत्पादन कम होना है। हो सकता है अगर आज हम बिजली देने की बात सोचते, तो पता नहीं कितने वर्श तक सोचते ही रहते, और बिजली न दे पाते। आज हमने हर गांव में बिजली दी, किसान के हर खेत में पानी लगाने के लिए बिजली का कुनैक्शन दिया और आगे देने के लिए तत्पर हैं, हमारी कोि ा ा है कि जब मैटीरियल उपलब्ध हो, तो बिजली दी जाए, ताकि बिजली देने से देहात का किसान खु ाहाल हो और खु ाहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आज के युग में बिजली देना और खास तौर से हमारे प्रान्त में बिजली देना, जो कृशि प्रधान प्रान्त है, वैसे तो सारा दे ा ही कृशि प्रधान है, ऐसे प्रान्त में जिसकी बहुत सी आबादी देहातों में रहती है, जिसके सभी कार्य क्योंकि बिजली पर निर्भर हो गए हैं, बिजली का मिलना आव यक है। उपाध्यक्ष महोदया, एक समय था, जब अखबार में खबर छपती थी कि भाखड़ा से बिजली मिलेगी और तब यह सोचा जाता था, कि इसको प्रयोग में कैसे लाया जाए, लेकिन आज हर जगह से पुकार आती है कि बिजली नहीं मिलती, बिजली की कमी है, इसका क्या कारण है ? इसका कारण उपाध्यक्ष महोदया, तरक्की है, प्रगति की बातें हैं, हम लोग तरक्की करते हैं और सारा दे ा तरक्की कर रहा है, इसीलिए यह मांग बढ़ रही है, बिजली की खपत बढ़ रही है। यह कैसे सोचा जा सकता था कि 1973–74 में इतनी बिजली की आव यकता होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने मुख्य मंत्री की दूरदि िता की दाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा

कि बिजली की खपत बढ़ेगी, चाहे कारखानों में बढ़ें, चाहे देहाती किसानों की आव यकता बढ़े। इस खपत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत से प्राजैक्ट्स के अन्दर अपना हिस्सा डाला है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मारफत अर्ज़ करूंगा कि इन प्रोजैक्टों में एक स्याल प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदे ा में है, जम्मू क मीर में सलाल प्रोजैक्ट है। यह बात उनके ध्यान में रही कि बिजली की खपत बढ़ेगी, इसीलिए इन प्रोजैक्टौं में अपना हिस्सा डाला। आज जो कमी हमें नजर आ रही है, कुछ अर्से के प चात् जब इन प्रोजैक्ओं से हमारा हिस्सा मिलने लगेगा तो मैं समझता हूं कि बिजली का संकट हमारे सामने नहीं रहेगा और जितनी बिजली की जरूरत होगी, उसके मुताकिब बिजली मिलनी आरम्भ हो जाएगी। कितनी दूरदि ता की बात है, लेकिन यह कहते हैं कि बिजली पहुंचाई नहीं गई, आपने किया क्या है। इस बात को देखते हुए मैं समझता था कि सदन में यह आंकड़े रखे जाएं इसमें दो राय नहीं है। पुरानी बिजली मन्त्री श्री रामधारी गौड़ ने बताया कि किसी मीटिंग में यह तय हुआ था कि सारे प्रान्तों में 50 प्रति ात बिजली 1980 तक दी जानी चाहिए, लेकिन हम अपनी सरकार के आभारी हैं कि इस समय के पूर्व ही 50 प्रति ात की बजाए सैन्ट–पर–सैन्ट बिजली गांवों में दी है और हमको तवक्को रखनी चाहिए कि आईंदा हमें जरूरत के मुताबिक पूर्ण रूप से बिजली मिलती रहेगी, इसके लिए हम कोि ा ा करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों का काम केवल यही है कि वे यही बात मन में

लेकर आलोचना करते हैं। आलोचना के उद्दे य से आलोचना करना मैं समझता हूं, निरर्थक है, व्यर्थ है।

एक दूसरा और पहलू है, जिस पर एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, वह है सर्विसिज़ के बारे में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन्होंने एक बात कही कि हरियाणा के अन्दर हरियाणा का कोई आफिसर नजर नहीं आता, सब बहार के अफसर नजर आते हैं। वे एक बात भूल गए कि सर्विसिज़ की रिक्रूटमैंट का एक ढंग होता है, एक नियम होता है। यह बात कहना कि एक ही प्रान्त के आफिसर हों, दूसरे प्रान्त के हों न, यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर अफसर ााही के खिलाफ हों, तो मैं इसकी ताईद करूंगा। यह जो कहते हैं कि पुराने आफिसर हैं, या दूसरी स्टेट के हैं, यह कोई अच्छी भावना नहीं है। अगर ये कोई और बात करते तो मैं भाायद उनके साथ सहमत होता लेकिन सिर्फ यह कह देना कि प्रान्त के बाहर के लोग आफिसर हैं, यह ठीक नहीं है। उन आफिसर्ज़ के अन्दर प्रान्त की भावना होनी चाहिए प्रान्त की तरक्की के लिए काम करने की भावना होनी चाहिए। अगर ऐसी बात करते, तो हम उनकी ताईद करते, लेकिन उनको डिस्करेज करना, डिफेम करना, कोई ठीक बात नहीं है। यह भाशा बोली जाती है, वह बोली जाती है, ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है। हमारे दे ा में कई भाशाएं बोली जाती है, विधान हमें इसकी छूट देता है, लेकिन ऐसी बातें यहां नहीं करनी चाहिएं। अगर कोई और बात कहते, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। कोई अधिकारी

किसी वर्ग को हो, किसी जाति का हो, किसी सूबे को हो, अगर उस अधिकारी के दिल में प्रान्त की तरक्की की धारण हो, तो वह अधिकारी बहुत अच्छा है, इससे बढ़ कर और कोई बात हो ही नहीं सकती, ऐसे अधिकारियों की सराहना करना मैं समझता हूं, उनके लिए ड्यू है, जो उनको मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे गवर्नर महोदय ने समाज के पिछड़े वगे, अनुसूतिच जातियों और जो समाज के बहुत पुराने अंग हैं और सदियों से दबे चले आते रहे हैं, उनकी चर्चा की है। उनकी भलाई के कार्यों के लिए बहुत सी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। उपाध्यक्ष महोदया, आजादी मिलने से पहले इस वर्ग की क्या हालत थी, यह सभी लोगों को मालूम है, किन्तु आजादी मिलने के बाद काफी राहत उनको मिली है, बहुत सी सुविधाएं नौकरी में भी और धन्धों में भी, उनको दी गई हैं। आजादी से पहले इस वर्ग की हिन्दुस्तान में क्या हालत थी ? इसके बारे में एक भाायर ने बड़ा ठीक कहा है कि ——

आह भाूद्र के लिए हिन्दुस्तान ग़मखाना है;

दर्दे इन्सानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है।

किन्तु आज जो उनके लिए किया गया है, उसका हमें फख़ है। आज वे समाज के अन्दर बराबरी के साथ रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और जीवन निर्वाह कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, कुछ सदस्यों ने कहा कि इस वर्ग के लिए

कुछ नहीं हुआ। यह बिल्कुल गलत बात है। काफी कुछ हुआ है। हां, यह कहना ठीक होगा कि काफी कुछ करना बाकी है। हम समाजवाद की भावना लेकर चले हैं, कल्याणकारी राज्य की भावना हमारे राज्य के सामने है। उनके लिए इसमें काफी कुछ किया जाना है, जिसके लिए सरकार प्रयत्न ाील है। आज हमारे बच्चे स्कूलों में, कालेजों में अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। उनकी फीस माफ होती है, उनको वजीफे मिलते हैं और नौकरी के लिए भी रिज़र्वे ान है। वे आई0ए0एस0 में आ सकते हैं और राज्य की सर्विस में भी उनके लिए रिज़र्वे ान है। विधान सभा और पार्लियामैंट में प्रतिनिधित्व करने के लिए भी उनके लिए रिज़र्वे ान है। मैं समझता हूं कि यह काफी कुछ है, लेकिन एक बात जो अभी बाकी है, देहात के अन्दर और भाहर के अन्दर भी, वह यह है कि यह वर्ग आर्थिक रूप से बहुत पीछे है। मेरे विचार के मुताबिक जब तक किसी वर्ग, किसी बिरादरी की, जाति की आर्थिक द ाा अच्छी नहीं होगी। तब तक वह समाज के अन्दर अपना सर ऊंचा करके नहीं चल सकती। आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना, इकोनोमिक फ्रीडम के बिना पोलिटिकल फ्रीडम उसके लिए बेकार होती है। मुझे खु ाी है कि सरकार इस बात से आगाह है, हमारी पार्टी आगाह है, लेकिन मैं एक सुझाव आपकी मार्फत उपाध्यक्ष महोदया रखना चाहूंगा। उनको रोजगार के साधन भी मुहैया कर दीजिए जिससे उनको कोई फिक्सड आमदीन गारंटिड आमदनी मिल सके। हम आज हरियाणा कल्याण निगम के द्वारा कर्जा देते हैं लेकिने देखने में क्या आता है ? जिस चीज़ के लिए

कर्जा दिया जाता है उस चीज़ के लिए उपयोग नहीं होता। इससे यह होता है कि उनके धन्धे पनप नहीं पाते। फिर यह भी बात है कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में बड़े कारखानेदार के साथ छोटे कार्यकर्ता का मुकाबला हो, तो वह छोटा उत्पादनकर्ता उसके सामने टिक नहीं पाता। तो इस समाज के लोगों के लिए ऐसे साधन उपलब्ध कराना जिससे उनको गारंटिड इनकम मिले, मैं समझता हूं, अति आव यक होगा। दूसरी बात जो उपाध्यक्ष महोदया, मैं रखना चाहता हूं, वह यह है दलित वर्ग तब तक ऊपर नहीं उठ सकता जब तक उसके अन्दर यह भावना उत्पन्न न हो कि मैंने समाज के अन्दर उठकर तरक्की करनी है, समाज के अन्दर बराबरी के साथ रहना है, और बराबरी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना है। मैं इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदया, कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। जब तक प्रत्येक आदमी यह बात नहीं समझेगा कि उसने खुद हिम्मत करके ऊपर उठना है, वह हर बात को सरकार के ऊपर न छोड़े तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो, उपाध्यक्ष महोदया, मैं गवर्नर साहब का आभारी हूं कि उन्होंने इस वर्ग के लिए प्रथम पृश्ठ पर ही कहा है कि हमने पिछड़ी श्रेणी के कल्याण को प्राथमिकता देनी है।

उपाध्यक्ष महोदया, विरोधी दल के साथियों ने ला ऐंड आर्डर की भी बात की। मैं आपकी मार्फत इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त के अन्दर ला ऐंड आर्डर की द ाा इस

वक्त वाक्या ही सराहनीय है। आप इसका दूसरे प्रान्तों के साथ मुकाबला करिए। वहां आप रात को नहीं चल सकते, क्योंकि वहां आपकी जान की इफाजत नहीं है। आप पड़ौसी प्रान्त के अन्दर ही देख लीजिए। वहां आए दिन कोई न कोई गड़बड़ होती है। मैं तो, इस सदन में यह बताना चाहता हूं कि ये भाई जो यहां ला ऐंड आर्डर के विरुद्ध बोलते हैं, गड़बड़ इन्हीं की वजह से ही होती है। ये प्रचार तो बड़े–बड़े महात्माओं का करते हैं लेकिन जिम्मदार ला ऐंड आर्डर के लिए खुद हैं। मैं पूछूं इनसे कहां गया महात्मा बुद्ध का सन्दे ा ? कहां गया महावीर का सन्दे ा कि दे ा के अन्दर, समाज के अन्दर हमें भाांति से रहना चाहिए ? भाांति से हर वर्ग में रह कर उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए ? ये सदन में कुछ कहते हैं, पब्लिक जलसों में कुछ कहते हैं, लेकिन तोड़–फोड़ के काम में सबसे आगे रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, इस बारे में तो मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि ये जो ला ऐंड आर्डर के ज्यादा केस पकड़े गए, ये इनकी वजह से ही पकड़े गए। इसलिए इनका ज्यादा ध्यान रखें। प्रान्त के अन्दर ऐसी बात का खतरा हमें तो मालूम नहीं पड़ता जिसके कारण ला ऐंड आर्डर को खतरा हो। हमारा ला ऐंड आर्डर बहुत अच्छा और सैटिसफैक्ट्री से ज्यादा अच्छा है। कुछ बातें इधर–उधर से होती हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते। उन बातों के लिए हर आदमी जिम्मेवार होता है। उनको रोकना तो आव यक है लेकिन मु कल है। फिर भी हमारे प्रान्त में बहुत अच्छी द ाा इसके बारे में है।

पिछले दिनों आपने देखा होगा, उपाध्यक्ष महोदया, चोर बाजारी के खिलाफ, स्मगलिंग के खिलाफ कुछ अभियान सभी प्रान्तों और दे ा में चला। कुछ लोग पकड़े भी गए, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी हुई। लेकिन बहुत से लोग हम में से ही उनके बचाव के लिए हाजिर हो जाते हैं। यह बड़ी गलत बात है लेकिन क्या करें, इस डैमोक्रेसी के अन्दर कई बुराइयां उत्पन्न भी हो जाती हैं और कई बुराइयों के जन्म के लिए हम खुद भी जिम्मेवार हैं। जब तक अपने अपने स्थान पर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को, अपने काम को जिम्मेवारी के साथ पूरा नहीं करता है, तब तक स्टेट के अन्दर, दे ा के अन्दर सारी बुराइयां समाप्त होने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदया, हमारे गवर्नर महोदय ने अभिभाशण में हर पहलू को छुआ है। खेती बाड़ी के बारे में उन्होंने कहा है और इरीगे ान के बारे में भी कहा है। हमारा प्रान्त एक कृशि प्रधान दे ा है। खेती बाड़ी का दर्ज़ा इसमें अहम है। यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि कृशि के क्षेत्र में जो तरक्की हमारे प्रान्त ने की है, वह प्र ांसनीय है। हरियाणा बनने के तुरन्त प चात् हम किस द ाा में थे, यह सबको मालूम है। उस समय अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था, जबकि आज हम बाहर भेजा करते हैं। आकस्मिक घटनाएं तो होती ही रहती हैं। कुदरत की मार यदि पड़ जाए, बारि ा समय पर न हो, सूखा पड़ जाए, या फ्लड आ जाए, इन बातों का तो न सरकार कुछ कर सकती है, न

आप कुछ कर सकते हैं और न हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी खेती बाड़ी के लिए मुझ इतना मालूम है कि हमारी मौजूदा सरकार ने पानी के साधन जुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिन जगहों पर पानी पहुंचना मु कल था, नामुमकिन था, वहां इस सरकार ने चाहे उठान योजना बनाकर या किसी और ढंग से पानी देने की को ा ा की है। मेरे अपने क्षेत्र में मुझे मालूम है, लोग बहुत गहरे बोर करवा कर थक कर बैठ जाया करते थे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अपने अधिकारियों ने चाहे, वे एम0आई0टी0सी0 के हैं या चाहे एस0एफ0डी0ए0 के हैं, बड़ी मेहनत से स्कीमें बनाकर किसानों को पानी देने की योजनाएं बनाई हैं। और आज किसानों के लिए 150 के करीब ट्यूबैवैल्ज़ वहां लगाए हैं, और हर हिसान के लिए को ा ा की जा रही है कि वह पानी ले। आप इस बात से अच्छी तरह से अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिस किसान का खेत सदियों से सूखा पड़ा हो वह –– (व्यवधान) ––

उपाध्यक्ष: ये ट्यूबवैल्ज़ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): अम्बाला तहसील में लगे हैं। छोटी–छोटी लघू सिंचाई की योजनाएं बनाकर साधारण किसान को हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाने की को ा ा की है। हमारी सरकार का इस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। हमारे यहां अम्बाला जिले में S.F.D.A. तथा मुफाल एजेंसी बहुत ही सुचारू रूप से काम करती रही है। पिछले दिनों उनके

जो इंचार्ज थे, उन्होंने वि ोश इंट्रैस्ट लेकर इतना काम करती रही है। जिसकी जितनी तारीफ की जाए, उतनी ही कम है। मुझे खु ाी है कि देहातों के अन्दर जो छोटे किसान थे, जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनको कर्जा दिया और साथ में सबसिडी भी दी। उन्होंने इस तरह से रोजगार के साधन बढ़ाए। डेरी–फार्म, मिल्क सोसायटीज़ बनीं। डेरी–फार्म से तो वहां के गरीब लोगौं ने दूध बेचकर अपने गुजारे के काफी साधन बनाए हैं। एग्रीकल्चरिस्ट जो मुफाल स्कीम के तहत आते हैं, उनको भी काफी लाभ पहुंचा है। ऐसी–ऐसी योजना हैं जो कि हमारे बहुत से सदन के माननीय सदस्यों ने रखी हैं कि जब तक छोटे किसानों के लिए ऐसे साधन उपलबध नहीं कराए जाएंगे, जिससे उनकी आमदनी सप्लीमैंट हो सकते तब तक उनका भला नहीं हो सकता। जैसे कि मिल्क डेरी है, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा सुचारू रूप से चल सकती है। सुझाव तो और भी हैं, जैसे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, उनसे भी गरीब लोगों का भला हो सकता है।

इसके साथ–साथ हमारे प्रान्त के अन्दर को–ऑप्रेटिव मूवमैंट का भी जिक्र गवर्नर महोदय ने किया है .....।

Deputy Speaker: I will request the hon. Member that he should wind up lease. He has spoken for more than twenty five minutes.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): को–आप्रेटिव मूवमेंट के तहत काफी बाम प्रान्त में हुआ है। हरियाणा प्रान्त में बहुत सी

सोसायटीज हैं। इस बारे में एक बात कहूंगा कि जिस वर्ग को इन को–आप्रेटिव मूवमैंट के तहत असलियत में फायदा पहुंचना चाहिए था, उनको फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों को अधिक कर्जे की जरूरत है, जिन्होंने अपने काम को चलाना है उनको इस मूवमैंट से बहुत कम लोगों को फायदा पहुंचा है। आज तक इस मूवमैंट से उन लोगों ने लाभ उठाया है, जिनको पैसे की आव यकता नहीं थी। आपको ये देखेन को भी मिलेगा कि बहुत सी सोसाइटीज के खिलाफ केसिज़ भी हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी, ऐसा मैं वि वास रखता हूं। यदि कृशि के क्षेत्र में किसानों के लिए इस प्रदे ा में छोटे–मोटे जो काम हो सकते हैं, वे इस को–आप्रेटिव मूवमैंट की मार्फत ही हो सकते हैं। अगर उनको सुचाय रूप से चलाया जाये तो छोटे लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। इसके साथ–साथ उपाध्यक्ष महोदया एक बात अव य कहना चाहूंगा कि इन सोसाइटीज़ को बैकों से –– (घंटी) ––

Deputy Speaker: Please wind up. I havt to give two minutes to Chaudhri Peer Chand also.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): मैं अर्ज़ कर रहा था कि इन सोसायटीज़ को बैंको से जो कर्जा मिलता है, उसके साथ उनको कम्पलसरी पचास परसैन्ट खाद लेना पड़ता है। मेरे अपने ब्लाक में ऐसा हैं सारे ब्लाक में पानी नहीं मिलता है। मैं इस विशय में निवेदन करूंगा कि खाद कम्पलसरी तौर पर न दिया जाए। केवल

खाद उन्हीं को दिया जाए, जिनको जरूरत है। –– (घंटी)–– उपाध्यक्ष महोदया, आप बहुत जोर डाल रही हैं। मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्षः मुख्य मंत्री जी ने भी बोलना है। उधर से दूसरे मैंबरों ने भी बोलना है। आपने आधा घंटा ले लिया। अभी मिनिस्टर साहब को भी टाईम देना है।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): उपाध्यक्ष महोदया, मैं अभी वाईंड अप कर रहा हूं हमारे सम्मानित सदस्यों ने ि ाक्षा में तरमीम लाने की बहुत सी तजवीज़ें सदन के सामने पे ा कीं। हर तरफ से यह विचार आता है कि ि ाक्षा पद्धति को बदलना आव यक है, लेकिन यह तो वही बात है कि कोई किस्ती मंझदार में हो, उस टाईम पर तजवीज़ करते हैं कि इसको निकाला कैसे जाए ? सवाल तो यह है कि कोई भी सदस्य यह सुझाव देने को तैयार नहीं है कि इसको निकाला कैसे जाए। किसी भी सम्मानित सदस्य ने सुझाव नहीं दिया कि ि ाक्षा प्रणाली को कैसे ठीक किया जाये। कोई ऐसा सुझाव आना चाहिए जिसको भारत सरकार भी कन्सीडर करे और राज्य सरकार भी सिफारि ा करे कि इस ि ाक्षा प्रणाली में यह चेंज आए। मैं सरकार से फिर यह निवेदन करूंगा कि ि ाक्षा प्रणाली में चैंज लाने के लिए ि ाक्षा ऐक्सपर्ट कुछ ऐसे सुझाव दें, जिससे हमारी ि ाक्षा आज की आव यकता के मुताबिक हो सके। जॉब–ओरिएंटिड हो सके। आज के जमाने की समस्याओं को हल करने वाली हो सके।

अन–ऐम्प्लायमैंट का जिक्र भी गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाशण में किया है। मैं तो यह कहूंगा कि अन–ऐंप्लायमैंट का कारण हमारी आजकल की ि ाक्षा पद्धति भी है और खास तौर से हमारे गरीब वर्ग के लोग, जो थोड़ी बहुत ि ाक्षा प्राप्त करके, दसवीं पास करके या बी0ए0 पास करके केवल सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाए, जिनके पास घरों में कोई धन्धे न हों। जिन लोगों के पास घरों में धन्धे हैं, साधन हैं, उनको पहले नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। पहले उन लोगों कों नौकरी मिलनी चाहिए, जो बिल्कुल ही बेकार हैं। इस प्रकार से अन–ऐम्प्लायमैंट जल्दी दूर हो सकती है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया। जो गवर्नर महोदय ने अभिभाशण दिया है, वह बहुत अच्छा है और इस समय जो प्रस्ताव सदन के सामने है, उसको पास किया जाए।

उपाध्यक्षः चौधरी पीर चन्द जी आपको दो मिनट दिए जाते हैं।

चौधरी पीर चन्द (बरवाला–एस0सी0): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए तो बहुत थोड़ा टाईम दिया है, लेकिन फिर भी इस थोड़े समय में कुछ विचार आपके सामने रखूंगा। आज हमारे राज्यपाल महोदया के अभिभाशण पर चर्चा चलते हुए कई रोज हो गए। सरकारी पक्ष के भाइयों में से काफी बोले हैं। उन्होंने बढ़–चढ़कर इस सरकार की बहुत बड़ाई की है। हमारे

अपोजी ान के भाइयों ने भी इस सरकार के जो कारनामे हैं और जो सही हैं, वे यहां पर रखे हैं, वे आपके सामने आए हैं। मैं इसी बार को लेकर एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय ने यह अभिभाशण बनवाया तो है, जिसको उन्होंने, यहां पढ़ कर सुनाया है, उसके अन्दर काफी ऐसी बातें हैं, जो हरियाणा की डिवैल्पमैंट के बारे में हैं। इसके अन्दर हरियाणा की बड़ी भारी डिवैल्पमैंट दिखलाई गई है। डिवैल्पमैंट कागजों के अन्दर तो है, लेकिन असलियत में कुछ और ही बात है। जैसा कि अभी बिजली कि डिपार्टमैंट के मुत्ताल्लिक काफी से ज्यादा कहा गया और इस बात पर रो ानी डाली गई कि इससे तमाम हरियाणा को बड़ा लाभ हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके जरिए सदन को बताना चाहता हूं कि इस बिजली से जमीदारों को नुक्सान ही हुआ है, लाभ नहीं हुआ। देहात के लोगों को यह ख्याल था कि बिजली से बहुत लाभ होगा। उनके मन में यह वि वास था कि बिजली से काफी उपज बढ़ेगी, काफी धन प्राप्त होगा, लेकिन उलट हुआ। हर व्यक्ति से कर्जा लेकर, जेवर बेचकर, जमीन गहने रखकर ट्यूबवैल्ज़ लगाए, बिजली विभाग से कुनैक ान लिए, लेकिन आज हालत क्या है। पहले तो दो–चार एकड़ का त कर लिया करते थे, लेकिन आज उनकी सारी जमीन खाली पड़ी हुई हैं तो यह हालत है बिजली विभाग की। इस विभाग की गलती की वजह से जमींदारों की तकरीबन 20–30 परसैंट मोटरें सड़ चुकी हैं। गांव के लोागों को टाईम पर यह पता नहीं होता कि कब बिजली छोड़ते हैं और कब बन्द करते हैं। इससे जमींदारागों की तमाम

मोटरों पर असर पड़ता है और मोटरें सड़ती हैं। इससे तमाम जमींदारों का नुक्सान हुआ है। यह तो है बिजली विभाग के कारनामे।

17.00 बजे

अब मैं उस क्लास की तरफ जाता हूं, जिसके लिए इन्होंने काफी से ज्यादा बोल–बाला किया हुआ है कि हम उनको बहुत कुछ दे रहे हैं। अभी थोड़ी दे पहले हमारे साथी चौधरी ि ाव राम वर्मा जी ने भी बताया कि लोन किसको मिलता है। लोन मिलता है, तो हरिजनों को नहीं, गैर हरिजनों को मिलता है। उन्होंने दूसरे ही ढंग से सोसाइटियां बनाईं, पैसा लिया और ट्रैक्टर खरीदे। हरिजनों को अगर कर्जा मिलता भी है तो 500 या 1000 रुपए कर्जा देते हैं। कर्ज़े की थोड़ी सी अमाउंट जो उन्हें मिलती है, इससे डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप अन्दाजा लगा सकती हैं कि इससे उनकी माली हालत में क्या सुधार हो सकता है। कैसे वे लोग कुछ कमा सकते हैं, क्या वे इंडस्ट्री लगा सकते हैं ? वह तो बेचारे मजदूरी भी नहीं कर सकते। यह हालत इस (हरिजन) निगम की है, जो हरियाणा सरकार ने हरिजनों के नाम से बनाई गई है। यह सरकार इस निगम का काफी से ज्यादा भाोर– ाराबा करती है। इस बात की भी आज यह सरकार चर्चा करती है कि हम हरिजनों को प्लाट देंगे।

लाला रुलिया रामः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा। इन्होंने फरमाया है कि निगम की तरफ से हरिजनों के बजाए गैर–हरिजनों को लोन मिला है। कोई ऐसा केस बताया जाए, जिसमें हरिजनों के सिवाय किसी गैर आदमी को कर्जा मिला हो ? .... (व्यवधान) ..

एक आवाजः नाम भी बता दो।

चौधरी पीर चन्दः ये नाम पूछते हैं तो मैं बता देता हूं। हिसार के अन्दर हमारे बाबू गुलाब सिंह जी ने एक फर्म बनाई जिसके द्वारा 22 ट्रैक्टर लिए गए, जिसका कई दफा यहां असैम्बली में जिक्र आया। उसकी कोई इनक्वायरी नहीं हुई, न उसकी कोई चर्चा है। उस हरिजन के पास अब भी कि तों के लिए नोटिस पहुंचता है और वह आदमी नोटिस हमें दिखलाता है। न उनके पास ट्रैक्टर हैं, न उनके पास जमीन है और न ही ऐसे कोई साधन हैं कि वे ट्रैक्टर चला सकें, लेकिन उनके नाम कर्जा लिया गया है और उस कर्जे का वह तमाम पैसा खाया गया। वह सारी बातें अखबारों में आई हैं ...(व्यवधान)....

चौधरी चांद रामः टाईम्ज़ आफ इंडिया पढ़ लें। (Interruptions)

Deputy Speaker: Order please. Mr. Chand Ram you cannot suggest anything to the hon. Member.

चौधरी पीर चन्दः यह इस अखबार में भी और दूसरी अखबारों में भी छपा है। मैं यह मानता हूं कि 14 में से दो रह गए, लेकिन मेरे पास इसका इलाज नहीं है। .... (घंटी) .. मुझे थोड़ा सा टाईम तो और बोल लेने दें।

उपाध्यक्षाः आपको दो मिनट और दे सकती हूं। ... (व्यवधान)...

चौधरी पीर चन्दः मैं आपका ध्यान इधर भी दिलाना चाहता हूं। क्वै चन आवर के दौरान यह पूछा गया कि हरिजनों को प्लाट के साथ–साथ क्या कोई ग्रांट वगैरह भी दी जाएगी ? तो हमारे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 900 रुपए हम ग्रांट के रूप में देते हैं। ऐसे कहते हैं कि जैसे कि बड़ी भारी रकम दे रहे हैं और नौ सौ रुपए से बहुत बड़ा मकान बन सकता है। इस महंगाई के जमाने में जबकि ईंट का भाव ही डेढ़ सौ रुपए प्रति हजार है, 25–30 रुपए प्रति थैला सीमेंट है और 15–16 रुपए राज की दिहाड़ी है, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार का हरिजनों की तरफ कितना ध्यान है। ये भी कहते हैं कि बड़ी भारी डिवैल्पमैंट हो रही है, बहुत बढ़िया कारोबार है, लेकिन मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि आप हरिजनों की यह हालत है कि उनको खाने के लिए एक टाईम की रोटी भी नहीं मिलती। कई ऐसे भाख्स होंगे, जो ऐसी हालत में हैं क्योंकि सब के सब काम बन्द हो चुके हैं। सरकार को कोई डिवैल्पमैंट का काम नहीं चल

रहा है। नहरों के काम बन्द हैं, सड़कों के काम बन्द हैं और बिजली के काम बन्द हैं। जो मजदूर पहले लगे हुए थे, उनको हटाया गया। आज हालत यह है कि उनको खाने को रोटी भी नहीं मिलती। एक तरफ तो गैस जलती है और रुपया पानी की तरह बहाया जाता है और दूसरी तरफ हालत यह है कि मजदूर को खाने को रोटी भी नहीं मिलती। तो फिर कैसे यह सरकार दावा करती है कि हम हरिजनों को बहुत कुछ दे रहे हैं ? आज हरिजन बेचारे दु:खी हैं। आज उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं। मैं कहता हूं कि डिवैल्पमैंट करनी है, तो पहले उनके खाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

उपाध्यक्षः चौधरी पीर चन्द जी, अब आप खत्म कीजिए, आपके काफी समय ले लिया है। (इस समय चौधरी पीर चन्द जी बैठ गए।) श्री बनारसी दास जी, आप बोलिए ..... (व्यवधान) ...

चौधरी पीर चन्दः मैडम, मुझे वाइन्ड आप करने के लिये तो दो मिनट दें। .... (व्यवधान) ...

उपाध्यक्षाः आप बैठ गए थे, इसलिए मैंने अब मंत्री जी को बोलने के लिए कह दिया है।

चौधरी चांद रामः गुप्ता जी, क्या आपके बाद मुख्य मंत्री जी भी जवाब देंगे ? (व्यवधान) ....

उपाध्यक्षाः हां जी, उन्होंने भी अभी बोलना है। ... (व्यवधान) ...

चौधरी चांद रामः जब उन्होंने बोलना है, तो आपके बोलने की क्या जरूरत है ?

सिंचाई एंव विद्युत मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त): उपाध्यक्ष महोदया, इनकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि जब सदन के नेता ने बोलना है और उन्होंने सारी डिबेट का जवाब देना है तो मेरी कोई आव यकता नहीं थी कि मैं बीच में बोलने के लिए आपसे समय लूं। परन्तु कुछ बातें कल इस सदन में ऐसी कही गई जो सीधी मुझसे सम्बन्ध रखती हैं यही कारण है कि मुझे आपसे समय मांगना पड़ा। मैं खास तौर से बिजली बोर्ड के बारे में इस सदन के सम्मानित सदस्य और मेरे बहुत पुरानी मित्र चौधरी दल सिंह ने बहुत कुछ बातें कहीं। उपाध्यक्ष महोदया मैं आपको वि वास दिलाता हूं कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध मैंने कोई बात नहीं कहनी है। मैं केवल उन्हीं बातों का उत्तर देना चाहता हूं जो कल कही गई हैं। उपाध्यक्ष महोदया, जितने हमारे विरोधी दलों के सम्मानित सदस्य अथवा नेता हैं, उनको यह हक हासिल है कि वे सदन में बोलें और सरकार की नुक्ताचीनी करें। विभिन्न विभागों के अन्दर जो त्रुटियां या कमियां हैं उनको निकला कर हाउस के सामने रखें। अगर मेरे दोस्त हैल्दी क्रिटिसिज़म करते और सही बात सदन में कहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं उनकी आलोचना का दिल से स्वागत करता और मैं इस बात का यकीन दिलाता कि उन त्रुटियों को या उन कमियों को हम दूर करने की पूरी–पूरी चेश्टा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, आप तो

जानती हैं आप विभाजन से पूर्व भी लैजिस्लेटर रही हैं, कि डैमोक्रेसी अथवा लोकतन्त्र के अन्दर जितना महत्त्व सत्तारूढ़ दल का है, उतना ही महत्त्व विरोधी दल का है। लेकिन विरोधी दल के मेरे मित्र यदि ठीक ढंग से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें तो बड़ी अच्छी तरह से हमारे दे ा में लोकतन्त्र पनप सकता है और आगे बढ़ सकता है, लेकिन केवल गलत बातें कहीं जाएं, और गलत आंकड़े सदन में प्रस्तुत किए जाएं या जनता को गुमराह करने की बात की जाए, तो विरोधी दल का ऐसा रोल, दे ा या लोकतन्त्र के हित के लिए अच्छा नहीं है। चौधरी दल सिंह जी बड़े विस्तार के साथ बोले। उन्होंने बताया कि राज्यपाल महोदय दो–तीन साल से वही बात यही आकर दोहरा देते हैं।

परन्तु चौधरी दल सिंह जी जब कभी बजट पर बोलते हैं, तो वही बातें तीन साल से दोहरा रहे हैं, जो बातें वह आज से पिछले साल कह चुके हैं या उससे यह साल कह चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आपको भी याद होगा कि पिछले साल या उससे पिछले साल इन्होंने कृशि की पैदावार के आंकड़ें दिए थे, ईयरवाइज़ आंकड़ें दिए थे, और उसके बाद हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने उनका बड़ा माकूल जवाब दिया था, लेकिन वे कल वही आंकड़ें फिर दोहरा रहे थे। वही बिजली बोर्ड की बात, वही लूट खसूट की बात, वही दिवाला निकलने की बात, यही सब बातें जो पिछले साल कही थीं, कल फिर दोहरा दीं। उपाध्यक्षा महोदया, यह तो रिकार्ड की बात है। आप इनकी गत वर्श की स्पीच

निकलवा कर देख लें, तकरीबन वह ऐसी बात अगर तीन दफा दोहराने की आव यकता हो, तो वह बात दोहराई जाती है और वह ऐसी बात है, जो तमाम प्रदे ा की उन्नति, उसके विकास से और उसके हित से सम्बन्ध रखती हैं लेकिन गलत बार–बार दोहराई जाए, इससे ज्यादा भार्म और लज्जा की और क्या बात हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था कि चौधरी दल सिंह जब तक बोले तो .... (व्यवधान) ....

Deputy Speaker% No Interruptions please.

चौधरी चांद रामः आन ए प्वांयट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, भार्म और लज्जा पार्लियामैंट्री भाब्द हैं या अनपार्लियामैंट्री भाब्द हैं ?

उपाध्यक्षाः उन्होंने किसी के लिए नहीं कहा बल्कि भार्म और लज्जा की बात कहा है।

चौधरी चांद रामः Again on a point of order. डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं क्लैरीफिके ान चाहता हूं। सवाल यह है कि भार्म और लज्जा कहीं भी इस्तेमाल होता है, तो उसका कनटैकस्ट नहीं देखते। The very words 'sharm and lajja' are unparliamentary.

उपाध्यक्षाः अगर भार्म और लज्जा किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए, तो मैं देखती कि यह पार्लियामैंट्री है या

अनपार्लियामैंट्री है। यह मेरी रूलिंग है। उन्होंने कहा कि यह भार्म की बात है।

श्री बनारसी दास गुप्तः उपाध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि चौधरी दल सिंह जब बोलते हैं, तो बिजली बोर्ड पर हमला करते हैं। कल जब उन्होंने बोलना भ्रारू किया, तो उस वक्त मैं स्पीकर साहब के चैम्बर में था। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि चौधरी दल सिंह ने बोलना आरम्भ कर दिया है वह अव य ही बिजली बोर्ड पर बोलेंगे। इसकी वजह क्या है ? वास्तविकता यह है कि एक व्यक्ति श्रावण में अन्धा हो गया था, उसको सारीह उमर हरा ही हरा दिखाई दिया। तो वही बात चौधरी दल सिंह पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा और यह तीन–चार मास के लिए इरीगे ान और पावर मिनिस्टर बन गए। इन्होंने उस समय कुछ बातें देखीं होंगी, वही बातें इनको 24 घंटे नजर आती है। यह इरीगे ान एंड पावर मिनिस्ट्री यह लहराती झन्डी, यह कार कोठी इनके दिमाग से उतरती नहीं। इसमें मेरा क्या दोश है ? मैं इससे क्या कर सकता हूं ? जब इनको मौका मिला तो मिनिस्टर बने और उसके फौरन बाद जब इलैक ान लड़ा, तो लोगों ने इनका फातिहा पढ़ दिया। क्योंकि इनके कारनामें ही ऐसे थे। कुछ दिन के लिए उनको काम मिला और उन्होंने कुछ किया नहीं। यह फिगर्ज़ और आंकड़ों के चक्कर में बहुत पड़ते हैं। कोई किताब अपने साथ में रखते हैं और उसमें से पढ़ कर आंकड़ें सदन के सामने पे ा करते हैं

इन्होंने कहा कि ग्रामों की संख्या एक जगह पर 6670 है, एक जगह पर 6731 है और एक जगह पर 6669 लिखी है। तो हरियाणा के अन्दर गांव कितने हैं, यह मैं आपके सामने स्पश्ट करना चाहता हूं कि 6669 की जगह 6670 मिस प्रिंट हो गया है। 69 और 70 में केवल एक का फर्क है। यह मिस–प्रिंट है। दूसरी बात इन्होंने कहीं कि एक जगह तो 6669 गांव इलैक्ट्रिफाई कर दिए लिखा है और दूसरी जगह 6731 इलैक्ट्रिफाईड कर दिए। हरियाणा में 6669 ग्राम है और इसके अलावा 62 कस्बें हैं अगर 6669 और 62 को जोड़ा जाए तो 6731 हो जाते हैं। यह कोई गलत बात नहीं कही कि सारे के सारे 6669 गांव इलैक्ट्रिफाई कर दिए। दूसरी जगह लिखा है कि 6731 इनक्ल्यूडिंग टाउन्ज़ कर दिए हैं। इसमें कौन सी गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदया, उस किताब के अन्दर स्पश्ट लिखा है इनकल्यूडिंग टाउन्ज़ और एक जगह खाली विलेजिज़ की फिगर दी है। यह तो इनकी फिगर्ज़ की बात है। अब आप बिजली बोर्ड के काम की बात देखिए। कभी यह बिजली बोडे के चेयरमैन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी किसी और आफिसर पर इल्जाम लगाते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, सरकारे के अन्दर अथवा किसी फर्म के अन्दर किसी भी व्यक्ति की योग्यता और उसके काम की प्र ांसा होती हैं। हमारे बिजली बोर्ड ने पिछले चार–पांच साल के अन्दर जो भाानदार रिकार्ड तमाम हिन्दुस्तान में कायम किया है, वह एक मिसाल है। इतिहास उसको भुला नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति नुक्ताचीनी करने की दृश्टि से नुक्ताचीनी करता है, तो उसका कोई इलाज नहीं। जो व्यक्ति

इस सदन में अपना स्पश्टीकरण न दे सके, अपनी सफाई पे ा न कर सके, उसके खिलाफ इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कल कुछ भाब्द प्रोसीडिंग्ज़ से निकालने केलिए प्रार्थना की थी। यह कहा जा सकता है कि सरकार में भ्रश्टाचार है, सरकार के अफसरान ठीक नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई सदस्य इल्जाम नहीं लगा सकता है। यह लोकतन्त्र की परम्परा के विरुद्ध है। अब मै। आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड ने क्या काम किया है। जब हरियाणा बना तो सन् 1966–67 में कुल 1312 गांवों में बिजली थी और 1967–68 में वही 1312 गांवों में बिजली रही। इस अर्से में चौधरी दल सिंह भी वज़ीर रहे और एक दूसरी सरकार भी आई जो मु कल से आठ महीने रही। यह कहते हैं कि हमारी सरकार थोड़े दिन ही सही, इतने थोड़े टाईम में हम कैसे काम कर सकते थे। परन्तु मैं कहता हूं कि बंसी लाल की सरकार जब एक साल में तीन हजार गांवों को बिजली दे सकती है तो ये चार महीने में दो सौ चार गांवों को तो बिजली दे सकते थे। लेकिन एक को भी नहीं दी क्योंकि इनकी नीयत नहीं थीं काम करने की क्योंकि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था सिवाय झंडी लहराकर भाान दिखाने के। बस एक ही प्रोग्राम इनके सामने था, और वह खम हो गया और फिर मौका नहीं मिला। मैं बता रहा था कि 1967–68 में उतने ही गांव रहे, एक भी वृद्धि नहीं हुई। 1968–69 में जब सइ सरकार ने बागडार अपने हाथ में ली तो 1525 गांवों में बिजली पहुंच गई। यानी 1968–69 में 213 गांवों में बिजली दी गई और 1969–70 के

अन्दर 3428 गांवों में बिजली पहुंचा दी गई, यानि 1903 ग्रामों में तकरीबन दो हजार गांवों को बिजली और दी। 1970–71 के अन्दर 6731 इनक्ल्यूडिंग टाउन्ज़ जिनकी संख्या 62 है, के अन्दर बिजली पहुंच गई। यानी एक साल के अन्दर 3303 गांवों को बिजली दी गई, जो कि हिन्दुस्तान कमे अन्दर किसी भी बिजली बोर्ड ने इतने थोड़े समय के अन्दर इतनी भारी संख्या में ग्रामों में बिजली नहीं दी। क्या कहते हैं वे भाई ? क्या वे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इतने गांवों को बिजली नहीं दी गई। वे आखिर किस बात की नुक्ताचीनी करते हैं ? किस बात के आंकड़े देते हैं, यह बात एक दर्पण की भांति हरियाणा के सामने और इस सदन के सामने और सारे भारत के सामने स्पश्ट है। उपाध्यक्ष महोदया सन् 61 की जनगणना के अनुसार वह आंकड़े मैंने बताए हैं। इससे आगे चलकर उन्होंने एक बात ट्यूबवैल्ज़ के बारे में कही कि कितने ट्यूबैवैल्ज़ को एनरजाइज़ किया। उसमें भी इन्होंने कुछ फिग्र्ज़ कोट की कि एक जगह पर 1 लाख 33 हजार कह दिया और एक जगह पर 1 लाख 49 हजार कह दिया, कौन सी फिग्र्ज़ ठीक है ? मैं कहता हूं कि ये दोनों फिगर ठीक हैं। 1 लाख 33 हजार भी ठीक है, 1 लाख 49 हजार भी ठीक है। अगर वह 60 हजार कह दें, तो वह भी ठीक है। वह कैसे ? वह मैं आपको बता देता हूं। 1 लाख 33 हजार ट्यूबवैल्ज़ बिजली बोर्ड ने एनरजाईज किए और कुछ ट्यूबैवैल्ज़ हरियाणा में ऐसे हैं, जो कि डीजल से चलते हैं। जब बिजली के हैड के नीचे ट्यूबैवैलों का नम्बर दिया जाता है तो 1 लाख 33 हजार और जब ऐग्रीकल्चर हैड के नीचे

यह नम्बर दिया जाता है, तो 1 लाख 49 हजार दिया जाता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदया, यह दोनों गलत बातें नहीं हैं, दोनों ही सही हैं। इसमें कोई भ्रम फैलाने वाली बात नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात तो ये लोग मानेंगे कि जब हरियाणा बना, उस वक्त हरियाणा में ट्यूबवैल्ज़ की संख्या केवल 29 हजार थी जो कि बिजली से चलते थे उस अर्से में कई सरकारें आईं और गईं लेकिन नलकूपों की संख्या बढ़ी नहीं। इस सरकार ने पिछले चार–पांच सालों में एक लाख से ऊपर ट्यूबवैल्ज़ को बिजली दी है। क्या यह रिकार्ड नहीं है, यह कोई काम नहीं हैं ? यह इस सरकार का और बिजली बोर्ड का एक भाानदार काम नहीं है जो इतने कुनैक ान्ज़ दे दिए, तो फिर ये लोग किस प्रकार की नुक्ताचीनी करते हैं ? आप एक बात और देखिए, चौधरी दल सिंह जी ने यहां पर पर–कैपिटा कन्ज़म्प ान की बात कही कि ये बिजली बोर्ड वाले क्या भोखी मारते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया और इसके साथ उन्होंने कुछ फिगर्ज़ कोट की। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त हरियाणा बना या जिस वक्त चौधरी बंसी लाल जी ने हरियाणा की बागडोर अपने हाथ में सम्भाली, उस वक्त हरियाणा में 57 यूनिट पर–कैपिटा कन्ज़म्प ान थी और आज 132 यूनिट पर–कैपिटा कन्ज़म्प ान है। आप मुझे बतलाइए कि क्या यह काम मुंह बोलती तस्वीर नहीं है ? क्या यह आलोचना करने वालों के मुंह के ऊपर तमाचा नहीं है ? ––(तालियां ––विघन –– ाोर) –– (चौधरी चांद राम जी की तरफ इ ाारा करते हुए) आपने तो

चन्दा इकट्ठा करना है, चन्दे वालों को तो कोई घाटा नहीं, कमाने वालों को घाटा रहता है।

चौधरी दल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है, मिनिस्टर साहब गवर्नर साहब के एड्रैस पर बोल रहे हैं या कि चन्दे की बात कह रहे हैं, कितनी इन्सल्ट की बात है, यह एस्प र्न पार्टी के ऊपर ही आता है –– (ाोर) ––

चौधरी चांद रामः (मन्त्री महोदय की तरफ इ ाारा) आप तो गांव गांव में मालाएं डलवाते आ रहे हो, वह क्या है ?

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। यहां पर चन्द्र की बात कही गई है, चन्दा तो हम भी लेते हैं, चन्दा लेना बुरी बात नहीं है लेकिन चन्द्र को खुर्द–बुर्द करना तो बुरी बात है। –– (ाोर) ––

श्री बनारसी दास गुप्तः तो उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके सामने एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। एक आव यक बात बतलाना चाहता था कि हमारे मित्र ने एक बात कह दी थी कि हरियाणा बिजली की दृश्टि से सबसे पीछे है। पहली बात बताई कि 57 से अब 132 यूनिट तक पर–कैपिटा कंजम्प ान पहुंच गई। पंजाब के अन्दर बतलाई 168.63 यूनिट पर–कैपिटा कंजम्प ान। लेकिन पंजाब के इन आंकड़ों में एक रहस्य की बता

है, वहां नंगल–फर्टिलाइज़र फैक्टरी है, जिसमें बड़ी कंजम्प ान होती है और वह सैन्ट्रल पूल से होती है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो पंजाब की पर–कैपिटा कंजम्प ान हमसे कम हो जाती है। तमिलनाडू की उन्होंन बतलाई 131.99, बंगाल की बतलाई 106.55, गुजरात की बतलाई 109.19, मैसूर की 113.60 और हमारी 132 यूनिट। इससे साम है कि हमारी प्रति व्यक्ति खपत हाइऐस्ट है। आज भी हरियाणा की पर–कैपिटा कंजम्प ान इाइऐस्ट है, फिर भी ये लोग गलत आंकड़े यहां देकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं इससे आगे चलकर उन्होंने लाइन लौसिज़ की बात कही। अगर बोर्ड के अन्दार ऐसी बात होती है तो हम उसे ठीक करना चाहते हैं, सुधार किया भी है। आप सोचें कि जहां गांव–गांव के अन्दर बिजली का प्रसार हुआ हो, जहां गांव–गांव के अन्दर खम्भों का जाल बिछा दिया गया हो, वहां पर लाइन लौसिज़ भी होंगे और इसकी बाकत पी0ए0सी0 ने अपनी रिपोर्ट में मैं ान भी किया है, पी0ए0सी0 का यह काम हैं इमने सैन्ट–परसैन्ट रूरल इलैक्ट्रीफिके ान किया तो लाइन लौसिज बढ़कर 27.30 हुए, यह अधिक है। इसके बाद बिजली बोर्ड ने, उसके अधिकारियों ने, तथा सरकार ने कहा कि लाइन लौसिज को कम किया जाए जिस पर अमल हुआ तो आज हमारे हरियाणा के अन्दर 21.7 लाइन लौसिज हैं। हमारे जितने पड़ोसी प्रदे ा हैं, खासतौर पर हम अपने नेबर वाली स्टेट पंजाब को लें तो उसमें हम से अधिक लाइन लौसिज हैं। यू0पी0, राजस्थान से भी हमारे कम हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी यह कौ ि ा ा है कि इससे

भी कम लाइन लौसिज हों। आगे चलकर चौधरी दल सिंह जी ने यह भी कहा कि बिजली बोर्ड के ऊपर 200 करोड़ रुपये का कर्जा है, उस पर इतना ब्याज देते हैं, इतना वह देते हैं। तो मैं यह कहता हूं कि कर्जा अगर है तो कर्जा कोई पाकिस्तान से लिया नहीं गया, अमेरिका से नहीं लिया गया, भारत सरकार से लिया है, लोगों से लिया है, हरियाणा सरकार से लिया है, या किसी फाइनैंि ायल इन्स्टीच्यू ान्ज से लिया हैं आज कोई भी फर्म अथवा कोई उद्योग धन्धे अगर कर्जा लेकर सैंट–परसैंट रूरल इलैक्ट्रीफिके ान किया, इसके बावजूद भी ये लोग नुक्ताचीनी करते हैं। मैं बिलकुल साफ बात कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हमने रूरल इलैक्ट्रीफिके ान किया, हमारा तकरीबन 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ और आज अगर हम इस तरह से देहातों में बिजली पहुंचाने का काम करें तो कम से कम 80–90 करोड़ रुपया से कम नहीं लगेगा। आज कल के महंगाई के जमाने में ऐसा करके हमने 40–45 करोड़ रुपये की बचत की है।

चौधरी चांद रामः यह महंगाई किसने बढ़ाई है ?

श्री बनारसी दास गुप्तः यह महंगाई किसी ने नहीं बढ़ाई है, हरियाणा सरकार ने नहीं बढ़ाई है, भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है, सारी दुनियां के अंदर महंगाई है। जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर सभी जगहों पर महंगाई है। इसकी जुम्मेवार न हरियाणा सरकार है, न भारत सरकार है।

तो उपाध्यक्ष महोदया, एक बात उन्होंने यह बतलाई कि हरियाणा बिजली बोर्ड का तो भट्ठा बैठ गया और यह घाटे के अन्दर जा रहा है और यह घाटा दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है। दल सिंह जी, बिजली बोर्ड आपकी जींद की अनाज मंडी की आढ़त की दुकान तो है नहीं (हंसी) जो इसमें मुनाफे की ही बात सोची जाये और ज्यादा से ज्यादा मुनाफाखोरी का लक्ष्य निर्धारित किया जाये। ऐसी यह संस्था नहीं है। यह बोर्ड लोगों को सुविधा देने के लिये हैं। आज एग्रीकल्चर को बिजली देने में नुक्सान होता है, यह बात साफ है लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर को बिजली देते हैं और न केवल देते ही हैं बल्कि देने में प्रायरिटी भी देते हैं और कई बार तो तमाम हरियाणा की इन्स्ट्रीज की बिजली बंद करके भी एग्रीकल्चर को बिजली देते हैं क्योंकि ऐसा किसान के हित में है, प्रदे ा के हित में है, और सारे दे ा के हित में है। इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा है जो हमने दूसरे प्रदे ाों को जो भी कमी वाले हैं उनको दिया है और –– (विघ्न) –– जरा भाान्ति से सुन लो। आप केवल कहना ही जानते हैं या सुनना भी जानते हैं ? मैं फैक्ट्स की बात कह रहा हूं और फिगर्ज़ दे कर बात कह रहा हूं .....

चौधरी ि ाव राम वर्मा: यह ठीक है कि कारखानों की तो बिजली बंद हो गई लेकिन खेती को फिर भी नहीं मिली ..... (विघ्न) .....

श्री बनारसी दास गुप्तः आप सबर से सुनते जायें मैं सब बातें बताऊंगा। तो उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह कह रहा था कि उन्होंने जो यह कहा कि बोर्ड घाटे में जा रहा है और रसातल में बैठ रहा है, यह बात बिल्कुल निराधार है, गलत है। वर्ल्ड बैंक का जो फारमूला है और सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट में जो फारमूला है उसके मुताबिक हमारे बिजली बोर्ड के खाता में 6.3 प्रति ात की रिटर्न है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के फारमूला के अनुसार है। इसके अलावा नफे और नुक्सान का ज्यादा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हमारा बोर्ड ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इक्विटी भोयर हों और डिवीडैंड के तौर से जैसे ज्वायंट स्टाक कम्पनीज़ बैलेंस– ाीट्स निकालती हैं वैसे इसमें नहीं निकालते हैं। लेकिन यह बात मैं कह सकता हूं कि घाटे वाली बात जैसे उन्होंने कहा इसमें नही है और जो उन्होंने कहा वह निराधार बात है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि आज से चार वर्श पूर्व जब सभी ग्रामों को बिजली पहुंचाई गई तब बोर्ड का केवल 40–45 करोड़ रुपये के लगभग खर्च हुआ था। आज अगर तमाम के तमाम देहात के अन्दर बिजली पहुंचाने की योजना बनाई जाये जो 80–90 करोड़ रुपये से भी काम नहीं चल सकता। यह तो रही रुपये की बात लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें कि आज यह हालत है कि पैसे से भी चीज नहीं मिल पा रही है चीजों की इतनी भाार्टेज है। उस वक्त मारकिट में हरियाणा बिजली बोडै ही परचेजर था लेकिन अब सारे दे ा के बिजली बोर्ड मारकिट में आ गये हैं

जिस की वजह से जितनी डिमांड है, उतना मैटीरियल नहीं मिल पा रहा है। आज अगर हम चाहें तब भी 80–90 करोड़ रुपये खर्च करके भी सारे हरियाणा के देहात में बिजली नहीं दे सकते थे, क्योंकि सामान ही अवेलेबल नहीं है। अगर आज सौ ट्यूबैवल्ज़ को भी बिजली देनी होती तो कन्डक्टर्ज़ ही नहीं मिलते, आर्डर पैंडिंग पड़े हुए हैं, मैनुफैक्चरर्ज़ के पास सामान की इतनी कमी है कि वह मिलता नहीं है और हम ट्यूबवैल्ज को बिजली नहीं दे सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों देहली में तमाम हिन्दुसतान के इरीग्रे ान एंड पावर मिनिस्टर्ज की कान्फ्रैंस हुई थी और उसमें मुझे तमाम प्रदे ाों के मन्त्रियों से मिलने का मौका मिला। उन सब ने मुझे बधाई दी और मुझ से कहा कि आपने भले वक्त में अपने प्रदे ा को इलैक्ट्रिफाई कर दिया, आज अगर ऐसा करना होता, तो उससे दुगुने रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा मटीरियल ही मार्किट में नहीं मिलता, जितना चाहिए। तो आप देखें कितना हरियाणा सरकार ने और इस बिजली बोर्ड ने प्रदे ा का फायदा किया, लेकिन इसके बावजूद भी नुक्ताचीनी ये भाई करते हैं। न सिर्फ हम ने ऐसा करके 40/45 करोड रुपया बचा लिया, बल्कि तीन–चार साल पहले बिजली दे देने से ट्यूबवैल्ज चले, उद्योग धन्धे चले और उन में उत्पादन हुआ। उस उत्पादन से जो लाभ हुआ, वह इस 40/45 करोड रुपए के लाभ से अलग है। अगर ऐसा न करते, तो तीन चार साल तक इस लाभ के महरूम रहते और अब जो दिक्कत आती, ज्यादा पैसा खर्च होता और पैसा खर्च

करने के बावजूद भी पूरा काम न कर पाते, यह दूसरा नुक्सान होता। तो मैं समझ नहीं पाया कि किस तरह की गलत पिक्चर पेंट करके कल सदन के सामने पे ा की गई, जो निराधार है, बेबुनियाद है। इसके अलावा एक बात और हमारे इन चौधरी साहब ने कही कि इस्माइलाबाद गांव में लाइन की री–एलाइनमैंट करने के ऊपर 60 रुपया खर्च हुआ ––(विघ्न)––

चौधरी दल सिंहः मैंने यह कहा था कि ऐसा करने में आठ लाख का नुक्सान रहा

श्री बनारसी दास गुप्तः 8 लाख 70 हजार का प्रोजैक्ट एस्टीमेट पर खर्च हुआ है, यह बात तो ठीक है। परन्तु नुक्सान का तो प्र न ही उत्पन्न नहीं होता। एक बात इन्होंने यह कही और बड़े जोर भाोर से कही कि बिजली बोर्ड ने डिफैक्टिव ट्रासफार्मर्ज़ लगाए हुए हैं और उनकी रिपेयर्ज़ पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यह बात भी बिल्कुल गलत है। उपाध्यक्ष महोदया, 1974–75 में ट्रांसफार्मर्ज़ की रिपेयर्ज़ पर कुल 21 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मैं एक और फैक्ट आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे बोर्ड ने ट्रांसफार्मर्ज़ की रिपेयर्ज़ के लिए इतनी अच्छी वर्क ाप लगाई हुई है, कारखाना लगाया हुआ है कि हम अपने आप सब रिपेयर्ज़ कर लेते हैं, बल्कि राजस्थान के बिजली बोर्ड ने हमें एप्रोच किया कि हमारे ट्रांसफार्मर्ज़ रिपेयर कर दो। तो आप देखें कि कितनी एफीि ाएंसी के साथ हमारा बिजली बोर्ड ट्रांसफार्मर्ज़ की रिपेयर का काम करता है। इसके अलावा एक बात जो चौधरी दल सिंह

जी ने कही वह बिलकुल ठीक है, कि हमारे प्रदे ा में बिजली की कमी है, कारखाने बंद पड़े रहते हैं और हजारों लाखों मजदूर बेकार हो जाते हैं। और ट्यूबवैल्ज़ को पूरी बिजली नहीं मिलती जितनी बिजली आज किसान चाहता है, उतनी बिजली हम किसान को नहीं दे पाते, यह सच्चाई की बात है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदया इसमे किस का दोश है ? सारा दोश हरियाणा सरकार का या हरियाणा बिजली बोर्ड का हो, ऐसी बात नहीं है, आप जानते हैं कि पिछले तीन साल में हरियाणा के अन्दर बारि ा नहीं हुई और हरियाणा में ही नहीं, बल्कि सारे दे ा में ही इन तीन सालों में सूखा रहा है और इस साल बदकिस्मती से एक बात और अधिक हुई कि न सिर्फ मैदानों में बारि ा नहीं हुई, बल्कि पहाड़ों पर भी बारि ा नहीं हुई और गोबिन्द सागर का जो कैचमैंट एरिया है, उसमें बहुत कम बारि ा हुई, जिसके नतीजे के तौर पर आज गोबिन्द सागम में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले में 105 फीट नीचे हैं। आप यह भी जानते हैं कि आज हरियाणा में बिजली प्राप्त करने का जो सब से बड़ा सोर्स है, वह भाखड़ा है और हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पावर है ––(विघ्न)–– आप समझिए इस बात को पिछले साल इन्हीं दिनों हमें भाखड़ा से 33 लाख यूनिट्स बिजली प्रति दिन मिलती थी, जो आज केवल 14 लाख यूनिट्स मिल रही है। इस तरह आप देखें 19 लाख यूनिट्स प्रति दिन का भाखड़ा से बिजली प्राप्त करने में घाटा हमें रहता है। इस घाटे का सामना तो करना ही पड़ेगा। यह जो संकट है, यह दैवी प्रकोप है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदया,

आज जानती हैं और दूसरे भाई भी जानते हैं कि 8/10 साल पहले जब कहत पड़ते थे तो इसलिए पड़ते थे कि बारि ा नहीं होती थी और उस समय न बिजली का साधन होता था और न नहर का पानी ही होता था। उस वक्त क्या हालत होती थी ? उस वक्त लोग भूखे रहते, न अनाज मिलता और न प ाुओं के लिए चारा मिलता और खेतों में प ाुओं के हड्डियों के ढेर नजर आते थे। तो जब दैवी प्रकोप होता है और कुदरत नाराज़ होती है, तो मुि कल का सामना करना ही पड़ता है। आज बिजली के संकट का जो सबसे बड़ा कारण है, वह है बारि ाों का अभाव। आज कल हमें 75 लाख यूनिट्स बिजली प्रतिदिन चाहिए, लेकिन आजकल हमें मिलती है, केवल कभी 25 लाख और कभी 30 लाख और ज्यादा से ज्यादा अगर जोर मारते हैं तो चालीस लाख यूनिट्स मिल जाती है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डोमैस्टिक कन्ज़म्प ान कामि ायल और असैंि ायल इंडस्ट्रियल कन्ज़म्प ान के लिए हमें बीस लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन चाहिए और इन तीनों को हम बन्द नहीं कर सकते। बाकी कभी, 5 लाख कभी दस लाख और कभी बीस लाख यूनिट्स बचती है और इसमें हम ट्यूबवैल्ज़ को चलाने के लिए प्राथमिकता देते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब हमारे पास बिजली की अत्यन्त कमी थी, तो व्हीट का सोइंग सीजन का गया। व्हीट हमारी मुख्य फसल है, इसलिए उसकी ज्यादा से ज्यादा बिजाई करनी थी। तो हमने आठ दिन तक हरियाणा के समस्त कारखानों के लिए बिजली बन्द कर दी और इसलिए कर दी ताकि हमारी गेहूं की बिजाई पूरी हो

जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे पास उन दिनों बड़े–बड़े उद्योगपतियों के देहली से टैलीफोन आए और मेरे पास सुरजपुर की सीमेंट फैक्ट्री के मालिक आए, और उन्होंने कहा कि सीमुंट असैंि ायल कमोडिटी है, इसलिए सीमेंट बनाने के लिए बिजली दो। मैंने उनको जवाब दिया कि ठीक है, सीमेंट बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि सीमेंट ज्यादा जरूरी है या रोटी ज्यादा जरूरी है।

हमने अनाज को बढ़ाने के लिए, कृशि उत्पादन के लिए बिजली देनी है, इंडस्ट्रीज के लिए बिजली देनी है, क्योंकि यहां मजदूरों को काम मिलना है, लेकिन इंडस्ट्रीज को बिजली देने का काम नम्बर दो पर रखा गया है, नम्बर वन एग्रीकल्चर को दिया है। हमारे यहां डोमैस्टिक कन्ज़म्प ान बिजली की 6.2 है, कमि र्ायल 13.3 है, इंडस्ट्रीज 49.6 है, एग्रीकल्चर 37.6 है और दूसरे कामों पर 3.4 है। एग्रीकल्चर पर खपत 37.6 है, जो हिन्दुस्तान के अन्दर हाइएस्ट है, कृशि क्षेत्र में इतनी खपत सारे हिन्दुस्तान में नहीं है, जितनी हरियाणा स्टेंट के अन्दर है। कई भाई पूछेंगे कि अगर आपके पास बिजली की इतनी भारी कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए आपने अब तक क्यों प्रबन्ध नहीं किया ? यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदया, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, कि जिस वक्त हरियाणा प्रदे ा बना था, तो उस वक्त हम लोग तो कहीं पिक्चर में नहीं थे। चौधरी दल सिंह और उनके बड़े बड़े नेता थे, और जब

विभाजन होने लगा, तो हमें पंजाब की निस्बत कम बिजली अलाट हुई। बिजली कौमन पूल में जाने के बाद, नंगल फर्टीलाइजर फैक्ट्री में जाने के बाद जो बिजली बचती थी, वह हरियाणा और पंजाब में तकसीम हुई। तकसीम करने से पंजाब को 60.5 मिली और हमको 39.5 मिली। उपाध्यक्ष महोदया, आपको पता होगा कि भाखड़ा के पानी के अन्दर हमारा भोयर पंजाब से ज्यादा है, तो क्या वजह है कि हमें बिजली कम मिली ? इसलिए कम मिली कि हम बिजली खपा नहीं सकते हैं, तो क्या वजह है कि हमें बिजलील कम मिली ? इसलिए कम मिली कि हम बिजली खपा नहीं सकते थे, हमारे पास बिजली के कन्जम्प ान के साधन नहीं थे। हमारी खपत और कन्जम्प ान को देखते हुए हमें बिजली कम मिली। अगर चौधरी दल सिंह और उन के नेता इस बात को ध्यान रखते, बिजली की लाईनें लगतो, फैलाव करते, तो हजारा कन्जम्प ान ज्यादा होता और हमे ाा के लिए भाखड़ा में हमारा बिजली का भोयर ज्यादा होता। इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसा हुआ है। उपाध्यक्ष महोंदय जब से हमारे मुख्य मंत्री ने सरकार की बागडोर अपने हाथ में ली है, बिजली का फैलाव ज्यादा किया है। एक वक्त ऐसा था, जब भाखड़ा से बिजली मिलती थी, तो उसको कन्ज्यूम नहीं कर सकते थे और हालत यह थी कि जो बिजली ज्यादा क्न्जयूम करता था, हम उसको इंसैंटिव देते थे, ज्यादा बिजली खर्च करने वाले को कम पैसे देने पड़ते थे और कम बिजली खर्च करने वाले को ज्यादा टैरिफ रेट देना पड़ता था क्योंकि कन्ज्यूम करने के साधन हमारे पास नहीं थे। हम यह

साधन पैदा करते गए। बिजली पैदा करने के साधन भी जुटाए और खर्च करने के साधन भी जुटाए। हमने सन 1968 के अन्दर ही फरीदाबाद में थर्मल प्लांट लगाने के लिए म ाीनरी का आर्डर–प्लेस कर दिया, क्योंकि हमने यह महसूस कर लिया था कि सबसे पहले बिजली की कमी जरूरत महसूस होगी। इस थर्मल प्लांट के निर्माण का कार्य 1971 में भाुरू कर दिया। तीन साल के अन्दर हमने फरीदाबाद का एक यूनिट बनाकर तैयार कर दिया जो आज ट्रायल बेसिज़ पर चल रहा है। हिन्दुस्तान में यह रिकार्ड टाईम है कि तीन साल में यह थर्मल प्लांट बन कर तैयार हो गया, इतने थोड़े अर्से में किसी प्रांत में नहीं बना .....

चौधरी दल सिंहः भठिण्डा का बना है।

श्री बनारसी दास गुप्तः भटिण्डा थर्मल प्लांट का काम हमसे पहले भाुरू हुआ था। चौधरी दल सिंह कह रहे थे कि मैंने जाकर फरीदाबाद प्लांट का उद्घाटन किया है, मैंने उद्घाटन नहीं किया है। अगर मैं इनकी बात को झूठ कहूं, तो अनपार्लियामैंट्री भाब्द हो जाएगा। लेकिन है यह सफेद झूठ, यह बिल्कुल गलत बात कही। उन्होंनें कि उसका उद्घाटन किया है, आज तक उसका उद्घाटन किसी ने भी नहीं किया है। न मैंने किया है और न किसी और ने किया है। इन्होंने यह कहा कि उससे एक भी यूनिट बिजली आज तक नहीं मिली। मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि डेढ़ से दो लाख यूनिट तक उससे बिजली पैदा हो चुकी है। जब थर्मल प्लांट चलता है, तो उसमें खराबियों भी हो

जाया करती हैं। भटिण्डा थर्मल प्लांट बहुत पहले चालू हुआ था, लेकिन खराब हो गया और अब बन्द है। कई खराबियां हो जाती हैं, क्योंकि थर्मल प्लांट के अन्दर म ाीनरी का बहुत भारी फैलाव होता है, कभी किसी चीज में डिफैक्ट हो जाता है, कभी किसी चीज में हो जाता है। हमारा एक थर्मल प्लांट फरीदाबाद में लग चुका है, जिसकी प्रोडक ान जनवरी में भाुरू हो जाएगी। आप देखें इसके अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, फरीदाबाद में हम एक और थर्मल प्लांट लगाने जा रहे हैं। 60 मैगावाट का लग चुका है और 60 मैगावाट का और लगाया जाएगा। इसी साल दिसम्बर, 1975 तक यह दूसरा थर्मल प्लांट आ जाएगा, जिससे 60 मैगावाट बिजली मिलने लगेगी। इसके और भी इन्तजाम कर रहे हैं, उसी जगह फरीदाबाद में ही तीसरा यूनिट लगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सैंन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमी ान को ऐप्लाई कर दिया है स्वीकृति के लिए अनुमति के लिए ताकि हम काम भाुरू कर सकें। जैसा कि चौधरी दल सिंह ने कहा कि आए साल पानीपत थर्मल प्लांट की बात दोहरा देते हैं, यह ठीक बात है दोहराते हैं, क्योंकि पानीपत में दो यूनिट 110—110 मैगावाट के लगाने हैं। लेकिन हमने यह बात कभी नहीं कही कि 77—78 से पहले प्रोडक ान आ जाएगी। एक यूनिट प्रोडक ान में सन 1977—78 में आने की आ ाा है और दूसरा प्रोडक ान में आएगा एक साल के बाद यानी 1978—79 में। यह हम कभी नहीं कहते हैं कि 1975—76 में आ जाएगा। इसमें कुछ कार्य आरम्भ हो चुका है, म ाीनरी के लिए आर्डर दिए जा चुके

हैं, 3 करोड़ रुपया इन–एडवांस दे दिया है। हमें पूरी आ ाा है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उस समय तक पानीपत में थर्मल प्लांट लगाने में कामयाब हो जाएंगे। पानीपत के अन्दर एक सैकेण्ड यूनिट लगाने का भी प्रोग्राम है लेकिन यह यूनिट छठी पंचवशीय योजना में कायम होगा, इससे पहले काम नहीं हो सकता। इस तरह बिजली का प्रबन्ध थर्मल प्लांट लगाकर कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त वैस्टर्न जमना नहर पर 45 मैगावाट का एक यूनिट लगाने की स्कीम है, जिससे हाईड्रो–इलैक्ट्रिक पैदा होगी। वहां पर जो नैचुरल फाल है, उस पर यह यूनिट लगाया जाएगा। यह सी0डब्ल्यू0पी0सी0 के पास मंजूरी के लिए गया है, मंजूरी आने के बाद भाुरू किया जाएगा। हम यहां पर ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हमारे आफिसर इस प्रयत्न में हैं कि बिजली की जो कमी हो रही है, उसको किस प्रकार पूरा किया जाए। हम यह जानते हैं कि तमाम दुनियां के अंदर बिजली एक ऐसी भाक्ति है, जिसके सहारे से दे ा प्रगति कर सकता है, बिजली से ही कृशि की पैदावार बढ़ सकती है, बिजली से ही उद्याग धन्धे प्रगति कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर हो सकती है और कई दूसरे साधन जुटाए जा सकते हैं। ब्यास और रावी का काम चल रहा है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि डेढ़ साल में यह काम पूरा हो जाएगा। इस प्रोजैक्ट से हमें पानी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी। पहला यूनिट बिहार का है, जिससे हमें 211 मैगावाट यूनिट बिजली मिलेगी, दूसरा पौंग डैम का है जिससे 40 मैगावाट मिलेगी। 1976–77 के अंदर इन दोनों यूनिटों सें बिजली मिलनी भाुरू हो

जाएगी और हमें लाभ होगा। इनके अतिरिक्त एक प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदे ा में चल रहा है–– सिडल हाईड्रो–इलैक्ट्रिक परियोजना। इस प्रोजैक्ट में हमारा भोयर है जिससे 40 मैगावाट बिजली मिलेगी और 1978–79 में इस प्राजैक्ट से हमें लाभ होना आरम्भ हो जाएगा। इसके अलिावा जम्मू क मीर में सैंन्ट्रल स्कीम के अन्दर सलाल का हाईड्रो–इलैक्ट्रिक प्राजैक्ट है, इस पर अभी काम भाुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब इस में बिजली का उत्पादन भाुरू होगा, तो 50 मैगावाट बिजली हरियाणा को मिलेगी। इतना काम करने के काद भी हम खामो ा नहीं बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, हमारा यह विचार है योजना है कि हम किसी बड़े प्रोजैक्ट के अंदर भोयर होल्डर बनें और किसी ऐसी स्टेट के साथ मिलकर अपने प्रांत के लिए बिजली पैदा करें जिससे हमारी कमी दूर हो पाए।

कल हमारे विपक्षी दल के भाई बोल रहे थे कि फलां प्रदे ा में बिजली पैदा करने की क्षमता इतनी है और फलां प्रदे ा में इतनी है, जबकि हरियाणा में यह क्षमता नहीं है। यह ठीक बात है। मैं मानता हूं कि हरियाणा में बिजली पैदा करने की क्षमता ज्यादा नहीं है। यहां तो एक 25 मैगावाट का थर्मल प्लांट फरीदाबाद में है और एक 6.8 मैगावाट का सूरजपुर में है। इसके अलावा अभी हाल ही में 60 मैगावाट का एक और थर्मल प्लांट फरीदाबाद में हमने लगाया है और एक सेसा ही बिजलीघर कुछ महीने प चात् भाुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पानीपत

में प्रत्येक 110 मैगावाट के दो बिजलीघरों के निर्माण कों मुकम्मल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके अलावा हम और क्या कर रहे हैं यह भी मैं आपको बताता हूं। हमारे पड़ौस में हिमाचल प्रदे ा है। उसमें हाइड्रो–इलैक्ट्रिसिटी के बड़े पोटैंि ायल हैं, वहां बड़ी गुंजाइ ा है और अनेक प्रकार के उनके यहां प्रोजैक्ट हैं, जहां हजारों मैगावाट बिजली पैदा हो सकती है। पिछले दिनों हमारे आफिसर्ज की एक टीम ि ामला गई और उनके अधिकारियों के साथ नाथवा झाकरी प्राजैक्ट के सम्बन्ध में उन्होंने बात की। उसमें एक हजार मैगावाट बिजली पैदा हो सकती हैं इस प्रोजैक्ट में भोयरहोल्डर बनने के लिए हमारे अधिकारियों ने उनके अधिकारियों के साथ बातचीत की। मैंने स्वयं भी उनके एक मंत्री के साथ दिल्ली में बैठकर बातचीत की। कुछ टमर्ज़ के अंदर, उपाध्यक्ष महोदया, हम भोयर होल्डर बन गए तो मैं समझता हूं कि अगले बीस साल तक के लिए हरियाणा की बिजली की समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी। इतने पर भी हम चुप नहीं बैठे हैं। हम और भी प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे जो इरीगे ान ऐंड पावर के कमी नर हैं, उनकों पिछले दिनों हमने मध्यप्रदे ा भेजा। उन्होंने मध्यप्रदे ा सरकार से बातचीज की कि तुम्हारे यहां जो कोल पिट्स हैं, सतपुड़ा के उन पर हम थर्मल प्लांटस लगाएं ताकि कोयला लाने की दिक्कत न रहे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप तो जानती हैं कि विरोधी दल का सारे हिन्दुस्तान में क्या रोल है। एक तरफ तो ये कमी की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ कमी को दूर करने वाले काम में रूकावट

पैदा करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने रेलवे की हड़ताल करवाई। उसका क्या परिणाम हुआ ? कोयला नहीं पहुंचा। कोयला न पहुंचने से कारखाने नहीं चले, थर्मल प्लांटस नहीं चले और थर्मल प्लांटस ने चलने से बिजली पैदा नहीं हुई। जब बिजली पैदा नहीं हुई, तो किसान को बिजली नहीं मिली, उसक ट्यूबवैल्ज़ नहीं चले और अनाज की पैदावार घटी। तो एक तरफ तो ये कमी की ि ाकायत करते हैं लेकिन दूसर तरफ पैदावार के रास्ते में रूकावट पैदा करने की कोि ा ा करते हैं और भांति–भांति के नारे लगाते हैं। पिछले दिनौं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता है हरियाणा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भड़का कर इन्होंने हड़ताल करवा दी। आज अगर वे फिर हड़ताल कर दें तो आप ही बताएं कि बिजली कैसे आएगी ? जब बिजली नहीं आएगी तो किसान के ट्यूबवैल्ज़ कैसे चलेंगे ? जब बिजलल नहीं आएगी तो किसान के ट्यूबवैल्ज कैसे चलेंगै ? जब ट्यूबवैल्ज नहीं चलेंगे तो कृशि की पैदावार नहीं बढ़ेगी तो ये फिर चीखेंगे कि भूखे मर गए या भूखा मार दिया। इसकी नीति क्या है, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि भारत सरकार की यह पालिसी है कि थर्मल प्लांट ज्यादा कोल पिट्स जहां है, कोल माइन्ज़ जहां हैं, वहीं पर लगाए जाएं। इसके लिए हमारे इरीगे ान ऐंड पावर कमि नर मध्य प्रदे ा के साथ हमारा यह ऐग्रीमैंट हो जाता है तो एक फायदा यह होगा कि ट्रांसमी ानल लाईन्ज के ऊपर हमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान से बातचीत करके भाखड़ा में राजस्थान का जो

हिस्सा है, उसे हम ले लेंगे और सतपुड़ा में, जो बिजली हमारे हिस्से की पैदा होगी उसमें से भाखड़ा वाले हिस्से के बदले में मध्य प्रदे ा को दे देंगे।

उपाध्यक्षाः गुप्ता साहब, आप कितना टाईम और लेंगे ?

श्री बनारसी दास गुप्तः पांच–सात मिनट और बोल लेता हूं।

इसके अलावा आपको पता है, उपाध्यक्ष महोदया, कि पिछले दिनों हमने एटोमिक ऐनर्जी प्लांट के लिए बड़ी भारी कोि ा ा की। एक साईट सिलैक ान कमेटी यहां आई। उसके चेयरमैन ने ताजेवाला के पास ही जगह सिलैक्ट कर ली थी लेकिन बदकिस्मती से वह फैसला हमारे हम में नहीं हुआ। अब वह एटोमिक एनर्जी प्लांट उत्तर प्रदे ा में नरोरा के स्थान पर लगने जा रहा है। हम फिर भी चुप नहीं बैठे हैं। अब पांचवें एटोमिक ऐनर्जी स्टे ान की बातचीत चल रही हैं उसके लिए हर भारत सरकार के पीछे लगे हुए हैं, ताकि उसे वह हरियाणा के अंदर लगाने का किसी प्रकार से फैसला करे। ये सब हमारी योजनाएं हैं, जो बिल्कुल डैफिनिट हैं, नि चत हैं। हम योजनाबद्ध काम करते हुए जा रहे हैं। होच–पौच डिवैल्पमैंट की बात आज हरियाणा में नहीं है। यहां तो योजनाबद्ध विकास की बात है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी दल सिंह जी ने कृशि पैदावार ने आंकड़े भी दिए। चौधरी दल सिंह जी आय साल उन्हीं

आंकड़ों को देते हैं। वही इनकी किताब है और पैदावार के वही इनके आंकड़े हैं।

चौधरी दल सिंहः किताब आपकी है, मेरी नहीं।

श्री बनारसी दास गुप्तः ठीक है, किताब हमारी है। हम इसे ओन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदया, आज एक बात मैं बतलाना चाहता हूं। हमारे सदन के नेता ने, मुख्य मंत्री जी ने भी एक बार इनके आंकड़ों का उत्तर दिया था। एक साल 1967–68, के अंदर एकदम हमारी प्रोडक ान बढ़ गई थी। हमारे यहां कई बार ऐसा होता है, उपाध्यक्ष महोदया, कि अगर बे ाुमार बारि ा हो जाए, भगवान अगर खु ा हो जाए तो चना बहुत मिकदार में पैदा हो जाता है। आपको याद होगा, मेरे कई बुजुर्ग भाई भी यहां बैठै हैं, भाायद उनको भी याद होगा और मुझे तो अच्छी प्रकार याद है कि नब्बे के साल में इतनी भारी वर्शा हुई थी, कि तमाम हरियाणा प्रदे ा के अंदर बड़ा भारी चना पैदा हुआ कि लोग खेतों से उसे निकाल नहीं पाए। कई जगह तो वह खेतों में ही कुड़ गया। लेने वाला भी कोई नहीं था। कहते हैं कि एक रुपये का एक मन चना बिका था। कई बार ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदया सन् 1967–68 में भगवान खु ा हुआ बारि ा अच्छी हुई और चने की फसल एकदम बढ़ गई। चौधरी दल सिंह जी भाायद यही फिगर 37,70,000 टन उत्पादन ही बतलाते हैं। उपाध्यक्ष महोदया,

इस फिगर को तो ये बार–बार कोट कर देते हैं लेकिन एक और बात को ये नहीं बताते जिसे कि मैं बतलाना चाहता हूं। वह बात यह है कि उस साल खरीफ की पैदावार 9,59,000 टनी थी और रबी की फसल 30,11,000 टन उत्पादन की बतलाते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, इस फिगर को तो ये बार–बार कोट कर देते हैं लेकिन एक और बात को ये नहीं बताते जिसे कि मैं बतलाना चाहता हूं। वह बात यह है कि उस साल खरीफ की पैदावार 9,59,000 टन थी और रबी की फसल 30,11,000 टन थी। चना रबी में बोया जाता है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, उस दफा बारि ा ज्यादा पड़ने और भगवान के खु ा हो जाने के कारण चूंकि चना ज्यादा पैदा हो गया इसलिए यह फिगर बढ़ी जिसको ये आये दफा कोट कर देते हैं। अगर इसके आगे की पोजि ान आप देखें तो उपाध्यक्ष महोदया, सही तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। सन् 68–69 के अंदर पैदावार हुई 2754000 टन क्योंकि बारि ा ज्यादा नहीं हुई। उसके बाद सन् 69–70 में पैदावार 4626000 टन हुई क्योंकि बारि ा कुछ अच्छी हो गई। एक दम 19 लाख टन पैदावार बढ़ गई। 70–71 में 4771000 टन पैदावार हुई लेकिन 71–72 में 4543000 टन हुई। कुछ कम हो गई क्योंकि बारि ा कम हो गई होगी। फिर 1972–73 में सूखा साल है। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदया, पुराने आदमी जो हैं, वे कहते हैं कि इतना भयानक सूखा अकाल उन्होंने कभी नहीं देखा लेकिन फिर भी पैदावार 4042000 टन हुई। एक बात और डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बताना चाहता हूं। वह बड़ी ध्यान देने की बात है। जहां तक रबी फसल

का सवाल हैह, उसमें मुख्य फसल गेहूं की होती है। अब मैं गेहूं के आंकड़े आपको बताता हूं। 67–68 में 1438000 टन हुआ था। 68–69 में 1529000 टन हुआ, 69–70 में 2147000 टन हुआ, 70–71 में 2342000 टन हुआ, 71–72 में 2402000 टन हुआ और 72–73 में 2233000 टन हुआ। तो डिप्टी स्पीकर साहिब आप देखेंगे कि 1967–68 में हमारे यहां जहां 1400000टन गेहूं पैदा होता था, वहां आज 2400000 टन गेहूं पैदा होता है। दस लाख टन की पैदावार बढ़ी है। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदया, हमारी महत्त्वपूर्ण फसल है राईस। हमें इस बात का गर्व है कि पिछले साल चावल हमने मिडल ईस्ट कन्टरीज को ऐक्सपोर्ट किया है क्योंकि अरब राश्ट्रों ने हरियाणा की बासमती को, हरियाणा के चावल को पसन्द किया और उसे खरीदा। 67–68 में इसकी पैदावार 287000 टन थी, उसके बाद 272000 टन हो गई, उसके बाद 372000 टन हो गई और आज है 536000 टन। (**इस समय अध्यक्ष महोदया पदासीन हुए**) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि किस प्रकार पैदावार हमारे प्रदे ा में बढ़ती रही है।

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं नहरों के पानी की बात बतला दूं। कल एक बात चौधरी दल सिंह जी कह रहे थे कि नहरें जहां निकाली हैं, वह वे जानते हैं। जिस तरफ इनका ई ाारा था, वह यह है कि जिला महेन्द्रगढ़ और जिला भिवानी के सूखे इलाकों में हमने नहरें निकाली हैं। चौधरी चांद राम ने भी और चौधरी दल सिंह जी ने भी एक बात यह कही कि इनका फायदा

क्या हुआ ? फायदा क्या हुआ, वह मैं जानता हूं क्योंकि वह मेरा इलाका हैं सन् 52 में एक भयानक कहत पड़ गया था। मारवाड़ी रिलीफ सोसाईटी कलकता से अकाल पीड़ितों की सहायता का काम करने के लिए यहां आई। हम जब गांव के अन्दर जाते थे तो हालत देखकर आंखों के अंदर आंसू आ जाते थे। खेतों के अंदर प ाुओं के पिंजरों के ढेर लगे होते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी प ाु, एक भी इन्सान हरियाणा के अन्दर भूख से नहीं मरा। वह इसलिए कि हमने कम से कम एक फसल का पानी दिया उन सूखे इलाकों को, जिससे वे चारा तथा खाने के लायक अन्न पैदा कर लेते हैं और मौज से अपने दिन काट लेते हैं। फिर अध्यक्ष महोदय, यह बात भी गलत है कि हमने इनके यहां का पानी काटकर उधर दिया है। यह तो वह पानी है जो बाढ़ के दिनों में जाया करता था, जिससे फसलें तबाह हो जाती थीं और गांव के गांव डूब जाते थे। उन इलाकों को बाढ़ के पानी की तबाही से बचाया हैं उस बाढ़ के पानी को बचाकर रेगिस्तान के इलाके में पहुंचाया है जो प्यास से मरता था, भूख से मरता था उनको इससे रोटी और चारा मिलता है।

18.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि सदन के नेता ने भी बोलना है। बहुत समय मैंने सदन का लिया है। असल तस्वीर डिवैल्पमैंट की, विकास की, पानी की और बिजली की लीडर आफ दी हाउस बताएंगें। फिग्र्ज़ तो मेरे पास भी

और काफी थीं, लेकिन लीडर आफ दी हाउस ने बोलना है इसलिए मैंने आपकी इजाजत से सारी बातें सदन के सामने रखीं और इस उद्दे य से रखीं कि वे सही तस्वीर से वाकिफ हो जाएं।

चौधरी दल सिंहः आन ए प्वांयट आफ पर्सनल एक्सप्लेने ान सर।

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, गुप्ता जी ने बार–बार पचासों दफा मेरा नाम अपनी स्पीच में लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा वहीं हूबहू गुप्ता जी ने माना है। फिर उन्होंने कह दिया कि गांवों की तादादप बढ़ी है –– (विघ्न) ––

Mr. Speaker: Order please. This is not a personal explanation.

चौधरी दल सिंहः उन्होंने अल्जाम लगाया है। तो स्पीकर साहब यह ज्यादती है ––(विघ्न)–– मैंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक हैं

Mr. Speaker: Anything about your person ?

चौधरी दल सिंहः पर्सन की बात कहता हूं। इन्होंने कहा कि सन् 1968 के अंदर हमने इलैक ान में हरा दिया। तो मैं यह कहता हूं ––(विघ्न)–– कि आपकी सारी सरकार उसी हल्के से

कई इलैक ानों में मेरे खिलाफ थी और फिर भी आप की हार हुई।

श्री बनारसी दास गुप्तः मैंने यह नहीं कहा। आप रिकार्ड देख सकते हैं। मैंने तो यह कहा है कि लोगों ने हरा दिया।

Mr. Speaker: Order please. No second speech please. The Hon. Chief Minister.

मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर सदन में दो रोज से विचार हो रहा है। मुझ से पहले बोलने वाले साथियों ने बहुत सी चीजों पर प्रका ा डाला है और इरीगे ान ऐंड पावर मिनिस्टर श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने तो बहुत ही बातें कवर कर ली हैं। इसलिए मैं हाउस का ज्यादा टाईम नहीं लूँगा। जहां तक हमारी प्रान्त की डिवैल्पमैंट का सवाल है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि डिवैल्पमैंट का पेस हमारे प्रान्त का हिन्दुस्तान के हर प्रान्त से ज्यादा है। आज मैं यह मानता हूं कि पिछले तीन साल पहले या दो साल पहले जिस तेजी के साथ हमारी तरक्की हो रही थी, उतनी तेजी के साथ तरक्की नहीं हो रही। इसका स्पीकर साहब एक कारण है। जिस समय हमने पूरे हरियाणा प्रांत को इलैक्ट्रिफाई किया, उस वक्त मार्कीट में चीजों को खरीदने के लिए बिजली की तार या खम्भे कोई भी चीज खरीदने के लिए हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्यादा था, बाकी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड या बाकी सरकार कम थी। हमको जो चीज उस समय मिली, उस

समय उसके भाव भी ठीक थे। उस समय टोटल इलैक्ट्रिफिके ान के ऊपर 44 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और आज अगर उतना ही हम काम करें, तो मैं समझता हूं कि 20–25 या तीस करोड़ रुपया ज्यादा खर्च आएगा। अब जब सवाल आता है कि हमने इलैक्ट्रिफिके ान ज्यादा कर दी, ज्यादा गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, मैं फिर्ग्ज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहूंगा। सरकार के पास आज जो आमतौर पर ि ाकायत आती है, वह आती है कि बिजली की भाार्टेज़ है। ि ाकायत यह आती है कि ट्यूबवैल्ज़ को बिजली नहीं मिलती, इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली नहीं मिलती। इसका क्या करें ? मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे पास बिजली की कमी है और उस बिजली की कमी को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम थर्मल प्लांट लगाएं और कोई दूसरा तरीका है नहीं। स्पीकर साहब, आने वाले जमाने के अंदर अगले दो साल के अंदर–अंदर डहर का जो सलापड़ जगह कहलाती है, ब्यास का प्रोजैकट चालू होते ही हमें डहर से बिजली मिलने लगेगी। भाखड़ा से जो बिजली मिलती है, वह फर्म हो जाएगी। हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने साठ मैगावाट का एक थर्मल प्लांट अभी फरीदाबाद में चालू किया है। वह फुल प्रोडक ान पर कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है अगले कुछ महीनों के बाद एक और थर्मल प्लांट साठ मैगावाट का फरीदाबाद में आ जाएगा इसी तरह से 110–110 मैगावाट के दो थर्मल प्लांट हम पानीपत में लगाने जा रहे हैं और उनमें से एक ही हमें उम्मीद है कि दो अढ़ाई साल में आ जाएगा। लेकिन आज पैसे की कमी सरकार के पास

है, सैंट्रल गवर्नमैंट के पास है क्रेडिट सैक्वीज़ भी है। पैसे की कमी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास भी है और हमारे पास भी है। पैसा हमारे रास्ते में एक रूकावट है। स्पीकर साहब, हमारे माननीय सदस्यगण जो हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने सरकार की नुक्ताचीनी की और नुक्ताचीनी करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नुक्ताचीनी न करें, तो हो सकता है, हम ज्यादा गलती कर जाएं। मैं तो यह चाहता हूं कि वे हमारी नुक्ताचीनी बराबद करते रहें ताकि हम कोई गलत काम आगे न करें। अगर मेरे भाई जो मैरे सामने बैठे हैं, वे चार्ज ाीट न देते, तो मैं इतना सम्भल कर न चलता, जितना आज चल रहा हूं। तो इन्होंने मेरा भला किया है, मेरा नुक्सान नहीं किया। मैं इनका बहुत अहसानमन्द हूं।

चौधरी दल सिंहः एक और चार्ज ाीट दे दें ?

चौधरी बंसी लालः और ज्यादा दे देंगे और ज्यादा अहसानमन्द हूंगा। तो स्पीकार साहब जब काम ज्यादा तेजी से होता है तो उसमें कोई कमी भी रह जाती है, कोई काम सब–स्टैण्डर्ड भी हो सकता है, लेकिन देखने की बात यह है कि काम करने वाले की नीयत क्या थी ? हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी कि सारे हरियाणा के एक–एक गांवों को इलैक्ट्रिफाई करना बगैर इस बात की तमीज के कि अपोजी ान पार्टी के किसी मैंबर का हलका है या कांग्रेस पार्टी के मैंबर का हलक है। हमने सब जगह बिजली पहुंचाई। अब अगर कोई यह कहे कि गांवों में सब जगह बिजली नहीं लगी तो चण्डीगढ़ जो कस्बा है, भाहर है, सिटी

है यह स्पीकर साहब सबसे ज्यादा माडर्न भाहर है और मेरी इन्फर्मे ान के मुताबिक 17 परसैंट घरों में चण्डीगढ़ में बिजली नहीं है। तो यह हमारा कसूर नहीं है। तो पावर जनरे ान का जितना हम प्रबन्ध कर सकते हैं, हम कर रहे हैं और अगले दो–अढ़ाई साल के बाद हरियाणा प्रान्त में पावर की भाार्टेज नहीं रहेगी। हम इतना प्रबन्ध करने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारे किसानों और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पूरी पावर मिलेगी ––(तालियां) ––

जहां तक अनाज की पैदावार का सवाल है, वह बनारसी दास जी ने सदन को आंकड़े बताए। जो आंकड़े हमारे विरोधी भाई दे देते हैं, वह चने की वजह से दे दे देते हैं, वरना आज एवरेज़ ईल्ड पर हैक्टेयर बढ़ी है। सन् 1968–69 में 850 के0जी0 थी, बढ़िया से बढ़िया साल था। सन् 1972–73 में 970 के0जी0 थी। भाूगर केन, काटन, आयल सीड्स में ऐसा है कि भाूगरकेन सन् 1967–68 में हमारे प्रान्त में चार लाख 75 हजार टन पैदा हुई थी। 1973–74 में यह बढ़कर पांच लाख 96 हजार टन हो गई। काटन सन् 1967–68 में दो लाख 68 हजार गांठे थी और 1973–74 में यह बढ़कर चार लाख 50 हजार गांठें हो गई।

इसी तरह स्पीकर साहब ट्यूबवैल्ज़ की संख्या के ऊपर चौधरी दल सिंह जी और चौधरी चांद राम जी इरीगे ान ऐंड पावर मिनिस्टर की फिग्र्ज़ को चैलेन्ज़ कर रहे थे। मैं उनकी इनफर्मे ान के लिए आपके जरिए बताना चाहता हूं कि सन्

1967–68 में आंकड़े थे, ट्यूबवैल्ज़ पंपिंग सैट्स और वैल्ज़ तीनों मिलाकर 25797 और सन् 1969–70 में इनकी तादाद हो गई एक लाख 44 हजार 636। आज ट्यूबवैल्ज पंपिंग सैटस और वैल्ज़ तीनों को मिलाकर इनकी तादाद हो गई है 2 लाख 2 हजार 109। अब इन फिग्र्ज़ को चैलेन्ज करें। मैं यह एथैनटिक फिग्र्ज़ बता रहा हूं। गुप्ता जी ने आपको बताई पंपिंग सैट्स और ट्यूबवैन्ज़ की, मैंने जो कुएं बने हैं, जिनमें न बिजली है, न पंपिंग सैट्स हैं, वे भाामिल करके बताए हैं।

चौधरी चांद रामः पैदावार तो नहीं बढ़ी।

चौधरी बंसी लालः पैदावार बढ़ी है। यह कोई नहीं कह सकता कि पैदावार नहीं बढ़ी। पैदावार के मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, पैदावार बढ़ी है, मैंने आपसे प्रार्थना की कि सन् 1968–69 का जो आप ऊंचे से ऊंचा साल समझते हैं, उसमें 887 के0जी0 पर हैक्टेयर पैदावार थी और सन् 1973–74 में यह 970 के0जी हो गई। बहुत फर्क पड़ा है।

इसी तरह से हाई ईल्डिंग वैराइटी का जो सीड फार्म था, स्पीकार साहब, वह टैन फोल्ड बढ़ गया। 1967–68 में इसकी खपत थी 86 हजार क्विंटल और 1973–74 में यह बढ़कर हो गया 14 लाख हैक्टयेर। फर्टीलाईज़र की कन्जम्प ान 1966–67 में थी 66 हजार 700 टन और 1973–74 में यह हो गई 5 लाख 80 हजार टन। पर हैक्टेयर यूज़ आफ फर्टीलाइजर 1966–67 में

स्पीकर साहब 18 के0जी0 पर–हैक्टेयर था और 1973–74 में यह हो गया 155 के0जी पर–हैक्टेयर। इसी तरह से हमारी ऐग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान भी अच्छा काम कर रही है। जीटर ट्रैक्टर 4277 उन्होंने नीलोखेड़ी में इस कार्पोरे ान ने असैम्बल किए और एक मार्डन कैटल फीड प्लांट जींद में लगाया है एक करोड़ रुपए की लागत से अभी चालू हुआ है जिससे प ाुओं को खिलाने में और दूध बढ़ाने में हमको फायदा होगा और हरियाणा ऐग्रीकल्चर माकीर्टिंग बोर्ड जो है, उसने नई मण्ड़या भी बनाई हैं और नई मण्डियां आगे बनाते भी जा रहे हैं। इस वक्त जो मण्ड़ियां बन रही हैं, वे हैं भाहजादपुर, ढांड, मतलोडा, जुंडला, नसंग, होडल, हसनपुर, फरुखनगर, सोहना, खरखोदा, कलानौर, सांपला, जुई, बहल, पालसमन्द और जींद। तो वह काम भी हम करते जा रहे हैं। लैंड रिक्लेमे ान के काम की बात गुप्ता जी ने बताई। हम लैंड रिक्लेमे ान का काम भी तेजी से कर रहे हैं। इसी तरह से स्पीकर साहब, ऐनीमल हैस्बन्डरी में हम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। बहुत सी चीजों की डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि गुप्ता जी ने बहुत सी बातें खोलकर आपको बताई हैं। को–आप्रेटिव सोसाइटीज़ की तादाद 30 जून 1968 को 12550 थी और वर्किंग कैपिटल था 66 करोड़ 37 लाख। मैंबरि ाप थी 9 लाख 57 हजार। और 30 जून 1974 को कोओप्रेटिज़ की संख्या है 13898। वर्किंग कैपिटल 66 करोड़ 37 लाख की बजाए 253 करोड़ 47 लाख हो गया और मैंबरि ाप 14 लाख 19 हजार हो गई। इसी तरह से स्पीकर साहब, जो अमाउंट प्राइमरी को–आप्रेटिव

एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ ने एडवांस किया है, 1967–68 में 2 करोड़ 21 लाख, 1973–74 में 9 करोड, 26 लाख। मार्कीटिंग फैडरे ान ने जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हैंडल किया। 1967–68 में 56 लाख था और 1973–74 में यह 20 लाख 30 हजार क्विंटल गन्ना पीड़ा, जबकि 1973–74 में यह 38 लाख 42 हजार क्विंटल गन्ना पीड़ा। 1967–68 में एक लाख 78 हजार क्विंटल चीनी पैदा हुई। दोनों मिलों में जबकि 1973–74 में यह बढ़कर 3 लाख 27 हजार क्विंटल हो गई। तो स्पीकर साहब, इसी तहर से डेयरी डिवैल्पमैंट में, हमारे पास एग्रीकल्चर के बाद, दूसरे नम्बर पर एनीमल हस्बैंडरी डेयरी डिवैल्पमैंट का ही काम है। इससे ही हमारे दे ा की हमारे प्रान्त की खु ाहाली हो सकती है। इमने जींद, भिवानी और अम्बाला में तीन बड़े बड़े प्लांट अब तब लगा दिए हैं। उनकी कैपेसिटी बढ़ायी भी जा सकती है। अगले दो प्लांट एक फरीदाबाद और एक रोहतक में, अन्डर कन्स्ट्रक ान हैं और कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। हम अपनी स्कीम के मुताबिक बैंकों से लोन दिलवाते हैं, लैंडलैस फार्मर्ज़ को या लैंडलैस गरीब हरिजन को ताकि उनको भैंसों का कर्जा मिल जाए। उससे व दूध भी पी सकें, बच्चों को भी पिला सकें। साथ की साथ उसको बेचर गुजारा भी कर सकें। यह काम हम पूरे प्रांत में बड़ी तेजी से फैला रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि प्रांत में कोई आदमी बगैर भैंस के न रहे। एक एक गांव, जो ज्यादा से ज्यादा इंटीरियर में है, उसका दूध भी मिल्क प्लांट तक पहुंचा देंगे। इसके बाद स्पीकर साहब, बिजली पर जो बात चल रही है, बिजली

के बारे में मैंने भी जवाब दे दिया है और इरीगे ान ऐंड पावर मिनिस्टर ने भी जवाब दे दिया, लाइन लासिज के बारे में, मैं हाज़िर नहीं था, भाायद इरीगे ान ऐंड पावर मिनिस्टर ने बताया हो। हमारा जो लाइन लाग है, वह है 21.60 प्रति ात यानी 22 प्रति ात से कम और आन्ध्र प्रदे ा में लास है 25.20 प्रति ात, बिहार में यह है 31.23 प्रति ात, पंजाब में यह है 24.71 प्रति ात, राजस्थान में यह है 25.7 प्रति ात, यू0पी0 में यह है 26.14 प्रति ात। यानी कोई प्रान्त इनमें से ऐसा नहीं, जिसके लाइन लॉसिज हम से कम हों। हमारे लाइन लासिज बराबर घटते आए हैं। 1972–73 में हमारे थे 23.30, 1973–74 में हमारे थे 22.3, 1974–75 में यह 31 नवम्बर 1974 तक की फिग्र्ज़ हैं, 21.80। तो मैं यह समझता हूं कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लाइन लासिज़ घटाने की अच्छी कोि ा ा की है। लेकिन जहां लाईनें इतनी लम्बी–लम्बी इंटीरियर तक जाती हों, लम्बी लाईनें हों, तो लाइन लासिज़ का होना कोई अजीब बात नहीं है और लाइन लासिज़ को बहुत ज्यादा घटा भी नहीं सकते ––(व्यवधान)––

चौधरी चांद रामः यह भी तो बता दो कि कितना खर्च करने के बाद यह लाइन लासिज़ कम हुआ है।

चौधरी बंसी लालः अगर लाईन लासिज़ कम करेंगे तो खर्च तो होगा ही। मुफ्त में तो स्पीकर साहब, कोई भी काम नहीं होगा। स्पीकार साहब, इसी तरह से एम्पलायमैंट में भी during the period January, 1974, 82, 874 were registered and 9085

placed in gainful employment. The placement is 11% as against All India average of 8.4 percent for the same period. एक्साइज़ एंड टैंक्से ान में हमारी इनकम बराबर बढ़ती जा रही है। 1968–69 में हमारी ऐक्साइज़ ऐंड टेक्से ान में इनकम थी 26 करोड़ 58 लाख, 1969–70 में यह हो गई 28 करोड़ 41 लाख, 1970–71 में यह हो गई 34 करोड़ 15 लाख, 1971–72 में यह हो गई 40 करोड़ 34 लाख, 1972–73 में यह हो गई 48 करोड़ 65 लाख, 1973–74 में यह हो गई 60 करोड़ 80 लाख, 1974–75 में एप्रौक्सीमेटली 70 करोड़। यानी 26½ करोड़ से चलकर 70 करोड़ पर हम पिछले 6 साल में पहुंच गए हैं। और इस सैल्ज़ टैक्स से हमने हलवाई ऐग्जैम्पट कर रखे हैं Cotton seed when purchased by a registered dealer exempted from payment of tax और दुकानदारों को भी हमने यह रियायत दे रखी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो या कोई खास सीरियस किस्म का कोई टैक्स इवेज़न न हो, तब तक हम किसी के यहां छापा नहीं मारते, किसी का कोई बही–खाता वगैरह चैक नहीं करते।

फूड ऐंड सप्लाईज़ का काम भी हमारा बड़ा तसल्लीबख्भा है। फारैस्ट हमारे पास बिल्कुल न होते हुए भी हमारे फारैस्ट का काम भी बिल्कुल तसल्लीबख्भा है। हैल्थ के बारे में स्पीकर साहब, हमने कई अस्पताल बनाए हैं और कई अस्पताल अब भी बन रहे हैं। जो अस्पताल इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बन रहे हैं, वे हैं भिवानी, कुरुक्षेत्र, गुड़गांवा और जींद। सब–डिवीजनल लेवल पर जो बन रहे हैं वे हैं – कैथल,

यमुनानगर, नरवाना और रिवाड़ी। प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज़—सीवन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट और मुडलाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, और बड़ागुढ़ा हिसार डिस्ट्रिक्ट और कुराली गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, ये अन्डर कन्स्ट्रक ान हैं। और स्पीकर साहब, हमारे भाुरू में फोर्थ प्लान में पर—कैपिता दवाई पर जो एक्सपैंडीचर था, वह 21 पैसे थे, और फोर्थ प्लान के ऐंड में यह 82 पैसा पर—कैपिटा हो गया। This is the highest per.capita expenditure on medicine in the country हाउसिंग में स्पीकर साहब, हाउसिंग बोर्ड ने पांच सौ घर एक बनाए, और आठ सौ, साढ़े आठ सो एक बनाए। इस वक्त तक टोटल 1314 हाउस बना चुके हैं और उम्मीद है कि 1974—75 में 31 मार्च 1975 से पहले पहले 200 घर और बना देंगें। हाउसिंग बोर्ड का काम खाता कामैन्उेबल है। इंडस्ट्रीज में भी हमारा काम बहुत अच्छा रहा है। बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज लगी हैं। इंडस्ट्रियल कनैक ान बहुत ज्यादा दिए गए हैं लेकिन अब हमारी बदकिस्मती है कि इंडस्ट्रीज पर बड़ा भारी कट है क्योंकि हमको ट्यूबवैल्ज़ के ऊपर चलाना पड़ता है। अगले दो—ढ़ाई साल तक हमें यह तकलीफ रहेगी अगर भगवान बारि ा कर दे तो हमारी यह तकलीफ जल्दी भी दूर हो सकती है, लेकिन बारि ा न होने की भाक्ल में दो—ढ़ाई साल के बाद जब ढहर से बिजली मिलने लगेगी, हमारा फरीदाबाद का दूसरा प्लांट आ जाएगा और भाखड़ा फर्म हो जाएगा, उसके बाद बिजली की दिक्कत इंडस्ट्री के लिए नहीं रहेगी जितनी कि आज है। इरीगे ान में स्पीकर साहब, चौधरी दल सिंह ने थोड़ी देर पहले ही कहा कि इरीगे ान बढ़ाई,

यह किया वह किया। इरीगे ान ऐसा है कि एक्चुअल इरीगेटिड एरिया और सी0सी0ए0 1966–67 में था। 57 लाख 12 हजार एकड़ और एक्चुअल इरीगेटिड था उस वक्त 32 लाख 75 हजार एकड़ और 1973–74 में सी0सी0ए0 हो गया। 65 लाख 84 हजार एकड़ और ऐक्चुअल इरीगे ान हो गई। 40 लाख 88 हजार एकड़ आढैर हमने लाइनें जो हैं लैंथ आफ कैनाल्ज़ इन हरियाणा 1967–68 में इनकी लम्बाई थी 5666 माइल और 1973–74 में 6337 माइल और हमने पिछले छः, सात साल में 3125 क्यूसिक पानी किसानों और बढ़ाया है। आगमैंट ान ट्यूबवैल्ज़ से, नहरों को पक्का करके, उसके सीपेज़ के लास को कम करके इससे हमने 3125 क्यूसिक पानी लोगों के लिए ज्यादा बढ़ाया है और हमने कई नहरें पक्की भी की हैं। उनके बारे मैं भाायद इरीगे ान ऐंड पावर मिनिस्टर ने नहीं बताया। आगमैंटे ान कैनाल, पटवार डिस्ट्रीब्यूटरी, दिल्ली पैरेलल, हांसी ब्रांच, लाइनिंग आफ दिल्ली ब्रांच, लाइनिंग आफ दिल्ली टेल डिस्ट्रीक्यूटरी, लाइनिंग भलोट ब्रांच, लाइनिंग भुटाना ब्रांच, लाइनिंग सुन्दर सब ब्रांच इनसे हमको 520 क्यूसिक पानी भी बचा और इनकी अलाइनिंग भी हुई। और ड्रेन नम्बर आठ जो है, उसकी हमने लिफ्ट इरीगे ान स्कीम बनाकर तीन जगह उसका पानी इस्तेमाल किया है। इसको पूरा हाउस जानता है। और डेज़र्ट एरियाज में स्पीकार साहब, हमने जो किया किया है, उसका करना जरूरी था। अगर डेज़र्ट एरियाज में हम यह काम नहीं करते, तो वह बाकी प्रांत के ऊपर भार बनकर रहते। आज क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर उस इलाके का है, आज

क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि इरीगे ान ऐंड पावर मिनिस्टर उस इलाके का है ––(व्यवधान)–– इस समय स्पीकर साहब, ड्राउट अफैक्टिड एरियाज में नहर कैनाल और दूसरी कैनाल्ज के ऊपर और सड़कों के ऊपर तकरीबन 20 हजार आदमियौं को रोजाना काम दे रखा है ड्राउट अफैक्टिड एरियाज में और वाटर कोर्सिज जिनमें पानी के लासिज ज्यादा होते हैं।

चौधरी चांद रामः यह भी बता दो कि वह आदमी कहां के हैं ? हरियाणा के उनमें कितने हैं।

चौधरी बंसी लालः हमने यह स्ट्रिक्ट हिदायत दे रखी है कि सिर्फ हरियाणा के आदमियों को ही लगाओ। अगर किसी ने गलत एड्रैस देकर हरियाणा का लिखाकर काम ले लिया हो तो मैं नहीं कह सकता। वरना हमारी स्ट्रिक्ट हिदायतें हैं कि आज के हालत में जब हमारे यहां ड्राउट कंडी ान्ज़ हैं, तो सिर्फ हरियाणा के आदमी को ही काम दिया जाए। बाकायदा लिखित हिदायतें जारी की हुई हैं ––(व्यवधान)–– आप जाकर देख आओ कि हरियाणा के हैं। आपक जाकर उनके एड्रैस देख आओ। और अगर कोई पड़ौस का कोई गरीब भाई भी कमाकर खा जाए तो क्या बुरी बात है। स्पीकर साहब जहां तक सड़कों का सवाल है, 1 नवम्बकर 1966 को जब हरियाणा बना तो 5100 किलोमीटर सड़कें थीं और 1366 गांवों को कनैक्ट करती थी, आज नवम्बर 1973 में सड़कों की तादाद हो गई है 14 हजार 70 किलोमीटर और 4258 गांवों तक सड़क पहुंच गई हैं। यानि मौजूदा सरकार के आने के

बाद 2872 गांवों को सड़कें दी गई हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 पब्लिक हैल्थ ने करीब 700 गांव को पानी दिया है और 745 गांव को 31 मार्च तक हम पानी दे पाएंगे और जब हरियाणा प्रांत बना तो सिर्फ 170 गांवों को पीने का पानी दिया हुआ था। ट्रांसपोर्ट का स्पीकर साहब, हमारा कम्पलीट नै ानेलाइजे ान हो चुका है और 31 मार्च 1974 तक हमारा फ्लीट करीब 1850 का हो जाएगा और पैसेन्जर्ज़ को जितनी फैसिलिटीज देनी चाहिए, उतनी हम दे रहे हैं। चौधरी राम लाल ने अपनी तकरीर में या किसी सवाल में जिक्र किया था कि पैसेन्जर्ज़ को फैसिलिटीज कितनी दे रहे हैं। प्राइवेट औप्रेटर्ज, चौधरी राम लाल जो देते थे, उससे कई गुणा ज्यादा फैसिलिटीज हम दे रहे हैं और टूरिज्म में किसी एक सज्जन ने यह कहा था कि इसमें नुक्सान हो रहा है। नुक्सान नहीं हो रहा है। टुरिज्म में हम लाखों रुपया कमा रहे हैं। बिल्कुल भी नुक्सावन नहीं उठा रहे हैं। टाउन ऐंड कन्ट्री प्लांनिंग का जो डिपार्टमैंट है, उसने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम करता जा रहा है और अर्बन ऐस्टेट बनाते जा रहे हैं फरीदाबादी, गुड़गांवा, सोनीपत, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, जींद, भााहबाद, पंचकूला, भिवानी, अम्बाला, करनाल, ये न्यू ए एस्टेट्स हम कुरूक्षेत्र, पानीपत, लाडवा, रिवाड़ी वगैरह यह हम सब करते जा रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने अच्छा खासा खर्च किया है और इसके साथ साथ महकमें ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पीकर साहब, मेरे साथी जो मेरे सामने बैठे हैं चाहे वह कितनी ही बुराई करें, अपने भीतर से वह यह समझते हैं कि काम हुआ है और काम होता रहना चाहिए। लेकिन इनका

जो क्रिटीसिज्म है, उसकी मैं तारीफ करता हूं, क्रिटिसिज्म करें यह बहुत अच्छी बात है और जो जवाब मैंने नहीं दिए, इनकी स्पीच में जो जो बातें आईं, जो जो कमियां हैं, उन कमियौं को दूर करने की पूरी कोि ा ा करेंगे और अपोजी ान बैंचिज़ दोनों मिलकर आगे बढाएं, इसकी तरक्की करें। हमारी यही नीयत होगी। हम अपोजी ान से कोई बात कभी कभी छिपाकर नहीं रखना चाहते। इन भाब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि गवर्नर साहब को यह मो ान आफ थैंक्स भेज दिया जाए।

Mr. Speaker: Now I will put the amendments to the vote of the House. The first amendment is by Chaudhri Dal Singh.

Chaudhri Dal Singh: I withdraw my amendment.

Mr. Speaker: Is it the pleasure of the House that the amendment be withdrawn ?

Voices : Yes.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Speaker: The second amendment is by Chaudhri Ram Lal and Chaudhri Shiv Ram Verma.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: I also withdraw my amendment.

Mr. Speaker: Is it the pleasure of the House that the amendment be withdrawn ?

Voices: Yes.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is-

"That the members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 1st January, 1975."

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjounred till 9.30 a.m. tomorrow.

18.28 बजे

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. tomorro, the 8th January, 1975.)